



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 26, 1973 (ज्येष्ठ 5, 1895)

No. 21]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 26, 1973 (JYAISTHA 5, 1895)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस

(NOTICE)

नीच लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 2 फरवरी 1973 तक प्रकाशित किये गये हैं :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 2nd February 1973 :—

अंक Issue	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
--------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------

—शून्य—
—Nil—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां निर्यत्नक प्रकाशन, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी।
मांग-पत्र निर्यत्नक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिए।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Controller of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Controller within ten days of the date of issue of these *Gazettes*.

विषय-सूची		पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	501	
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	819	
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	—	
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	586	
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—	
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें	—	
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	979	
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं		1809
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश		155
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं		825
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस		227
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं		25
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं		1551
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस		95
पूरक संख्या 21—		
19 मई, 1973 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महीनारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट		653
28 अप्रैल, 1973 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े		669

CONTENTS

PAGE	PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	PAGE
501	PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	155
819	PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	825
—	PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	227
586	PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	25
—	PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1551
—	PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	95
979	SUPPLEMENT No. 21 Weekly Epidemiological Reports for week ending 19th May, 1973	653
	Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 28th April, 1973	669

PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	501
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	819
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	586
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)	979

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 मई 1973

सं० आर० एस० 18/73-टी०—आसाम राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सभा के एक निर्वाचित सदस्य, श्री महेंद्र मोहन चौधरी ने 4 मई, 1973 से राज्य सभा में अपना स्थान त्याग दिया है।

बी० एन० बनर्जी, सचिव

26. श्री अवधेश चन्द्र सिंह
27. श्री आर० के० सिन्हा
28. श्री कमल नाथ तिवारी
29. श्री एम० जी० उद्दे
30. श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव

गौतम देव शर्मा, उप-सचिव

लोक सभा सचिवालय

(प्राक्कलन समिति शाखा-एफ)

नई दिल्ली-1, दिनांक 9 मई, 1973

सं० 3/1/ई० सी० एक/73—लोक सभा के निम्नलिखित सदस्य 30 अप्रैल, 1974 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं :—

1. श्री आर० एन० बर्मन
2. श्री राजगोपाल राव बोदपल्ली
3. श्री स्वामी ब्रह्मानन्द
4. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा
5. श्री भाउ साहिब धामनकर
6. श्री गिरिधर गोमांगो
7. श्री डी० बी० चन्द्र गौडा
8. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर
9. श्री हरी सिंह
10. श्री एम० एम० जोजफ
11. श्री तुलसीराम दशरथ कांवले
12. हाजी लुत्फल हक
13. श्री नागेश्वर राव मेबुरी
14. श्री प्रसन्नभाई मेहता
15. श्री मोहम्मद ताहिर
16. श्री सुरेन्द्र महन्ती
17. श्रीमती शकुन्तला नायर
18. श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे
19. श्री अनन्त राव पाटिल
20. श्री भारखण्डे राय
21. श्री पी० गंगा रेड्डी
22. श्री चौधरी लाधू राम
23. श्री इब्राहीम सुलेमान सेट
24. श्री पी० ए० सामिनाथन्
25. श्री पी० रंगानाथ शिनाय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 26 मई, 1973

सं० 15/1/73-अ० भा० से० (1)—ऐसे निर्मुक्त आपातकालीन आयुक्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारियों के लिए, जिन्होंने 1 नवम्बर, 1962 के बाद किन्तु 10 जनवरी, 1968 से पूर्व सशस्त्र सेनाओं में कमीशन प्राप्त कर लिया हो अथवा 10 जनवरी, 1968 से पहले कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित हुए हों परन्तु उन्हें उस तारीख को या उसके बाद कमीशन प्रदान किया गया हो, निम्नलिखित सेवाओं में, आरक्षित रिक्तियों को चयन द्वारा भरने के लिए 1972 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली सम्मिलित प्रतियोगी परीक्षा के नियम, सम्बन्धित मंत्रालयों की सहमति से तथा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सहमति से, भारतीय प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम, 1954 और भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 7 क और निर्मुक्त आपातकालीन आयुक्त अधिकारी तथा अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारी (रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1971 के नियम 5 में दिये गये उपबन्धों के अनुसरण में आम जानकारी के लिए प्रकाशित किये जा रहे हैं। उपरोक्त उपबन्ध 29 जनवरी, 1974 के बाद लागू नहीं रहेंगे यदि इनकी अवधि सरकार द्वारा बढ़ा नहीं दी जाती।

- (i) भारतीय प्रशासन सेवा,
- (ii) भारतीय विदेश सेवा,
- (iii) भारतीय पुलिस सेवा,
- (iv) केन्द्रीय सूचना सेवा (ग्रेड II) श्रेणी 1,
- (v) भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा,
- (vi) भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा,
- (vii) भारतीय रक्षा लेखा सेवा,
- (viii) भारतीय आय-कर सेवा (श्रेणी 1),

- (ix) भारतीय आडिनेन्स फैक्टरी सेवा, श्रेणी-1
(सहायक प्रबन्धक—गैर-तकनीकी),
- (x) भारतीय डाक सेवा,
- (xi) भारतीय रेलवे लेखा सेवा,
- (xii) सैनिक भूमि (मिलिटरी लेण्ड्स) और छावनी सेवा,
श्रेणी - 1,
- (xiii) भारतीय रेलवे यातायात सेवा,
- (xiv) दिल्ली, तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह
पुलिस सेवा श्रेणी II,
- (xv) केन्द्रीय सचिवालय सेवा अनुभाग अधिकारी ग्रेड,
श्रेणी II,
- (xvi) सीमा शुल्क मूल्य निरूपक (एग्जेजर) सेवा श्रेणी II,
- (xvii) दिल्ली तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल
सेवा श्रेणी-II,
- (xviii) भारतीय विदेश सेवा शाखा (ख) सामान्य संवर्ग के
एकीकृत ग्रेड II तथा III, श्रेणी II (अनुभाग अधिकारी
ग्रेड),
- (xix) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा, श्रेणी-II,
- (xx) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा, सहायक सिविल-
लियन स्टाफ अधिकारी ग्रेड, श्रेणी II,
- (xxi) सैनिक भूमि (मिलिटरी लेण्ड्स) और छावनी सेवा
श्रेणी II,
- (xxii) गोआ, दमन व दियु सिविल सेवा, श्रेणी II तथा
- (xxiii) पांडिचेरी सिविल सेवा, श्रेणी II,

उम्मीदवार उपर्युक्त सेवाओं में से किसी एक अथवा एक से अधिक सेवाओं के लिए परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन कर सकता है। जिन सेवाओं के बारे में वह चाहता है कि उस पर विचार किया जाए उनका उल्लेख वह अपने आवेदन पत्र में कर दे। उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि किसी भी ऐसी सेवा में उनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार नहीं किया जाएगा जिसका उल्लेख वे अपने आवेदन पत्र में नहीं करेंगे।

ध्यान दें : (1) उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आवेदन पत्रों में उन सेवाओं के अधिमान क्रम का स्पष्ट उल्लेख करें जिनके लिए वे प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के इच्छुक हैं। उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे अपनी इच्छानुसार जितनी सेवाओं का चाहें उल्लेख करें जिससे कि नियुक्तियां करते समय, योग्यता क्रम में उनके स्थान को दृष्टि में रखते हुए, उनके अधिमानों का भी समुचित ध्यान रखा जा सके।

- (2) उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन पत्र में मूलतः उल्लिखित सेवाओं में किसी अन्य सेवा का नाम जोड़ते अथवा उनके वरीयता क्रम में कोई परिवर्तन करने से सम्बन्धित किसी ऐसे अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा जो इस परीक्षा के अंतिम

परिणाम घोषित होने के 10 दिन के अन्दर मंत्रिमण्डल सचिवालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) में प्राप्त नहीं हो जाता।

परीक्षा के लिखित भाग के परिणामों के आधार पर भारतीय प्रशासन सेवा/भारतीय पुलिस सेवा की मौखिक परीक्षा के लिए सफल हो जाने वाले उम्मीदवार से मंत्रिमण्डल सचिवालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) अलग से इस बात के लिए कहेगा कि वह उस विभाग को उन विभिन्न राज्यों के वरीयता क्रम की सूचना दे जिनमें वह अपना आवंटन चाहता है।

2. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित पद आरक्षित रखे जाएंगे।

अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों से अभिप्राय निम्नांकित में उल्लिखित जातियों/आदिम जातियों में से किसी एक से है; बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के साथ पठित अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (भाग 'ग' राज्य) आदेश, 1951, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) आदेश, 1950 और संविधान अनुसूचित आदिम जाति (भाग 'ग' राज्य) आदेश, 1951 संविधान (जम्मू और काश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1959 संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962 और संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964 तथा संविधान (अनुसूचित आदिम जातियों) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान (गोआ दमन व दियु) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968 और संविधान (नागा-लैण्ड) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970।

3. संघ लोक सेवा आयोग यह परीक्षा नियमों के परिशिष्ट II में निर्धारित विधि से लेगा।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

4. इन नियमों में की गई व्यवस्थाओं के अनुसार निम्न-लिखित वर्गों के वे आपातकालीन आयुक्त तथा अल्पकालीन आयुक्त अधिकारी जिन्होंने 1 नवम्बर, 1962 के बाद, परन्तु 10 जनवरी, 1968 से पहले सशस्त्र सेनाओं में कमीशन प्राप्त कर लिया हो अथवा 10 जनवरी, 1968 से पहले कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित हुए हों, परन्तु जिन्हें उस तारीख को या उसके बाद कमीशन प्रदान किया गया हो इस परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।

- (i) जो अधिकारी इस अधिसूचना की तारीख से पहले 1973 के दौरान निर्मुक्त हुए हों अथवा उसके बाद 1974 के अन्त तक निर्मुक्त होने वाले हों,
- (ii) नियम 9 की व्यवस्थाओं के अनुसार उक्त नियम में उल्लिखित अधिकारी

नोट 1 :—इन नियमों के प्रयोजनार्थ “निर्मुक्त” का अर्थ है :—

- (1) निर्मुक्त होने के नियत वर्ष के अनुसार निर्मुक्त;
- (2) सैनिक सेवा में विकलांगता के कारण अशक्तता।

किन्तु यह निर्मुक्ति, सेवा के दौरान अथवा प्रशिक्षण के अंत अथवा उसके दौरान या वास्तविक सेवा में लिए जाने में पूर्व प्रशिक्षण की अवधि को पूरा करने के लिए प्रदत्त अल्प सेवा कमीशन के अन्त में नहीं होनी चाहिए। कदाचार या अक्षमता या अपने ही अनुरोध पर निर्मुक्त हुए अधिकारियों के मामले इसके अधीन नहीं आते।

नोट 2 :—“निर्मुक्त होने के नियत वर्ष” का अर्थ है :—

- (i) जहाँ तक इसका सम्बन्ध आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों से है, उनके लिए वह वर्ष जिसमें वे रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पूर्व बद्ध कार्यक्रम के अनुसार निर्मुक्त होने हों; तथा
- (ii) जहाँ तक अल्पकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों का सम्बन्ध है उनके लिए वह वर्ष जिसमें अल्पकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों के रूप में सामान्य सेवाकाल की समाप्ति होनी है।

नोट 3 :—यदि प्रार्थना-पत्र भेजने के पश्चात्, किसी व्यक्ति को सेना में स्थायी कमीशन मिल जाए या वह सेना से त्याग-पत्र दे दे, या कदाचार, अक्षमता के कारण या अपने ही निजी अनुरोध पर वह निर्मुक्त हो जाए, तो परीक्षा के लिए उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

नोट 4 :—जो इन्जीनियर तथा डाक्टर केन्द्रीय सरकार में या राज्य सरकारों में या सरकार के स्वामित्व में चलने वाले औद्योगिक संस्थानों में कार्य करते हैं और जिनको अनिवार्य दायिता योजना के अन्तर्गत सशस्त्र सेना में न्यूनतम निर्धारित अवधि के लिए सेवा करनी पड़ती है और जिनकी संगत नियमों के अन्तर्गत इस प्रकार की सेवा अवधि में अल्पकालीन सेवा कमीशन प्रदान किया जाता है, वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे।

नोट 5 :—सशस्त्र सेना की स्वयं सेवक आरक्षी सेवा (वालंटियर रिजर्वफोर्स) से सम्बद्ध अधिकारी, जिन्हें अस्थायी सेवा पर बुलाया गया हो, वे इस परीक्षा में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।

5. (1) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक अवश्य होना चाहिए।

(2) अन्य गेवाओं के लिए उम्मीदवार को या तो—

- (क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या
- (ख) सिक्किम की प्रजा, या
- (ग) नेपाल की प्रजा, या
- (घ) भूटान की प्रजा, या

(ङ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(च) मूल रूप से भारतीय व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका (पहले सीलोन के नाम से विख्यात) और पूर्वी अफ्रीका में कीनिया, उगांडा, टेंजानिया, संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीवार) से आया हो।

परन्तु अगर की (ग), (घ), (ङ) तथा (च) कोटियों के अन्तर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा दिया गया पात्रता (एलिजिविलीटी) प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

एक और शर्त भी है कि उपर्युक्त (ग), (घ) और (ङ) कोटियों के उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जाएंगे।

परीक्षा में उस उम्मीदवार को भी बैठने दिया जा सकता है जिसके लिए पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो और उसे सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र दिये जाने की शर्त के साथ अन्तिम (प्राविजनल) रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है।

6. (क) उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक है कि उसकी आयु, उस वर्ष 1 अगस्त, को जिसमें वह सशस्त्र सेना में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित हुआ हो (जहाँ केवल कमीशन परवर्ती प्रशिक्षण हो) या उसने कमीशन प्राप्त किया हो, 24 वर्ष नहीं होनी चाहिए।

यह व्यवस्था की जाती है कि निम्नलिखित नियम 10 (ख) के अधीन इस परीक्षा में बैठने के हेतु प्रार्थना-पत्र भेजने वाले उम्मीदवार को उपर्युक्त तारीख को निम्नलिखित आयु का नहीं होना चाहिए :—

(1) जिस वर्ष किसी व्यक्ति ने कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश लिया हो या कमीशन प्राप्त किया हो (जहाँ केवल कमीशन के बाद प्रशिक्षण हो) उस वर्ष सेना में सम्मिलित होने से यदि उसके अध्ययन में व्यवधान न पड़ जाता, तो वह निम्नांकित नियम 10(क) में विहित योग्यता की परीक्षा में बैठने का पात्र होता। इन के मामले में 24 वर्ष।

(2) जिस वर्ष किसी व्यक्ति ने कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश लिया हो या कमीशन प्राप्त किया हो (जहाँ केवल कमीशन के बाद प्रशिक्षण हो) सेना में सम्मिलित होने से यदि उनके अध्ययन में व्यवधान न पड़ जाता, तो वह अगले वर्ष निम्नांकित नियम 10(क) में विहित योग्यता की परीक्षा में बैठने का पात्र होता इन के मामले में 23 वर्ष।

- (3) जिस वर्ष किसी व्यक्ति ने कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश लिया हो या कमीशन प्राप्त किया हो (जहां केवल कमीशन के बाद प्रशिक्षण हो), सेना में सम्मिलित होने से यदि उसके अध्ययन में व्यवधान न पड़ जाता, तो वह उससे दूसरे वर्ष निम्नांकित नियम 10(क) में विहित योग्यता की किसी परीक्षा में बैठने का पात्र होता। इनके मामले में 22 वर्ष।
- (4) जिस वर्ष किसी व्यक्ति ने कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश लिया हो या कमीशन प्राप्त किया हो (जहां केवल कमीशन के बाद प्रशिक्षण हो), सेना में सम्मिलित होने से यदि उसके अध्ययन में व्यवधान न पड़ जाता, तो वह उससे तीसरे वर्ष निम्नांकित नियम 10(क) में विहित योग्यता की किसी परीक्षा में बैठने का पात्र होता। इनके मामलों में 20 वर्ष।
- (5) जिस वर्ष किसी व्यक्ति ने कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश लिया हो या कमीशन प्राप्त किया हो (जहां केवल कमीशन के बाद प्रशिक्षण हो), सेना में सम्मिलित होने से यदि उसके अध्ययन में व्यवधान न पड़ जाता, तो वह उससे चौथे वर्ष निम्नांकित नियम 10(क) में विहित योग्यता की किसी परीक्षा में बैठने का पात्र होता। इनके मामलों में 20 वर्ष।
- (6) जिस वर्ष किसी व्यक्ति ने कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश लिया हो या कमीशन प्राप्त किया हो, सेना में सम्मिलित होने से यदि उसके अध्ययन में व्यवधान न पड़ जाता, तो वह उससे पांचवें वर्ष निम्नांकित नियम 10(क) में विहित योग्यता की किसी परीक्षा में बैठने का पात्र होता। इनके मामले में 19 वर्ष।
- (ख) ऊपर निर्धारित आयु सीमा में छूट दी जा सकती है:—
- (1) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष,
- (2) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद परन्तु 25 मार्च, 1971 से पहले भारत में आया वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष।
- (3) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और वह 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद परन्तु 25 मार्च, 1971 से पहले भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आया वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष।
- (4) यदि उम्मीदवार संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी का निवासी हो तथा उसने कभी न कभी फ्रांसीसी माध्यम से शिक्षा प्राप्त की हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष।
- (5) यदि उम्मीदवार अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद, श्रीलंका (पहले सिलोन के नाम से विख्यात) से वास्तव में प्रत्यावर्तित होकर, भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष।
- (6) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और साथ ही अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन, 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका (पहले सिलोन के नाम से विख्यात) से वास्तव में प्रत्यावर्तित होकर, भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष।
- (7) यदि उम्मीदवार गोआ, दमन और दियु के संघ राज्य क्षेत्र का निवासी हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष।
- (8) यदि उम्मीदवार कीन्या, उगांडा, या टंजानिया संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टैंगानिका तथा जंजीबार) से आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष।
- (9) यदि उम्मीदवार 1 जून, 1963 को या उसके बाद बर्मा से वास्तव में प्रत्यावर्तित होकर, भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष।
- (10) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और साथ ही 1 जून, 1963 को या उसके बाद, बर्मा से प्रत्यावर्तित होकर, भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक 8 वर्ष।
- (11) रक्षा सेनाओं के उन विक्लांग कर्मचारियों के मामलों में अधिक से अधिक 3 वर्ष तक जो किसी शत्रु देश से अथवा उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में हुए संघर्ष के दौरान विक्लांग हुए तथा उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त किए गए।
- (12) रक्षा सेनाओं के ऐसे विक्लांग कर्मचारियों में अधिक से अधिक 8 वर्ष जो कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के हैं तथा जो किसी शत्रु देश से अथवा उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में हुए संघर्ष के दौरान विक्लांग हुए तथा उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त किए गए,
- (13) जिस उम्मीदवार ने सशस्त्र सेना के कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में 1963 में प्रवेश किया था, या जिन्हें (कमीशन के बाद प्रशिक्षण में) कमीशन मिला हो। वह यदि पाकिस्तान से आया हुआ वास्तविक

विस्थापित व्यक्ति है, उसके मामले में अधिक से अधिक 3 वर्ष । यह छूट परीक्षा के लिए प्राप्त प्रथम अवसर तक ही सीमित रहेगी ।

(14) जिस उम्मीदवार ने सशस्त्र सेना के कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में 1963 में प्रवेश किया था या जिन्हें (कमीशन के बाद प्रशिक्षण में) कमीशन मिला हो, वह यदि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का है, तथा साथ ही पाकिस्तान से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है तो उसके मामले में अधिक से अधिक 8 वर्ष यह छूट परीक्षा के लिए प्राप्त अवसर तक ही सीमित रहेगी ।

(15) जिस उम्मीदवार ने सशस्त्र सेना के कमीशनपूर्व प्रशिक्षण में 1963 या 1964 या 1965 में प्रवेश किया है या जिन्हें (कमीशन के बाद प्रशिक्षण में) कमीशन मिला हो वह यदि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का निवासी है तो उसके मामले में अधिकतम 4 वर्ष । यह सुविधा कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित होने वाले या 1965 में (कमीशन बाद प्रशिक्षण में) कमीशन प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के सम्बन्ध में परीक्षा में बैठने के लिए मिलने वाले प्रथम अवसर तक ही सीमित होगी, तथा

(16) यदि किसी उम्मीदवार ने कमीशन मिलने से पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश लिया हो या उसे 1963 अथवा 1964 व 1965 में (कमीशन के बाद प्रशिक्षण की स्थिति में) कमीशन मिला हो, और भारतीय नागरिक हो तथा श्रीलंका (पहले सिलोन के नाम से विख्यात) से प्रत्यावर्तित हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष ।

जो उम्मीदवार कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित हुए हों, या जिन्हें 1965 में हुए (कमीशन बाद प्रशिक्षण में) कमीशन मिला हो, उनके सम्बन्ध में इस परीक्षा में प्रथम अवसर के लिए ही सुविधा सीमित है ।

नोट 1—नियम 6(क) के परन्तुक के क्रम संख्या (2), (3), (4), (5) तथा (6) में उल्लिखित उम्मीदवारों पर नियम 6(ख) के खण्ड (13) तथा (14) के उपबन्ध लागू नहीं होंगे ।

नोट 2—नियम 6 के परन्तुक के क्रम संख्या (3), (4), (5) तथा (6) में उल्लिखित उन उम्मीदवारों पर नियम 6(ख) के खण्ड (15) तथा (16) के विहित उपबन्ध लागू नहीं होंगे, जिन्होंने कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश लिया हो या जिन्हें 1963 में हुए (कमीशन बाद प्रशिक्षण में) कमीशन मिला हो ।

नियम 6(क) के परन्तुक के क्रम संख्या (2) में उल्लिखित उन उम्मीदवारों पर नियम 6(ख) के खण्ड (15) तथा (16) में विहित उपबन्ध लागू नहीं होंगे, जिन्होंने 1964 के पश्चात् कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश लिया हो या जिन्हें (कमीशन बाद प्रशिक्षण में) कमीशन मिला हो ।

उपर्युक्त परिस्थिति को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी हालत में छूट नहीं दी जा सकती ।

7. किसी भी उम्मीदवार को प्रतियोगिता परीक्षा में दो बार से अधिक बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

परन्तु उस उम्मीदवार को प्रतियोगिता परीक्षा में केवल एक ही बार बैठने की अनुमति दी जाएगी जो उस वर्ष 1 अगस्त, को, जिसमें उसने सशस्त्र सेना में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण आरम्भ किया था या जिन्हें (कमीशन के बाद प्रशिक्षण में) कमीशन मिला था और उपर्युक्त नियम 6 में उल्लिखित आयु का नहीं हुआ था किन्तु जिस वर्ष में उसने कमीशन पूर्व प्रशिक्षण आरम्भ किया था उसके बाद में उस वर्ष के 1 अगस्त को उस आयु का ही हो गया था ।

नोट :—यदि किसी उम्मीदवार ने भा० प्र० से० आदि (निर्मुक्त आपातकालिक कमीशंड/अल्प सेवा कमीशंड अधिकारी) की 1973 से पहले ली गई परीक्षा की हो तो उसके उस प्रयत्न को भी, इस विनियम के अधीन उम्मीदवारों के प्रयत्नों की गणना करते समय, ध्यान में रखा जाएगा ।

8. (i) यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में केवल एक ही बार बैठने का पात्र हो तो उसे अपने निर्मुक्त होने के वर्ष से पहले के वर्ष में परीक्षा में बैठना चाहिए ।

(ii) यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में दो बार बैठने का पात्र हो तो उसे अपने निर्मुक्त होने के वर्ष से पहले वर्ष में तथा अपने निर्मुक्त होने के वर्ष में परीक्षा में बैठना चाहिए ।

9. नियम 8 में विहित किसी भी बात के बावजूद :—

(क) बशर्ते कि सैनिक सेवा के कारण विक्लांग हुए अल्प-कालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी इस नियम के नीचे टिप्पणियों में उल्लिखित अपवादों के अनुसार सन् 1973 में होने वाली परीक्षा में बैठें ।

(1) यदि वह सन् 1972 की परीक्षा के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त करने की निर्धारित अन्तिम तारीख के पश्चात् 1972 के दौरान विक्लांग हुआ हो, अथवा सन् 1973 की परीक्षा के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के लिए अन्तिम तारीख से पहले सन् 1973 के दौरान विक्लांग हुआ हो और यह अवसर लेने के लिए पात्र हो तो वह उसका केवल मात्र अवसर होगा,

(2) यदि वह सन् 1972 की परीक्षा के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त करने की निर्धारित अन्तिम तारीख के पश्चात् सन् 1972 में विक्लांग हुआ हो अथवा सन् 1973 की परीक्षा के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के लिए अन्तिम तारीख से पहले सन् 1973 के दौरान विक्लांग हुआ हो और दो अवसर लेने के लिए पात्र हो तो यह उसका पहला अवसर होगा ।

(3) यदि वह सन् 1971 की परीक्षा के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त करने की निर्धारित अन्तिम तारीख के पश्चात् सन् 1971 के दौरान विक्लांग हुआ हो, अथवा सन् 1972 की परीक्षा के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के लिए अन्तिम तारीख से पहले सन् 1972 के दौरान विक्लांग हुआ हो और दो अवसर लेने के लिए पात्र हो तो यह उसका दूसरा अवसर होगा ।

(4) यदि वह सन् 1972 की परीक्षा के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त करने की निर्धारित अन्तिम तारीख के पश्चात् सन् 1972 के दौरान विक्लांग हुआ हो और यदि वह सन् 1973 के दौरान रिलीज होने वाला हो तो उसका यह दूसरा अवसर होगा ।

टिप्पणी 1—उपर्युक्त (क) में विहित व्यवस्था उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगी जो सन् 1971, 1972 तथा 1973 के दौरान सैनिक सेवा अवधि में विक्लांग हुए या जी सैनिक सेवा की इस अवधि में अधिक गम्भीर रूप से विक्लांग हुए हों और जिन्होंने क्रमशः सन् 1971, 1972 तथा 1973 के दौरान रिलीज होना था ।

टिप्पणी 2—उपर्युक्त (क) से खण्ड (1) अथवा (2) में विहित व्यवस्था उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगी जो सन् 1972 के दौरान सैनिक सेवा अवधि में विक्लांग हुए हों या जिनकी विक्लांगता इस सेवा अवधि में अधिक गम्भीर हो गई है और जिन्हें सन् 1973 के दौरान रिलीज होना था ।

टिप्पणी 3—उपर्युक्त (क) के खण्ड (3) में विहित व्यवस्था उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगी जो सन् 1971 के दौरान सैनिक सेवा अवधि में विक्लांग हुए हों या उस सेवा के कारण उनकी विक्लांगता अधिक गम्भीर हो गई हो, तथा जिन्हें सन् 1972 के दौरान रिलीज होना था ।

(ख) आपात्कालीन आयुक्त/अल्प सेवा आयुक्त अधिकारी जिसने 10 जनवरी, 1968 से पहले सशस्त्र सेना के कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश किया हो किन्तु जिसे 10 जनवरी, 1968 को या उसके बाद कमीशन मिल गया हो, 1973 में होने वाली परीक्षा में निम्नलिखित शर्तों के साथ बैठ सकता है :—

(i) अपने दूसरे अवसर के रूप में, यदि वह 1972 में रिलीज हुआ हो और दो अवसर लेने का पात्र हो ;

(ii) अपने दूसरे अवसर के रूप में यदि वह वर्ष 1970 की परीक्षा के आवेदन पत्रों की प्राप्ति के लिए निर्धारित अन्तिम तारीख के बाद,

1970 के दौरान विक्लांग हुआ हो, या 1971 की परीक्षा के आवेदन पत्रों की प्राप्ति के लिये निर्धारित अन्तिम तारीख से पहले, 1971 के दौरान विक्लांग हुआ हो, और यदि वह दो अवसर लेने का पात्र हो ;

टिप्पणी—उपरोक्त मद (ii) में निहित व्यवस्थाएं उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होंगी जो सन् 1970 के और 1971 के दौरान सैनिक सेवा के कारण हुई विक्लांगता अथवा उस विक्लांगता के गम्भीर रूप धारण करने के कारण अशक्त हुए हों, और जिन्हें प्रकणः 1970 और 1971 में रिलीज होना था ।

ध्यान दें—इस नियम के उपबन्धों के अनुसार जो उम्मीदवार 1974 में अपना दूसरा अवसर लेने के पात्र हैं वे उस अवसर का उपयोग कर सकेंगे यदि इन नियमों के नियम 1 में निर्दिष्ट नियमों के उपबन्धों की अवधि सरकार द्वारा 28 जनवरी, 1974 से आगे के लिए बढ़ा दी जाती है ।

10(क) उम्मीदवार के पास परिशिष्ट 1 में बताए गए, किसी भी विश्वविद्यालय की डिग्री होनी चाहिए या परिशिष्ट 1(क) में उल्लिखित कोई भी योग्यता होनी चाहिए ,

बशर्ते कि :—

(1) संघ लोक सेवा आयोग अपवाद स्वरूप ऐसे उम्मीदवार को भी योग्यता प्राप्त उम्मीदवार मान सकता है जिसके पास ऊपर बताई गई योग्यताएं नहीं हैं परन्तु जिसने ऐसी अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं जिनके स्तर से आयोग की राय में उसके परीक्षा में प्रवेश लेने का औचित्य प्रकट होता है ।

(2) जो उम्मीदवार अन्यथा योग्यता प्राप्त है परन्तु ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की है जो परिशिष्ट 1 में सम्मिलित नहीं है, वह भी आयोग के पास आवेदन कर सकता है और आयोग के विवेक से उस परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है ।

(ख) जो उम्मीदवार सशस्त्र सेना में आपात्कालीन कमीशन/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्ति के लिए सेवा चयन बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत होने के समय, इस नियम के उप नियम (क) में निर्धारित कोई योग्यता प्राप्त करने के लिए किसी विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी संस्था में अध्ययन कर रहा था, परन्तु जो सशस्त्र सेना में नियुक्त हो जाने के कारण अपना अध्ययन जारी नहीं रख सका और इस प्रकार ऐसी योग्यता प्राप्त नहीं हुई, वह उम्मीदवार भी इस परीक्षा में बैठने का पात्र होगा ।

नोट—जो उम्मीदवार किसी ऐसी परीक्षा में बैठा है जिसमें उत्तीर्ण होने से वह इस नियम के उप-नियम (क) के अनुसार इस परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हो जाएगा, परन्तु जिस परीक्षा

का परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है, वह भी इस परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन कर सकता है। जो उम्मीदवार ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठना चाहता है वह भी आवेदन कर सकता है, बशर्त कि वह अर्हक परीक्षा इस परीक्षा के आरम्भ होने से पहले ही पूर्ण हो जाए। ऐसे उम्मीदवारों को इस परीक्षा में बैठने दिया जाएगा, जो अन्यथा इसके लिए पात्र होंगे, परन्तु यह प्रवेश अस्थायी माना जाएगा और उसे रद्द किया जा सकेगा, यदि उक्त परीक्षा के उत्तीर्ण करने का प्रमाण यथाशीघ्र और इस परीक्षा के आरम्भ होने के बाद किसी भी स्थिति में दो-महीने तक प्रस्तुत नहीं करेंगे।

11. यदि किसी परीक्षा के परिणाम के आधार पर किसी उम्मीदवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय विदेश सेवा में नियुक्ति हो जाती है तो वह इस परीक्षा में बैठने का पात्र नहीं होगा।

यदि पिछली परीक्षा के परिणाम के आधार पर किसी उम्मीदवार की नियुक्ति नीचे स्तम्भ (2) में उल्लिखित किसी सेवा में हो जाती है तो वह इन नियमों की व्यवस्थाओं के अधीन इस परीक्षा में केवल उन्हीं सेवाओं के लिए बैठने का पात्र होगा जो उक्त सेवा के सामने नीचे स्तम्भ (3) में दी हुई है :—

क्रम संख्या	जिस सेवा में नियुक्ति हुई	जिन सेवाओं के लिये परीक्षा में बैठने का पात्र हैं
1.	भारतीय पुलिस सेवा	भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा तथा अन्य केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी-I
2.	केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी-I (भारतीय विदेश सेवा को छोड़कर)	भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा
3.	केन्द्रीय सेवाएं, श्रेणी-II (संघ शासित क्षेत्रों की सिविल तथा पुलिस सेवाओं सहित)	भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा तथा अन्य केन्द्रीय श्रेणी-I

12. सशस्त्र सेवाओं में कार्य कर रहे उम्मीदवार को चाहिए कि वह इस परीक्षा के लिये अपना आवेदन पत्र अपने यूनिट को कमांड करने वाले अफसर के सामने प्रस्तुत कर दें, जो उसे संघ लोक सेवा आयोग के पास भेज देगा। उम्मीदवार जो स्वयं अपने यूनिट का समाविष्ट अधिकारी है, अपने से वरिष्ठ अधिकारी की मार्फत आवेदन पत्र भेजें।

सरकारी सेवा में लगे अन्य सभी उम्मीदवारों को चाहे वे स्थायी अथवा अस्थायी रूप में कार्य कर रहे हों या नैमित्तिक अथवा दिहाड़ी वाले कर्मचारियों को छोड़कर कार्य प्रभारी कर्मचारी हों, परीक्षा में बैठने के लिए अपने विभाग के अध्यक्ष से पूर्व अनुमति अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए।

13. परीक्षा में बैठने के लिये उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

14. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा, जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) नहीं होगा।

15. यदि कोई उम्मीदवार किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिये पैरवी करने की कोई कोशिश करेगा तो उसे परीक्षा में बैठने के लिये अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

16. किसी दूसरे व्यक्ति से परीक्षा दिलवाने अथवा जाली या फेर बदल किए प्रमाण पत्र पेश करने अथवा गलत या झूठी बात बताने अथवा किसी तथ्य को छिपाने या परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित उपाय अपनाने परीक्षा भवन में कोई अनुचित उपाय अपनाने या अपनाने की चेष्टा करने अथवा परीक्षा भवन में किसी तरह का अनुचित आचरण करने पर आयोग ने यदि किसी उम्मीदवार को अपराधी घोषित किया है तो उम्मीदवार के विरुद्ध दण्डिक अभियोजन के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यवाही की जा सकती है :—

(क) (1) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उम्मीदवारों के चुनाव के लिये आयोजित किसी परीक्षा में सम्मिलित होने अथवा किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने से, तथा

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकार के अन्तर्गत नौकरियों से, उसको सदा के लिये अथवा किसी विशेष अवधि के लिये, वारित किया जा सकता है।

(ख) यदि वह पहले से ही सरकार की सेवा में हो तो उचित नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही हो सकती है।

17. आयोग लिखित परीक्षा में अपने निर्णय पर निर्धारित न्यूनतम अर्हता-अंक (क्वालीफाइंग मार्क्स) प्राप्त उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा के लिये बुलाएगा।

18. परीक्षा के बाद, आयोग उम्मीदवारों के द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यता क्रम से उनकी सूची बनाएगा और उसी क्रम से उन उम्मीदवारों में से जितने लोगों को आयोग अपने निर्णय के अनुसार परीक्षा के आधार पर अर्हता प्राप्त समझेगा, उन्हें इन रिक्तियों पर नियुक्त करने के लिये सिफारिश करेगा।

लेकिन शर्त यह है कि आयोग, जिस सीमा तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिये आरक्षित स्थान सामान्य योग्यता के आधार पर नहीं भरे जा सकते उस सीमा तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों के योग्यता स्तर में ढील दे कर चुनने की सिफारिश करे जिससे कि आरक्षित कोटे में होने वाली कमी पूरी की जा सके, बशर्त कि ये प्रत्याशी सेवाओं में नियुक्ति के लिये पात्र हों, भले ही परीक्षा में उनका योग्यता क्रम कुछ भी हो।

19. (क) यदि परीक्षाफल के आधार पर, निर्मुक्त आपातकालीन आयुक्त/अल्पकालीन सेवा आयुक्त अफसरों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त संख्या में अर्हता प्राप्त उम्मीदवार नहीं होंगे, तो अपूरित रिक्तियों को इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित विधि से भरा जाएगा।

(ख) अगर योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों की संख्या निर्मुक्त आपातकालीन आयुक्त अफसरों/अल्पकालीन सेवा आयुक्त अफसरों के लिये आरक्षित स्थानों से अधिक हो तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों को नियुक्त नहीं किया गया है उनके नाम प्रतीक्षा सूचियों पर रखे जाएंगे जिससे उन्हें बाद के वर्षों में उनके लिये आरक्षित कोटे के पदों पर नियुक्त किया जा सके बशर्ते कि निर्मुक्त आपातकालीन आयुक्त/अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारियों के लिए आरक्षण भारत सरकार द्वारा 28-1-1974 में आगे के लिये जारी रखे जाने हैं।

20. हरेक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किताब रूप में और किस प्रकार दी जाए, उसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा। आयोग परीक्षाफल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्राचार नहीं करेगा।

21. इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्तियाँ करते समय उम्मीदवारों की उन प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाएगा जो उन्होंने प्रार्थना पत्र भेजते समय व्यक्त की हैं।

किन्तु यह कि यदि कोई उम्मीदवार पिछली परीक्षा के परिणामों के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त हो जाता है तो इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर किसी अन्य सेवा के लिये उसकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

किन्तु यह और भी शर्त है कि यदि कोई उम्मीदवार पिछली परीक्षा के परिणामों के आधार पर स्तम्भ (2) में उल्लिखित किसी सेवा में नियुक्त हो जाता है तो इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर नीचे स्तम्भ (3) में उसी सेवा के सामने उल्लिखित सेवाओं के लिये ही उसकी नियुक्ति पर विचार किया जाएगा।

क्रम सं०	जिस सेवा में नियुक्ति हुई	जिस सेवा में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा
1.	भारतीय पुलिस सेवा	भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और अन्य केन्द्रीय सेवाएं, श्रेणी-I
2.	केन्द्रीय सेवाएं, श्रेणी-I (भारतीय विदेश सेवा को छोड़कर)	भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा।

3. केन्द्रीय सेवाएं, श्रेणी-II भारतीय प्रशासनिक सेवा, (संघ शासित क्षेत्रों की भारतीय पुलिस सेवा और सिविल तथा पुलिस सेवाओं अन्य केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी-I सहित)

22. परीक्षा में पास हो जाने से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार इस सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से योग्य है।

23. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे वह संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक न निभा सके। यदि सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बीच किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हो कि वह इन आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर सकता तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। आयोग द्वारा मौखिक परीक्षा के लिए बुलाए गए उम्मीदवार की डाक्टरी परीक्षा कराई जा सकती है।

नोट :—बाद में निराश न होना पड़े इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र भेजने से पहले सिविल सर्जन के स्तर के सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपनी जांच करावाएं। नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों की किस प्रकार की डाक्टरी जांच होगी और उसके लिए स्वास्थ्य का स्तर किस प्रकार का होना चाहिए, इसके ब्यौरे इन नियमों के परिशिष्ट 4 में दिए गए हैं। भूतपूर्व रक्षा सेवाओं के विकलांग कर्मचारियों के मामले में उन मामलों के संबंध में प्रत्येक सेवा की अपेक्षाओं के अनुरूप छूट दी जाएगी।

24(क) जिस स्त्री/जिस पुरुष ने ऐसे पुरुष/ऐसी महिला से विवाह करने का करार किया हो अथवा विवाह कर लिया हो, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जिस पुरुष/जिस तत्नी ने जीवित पत्नी/पति के होते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह करने का करार किया हो अथवा विवाह कर लिया हो, वह उक्त पद पर नियुक्त का पात्र नहीं होगा/होगी।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति पर अथवा जिससे विवाह किया गया हो उस पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य कारण हैं, तो ऐसे व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

25. भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त अधिकारियों को किसी भी हालत में भारतीय नागरिकता प्राप्त व्यक्तियों को छोड़कर बिवाह करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

26. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि सेवा में भर्ती होने से पहले ही हिन्दी का कुछ ज्ञान होना उन विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने की दृष्टि से लाभदायक होगा जो उम्मीदवारों को सेवा में भर्ती होने के बाद देनी पड़ती हैं।

27. इस परीक्षा के आधार पर जिन सेवाओं में भर्ती की जानी है उसके संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट 3 में दिए गए हैं।

बी० रंगानाथन, अव्वर सचिव

परिशिष्ट I

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय की सूची

(नियम 10 के अनुसार)

भारतीय विश्वविद्यालय

कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय जो भारत के केन्द्रीय या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम से निर्गमित किया गया हो और अन्य शिक्षा संस्थान जो संसद के अधिनियम से स्थापित किया गया हो अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय मान लिए जाने की घोषणा हो चुकी है।

बर्मा के विश्वविद्यालय

रंगून विश्वविद्यालय और मांडले विश्वविद्यालय।

इंग्लैंड और वेल्स के विश्वविद्यालय

बर्मिंघम, ब्रिस्टल, केम्ब्रिज, डहमे, लीड्स लिबरपुल, लंदन। मैचेस्टर, आक्सफोर्ड, रीडिंग, शफील्ड और वेल्स के विश्वविद्यालय।

स्काटलैंड के विश्वविद्यालय

एबरडीन, एडिनबरा, ग्लासगो, और सेट एन्ड्रयूज विश्व-विद्यालय।

आयरलैंड के विश्वविद्यालय

डबलिन विश्वविद्यालय (ट्रिनिटी कालेज)।

नेशनल यूनिवर्सिटी, डबलिन।

क्वीन्स यूनिवर्सिटी, बेलफास्ट।

पाकिस्तान के विश्वविद्यालय

पंजाब विश्वविद्यालय।

सिंध विश्वविद्यालय।

बंगला देश के विश्वविद्यालय

ढाका विश्वविद्यालय।

राजशाही विश्वविद्यालय।

नेपाल का विश्वविद्यालय

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाण्डू।

परिशिष्ट 1-क

परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए अनुमोदन योग्यताओं की सूची
(नियम 10 के अनुसार)

1. शास्त्री, काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
2. फांसीसी परीक्षा (Propedentique)।
3. उच्च ग्राम शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् (नेशनल कौंसिल आफ ग्राम हायर एज्यूकेशन) से ग्राम सेवाओं में डिप्लोमा।
4. विश्वभारतीय विश्वविद्यालय का उच्च ग्राम सेवाओं में डिप्लोमा।
5. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् आस इंडिया कौंसिल फार टेक्निकल एज्यूकेशन से वाणिज्य में डिप्लोमा।
6. केन्द्रीय सरकार के अधीन वरिष्ठ सेवाओं और पदों पर भर्ती के लिए सरकार से मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय डिप्लोमा।
7. श्री अरविन्द अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र पांडिचेरी का "उच्च पाठ्यक्रम," यदि "पूर्ण छात्र" (फुल स्टूडेंट) के रूप में यह पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया गया हो।
8. भारतीय खान विद्यालय, धनबाद, से खनन इंजीनियरी में डिप्लोमा।
9. मानविकी और प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र में उपाधि-पत्र यू० एस० एस० आर० में उच्च शैक्षिक स्थापना से अनुप्रमाणित उपाधि-ग्रहण बिना प्रथम वैज्ञानिक शोध प्रबन्ध का पक्ष लिए हुए परन्तु राज्य की परीक्षाएं पास की हों।
10. शास्त्री (अंग्रेजी विषय के साथ) या पुराना शास्त्री या अंग्रेजी सहित अतिरिक्त विषयों में विशेष परीक्षा सहित सम्पूर्ण शास्त्री परीक्षा अर्थात् वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की वरिष्ठ शास्त्री परीक्षा।
11. गुरुकुल विश्वविद्यालय, कांगड़ी, हरिद्वार की अनंकार डिग्री।
12. अमेरिकन यूनिवर्सिटी आफ बेरूत, बेरूत लेबनान द्वारा प्रदान की गई बैचलर आफ आर्ट्स (बी० ए०) तथा बैचलर आफ साइंस (बी० एस०) की डिग्रियां।

परिशिष्ट II

परीक्षा की रूपरेखा

1. प्रतियोगिता-परीक्षा के निम्नलिखित भाग होंगे :—
- (क) तीन विषयों में लिखित परीक्षा जिसका विवरण नीचे पैरा 2 में दिया हुआ है। इसके पूर्णांक 450 होंगे।
- (ख) उन उम्मीदवारों के लिए मौखिक परीक्षा जिन्हें आयोग इस प्रयोजन के लिए बुलाएगा। इसके पूर्णांक 250 होंगे और इनमें से 50 अंक सशस्त्र मेना के मेवाबूत के गुल्यांकन के लिए रखे जाएंगे।

2. लिखित परीक्षा के विषय, निर्धारित समय और प्रत्येक विषय के पूर्णांक इस प्रकार होंगे :—

विषय	निर्धारित समय	पूर्णांक
(I) निबन्ध	3 घंटे	150
(II) सामान्य अंग्रेजी	3 घंटे	150
(III) सामान्य ज्ञान	3 घंटे	150

3. परीक्षा का पाठ्यविवरण संलग्न अनुसूची के अनुसार होगा। लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय के लिए वही प्रश्न-पत्र होंगे जो इस परीक्षा के साथ ही ली जाने वाली नियमित भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि परीक्षा की योजना के अनुसार उपयुक्त विषयों के लिए होंगे।

4(क) ऊपर के पैरा 2 के क्रमशः (I) और (II) के 'निबन्ध' तथा 'सामान्य ज्ञान' के प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी अथवा संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भाषा में दिए जा सकते हैं, अर्थात् असमिया, बंगला, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। अंग्रेजी के अतिरिक्त विकल्प रूप में किसी अन्य भाषा में उत्तर देने वाले उम्मीदवारों को वही भाषा दोनों पत्रों के लिए चुननी होगी। विकल्प सम्पूर्ण पत्र के लिए लागू होगा न कि उस के किसी अंश के लिए।

(ख) ऊपर के पैरा 2 के क्रमशः (II) के सामान्य अंग्रेजी के उत्तर अंग्रेजी में दिए जाने चाहिए।

टिप्पणी I:—ऊपर दिए पैरा 4(क) में अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी भाषा में प्रश्न-पत्र (श्री०) के उत्तर देने के इच्छुक उम्मीदवार को आवेदन-पत्र के कालम 34 में संबंधित भाषा का नाम संबंधित प्रश्न-पत्र (प्रश्न-पत्रों) के सामने देना चाहिए। यदि दिए हुए कालमों में एक या दोनों प्रश्न-पत्रों के संबंध में कोई अंदराज नहीं किया जाता है तो यह समझा जाएगा कि प्रश्न-पत्र/प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिए जाएंगे। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम समझा जाएगा और परिवर्तन अथवा परिवर्धन के लिए कोई अनुरोध नहीं माना जाएगा।

टिप्पणी II:—ऊपर दिए पैरा 4(क) में संविधान की आठवीं अनुसूची में दी गई किसी भाषा में विकल्प रूप से प्रश्न-पत्र (प्रश्न-पत्रों) के उत्तर देने वाले उम्मीदवार अपने उत्तर क्रमशः निम्नलिखित लिपि में देंगे :—

भाषा	लिपि
1. असमिया	असमिया
2. बंगला	बंगला
3. गुजराती	गुजराती

4. हिन्दी	देवनागरी
5. कन्नड़	कन्नड़
6. कश्मीरी	फारसी
7. मलयालम	मलयालम
8. मराठी	देवनागरी
9. उड़िया	उड़िया
10. पंजाबी	गुरुमुखी
11. संस्कृत	देवनागरी
*12. सिंधी	देवनागरी अथवा अरबी
13. तमिल	तमिल
14. तेलुगु	तेलुगु
15. उर्दू	फारसी

*ऊपर पैरा 1(क) में दिए गए प्रश्न-पत्र (प्रश्न-पत्रों) के उत्तर देने के लिए सिंधी का विकल्प देने वाले उम्मीदवारों को आवेदन-पत्र के कालम 32 में उस विशेष लिपि (देवनागरी या अरबी) का नाम लिखना चाहिए जिस में वे उत्तर लिखेंगे।

5. उम्मीदवारों को प्रश्नों का उत्तर अपने हाथ से लिखना होगा। उन्हें किसी भी हालत में उनकी ओर से उत्तर लिखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हता अंक (क्वालिफाइंग मार्क्स) निर्धारित कर सकता है।

7. यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट आसानी से पढ़ने लायक नहीं होगी तो इसके लिए उसे अन्यथा प्राप्त कुल अंकों में से कुछ अंक काट लिए जाएंगे।

8. उम्मीदवारों को प्रत्येक विषय में दिए गए नम्बरों में से आयोग द्वारा निर्धारित नम्बर इसी लिए काट लिए जाएंगे कि कहीं सतही ज्ञान को तो कोई महत्व नहीं दिया गया है।

9. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि अभिव्यक्ति कम से कम शब्दों में क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई है।

अनुसूची

(देखिए परिशिष्ट II का पैरा 3)

भाग—(क)

1. **निबंध—**उम्मीदवारों से एक निबंध लिखने की अपेक्षा की जाएगी। चुनाव के लिए कई विषय दिये जायेंगे। उनसे आशा की जाएगी कि वे निबंध के विषय की परिधि में ही अपने विचारों को क्रम से व्यवस्थित करें और संक्षेप में लिखें। प्रभावपूर्ण और ठीक-ठीक भावाभिव्यक्ति का प्रश्न दिया जाएगा।

2. **सामान्य अंग्रेजी—**प्रश्न इस प्रकार के होंगे जिनसे उम्मीदवारों के अंग्रेजी भाषा के ज्ञान तथा शब्दों के सुन्दर उपयोग की सामर्थ्य का पता चले। कुछ प्रश्न इस प्रकार भी रखे जाएंगे जिससे

उनकी तर्कशक्ति, उनकी निहितार्थ को ग्रहण कर सकने की सामर्थ्य तथा महत्वपूर्ण और कम महत्व वाले कार्य में अन्तर समझ सकने की योग्यता की परीक्षा हो सके। जैसा कि आमतौर पर होता है संक्षेप सार-लेखन के लिए लेखांक दिए जायेंगे। संक्षिप्त एवं प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए श्रेय दिया जाएगा।

3. सामान्य ज्ञान—सामयिक घटनाओं के, और ऐसी बातें जो प्रतिदिन देखते और अनुभव करते हैं, उसके वैज्ञानिक दृष्टि से ज्ञान सहित जिस की ऐसी शिक्षित व्यक्ति से आशा की जा सकती है कि जिसने वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो। इस प्रश्न में भारतीय इतिहास और भूगोल के ऐसे प्रश्न भी होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवारों को विशेष अध्ययन के बिना ही आना चाहिए। इस प्रश्न पत्र में महात्मा गांधी के उपदेशों से सम्बन्धित प्रश्न भी होंगे।

भाग—(ख)

मौखिक परीक्षा—एक बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों की मौखिक परीक्षा ली जाएगी, बोर्ड के सामने प्रत्येक उम्मीदवार के कैरियर का वृत्त होगा, जिसमें सशस्त्र सेनाओं में उसकी सेवा का वृत्त भी शामिल होगा। उम्मीदवार से सामान्य रुचि के विषयों तथा सशस्त्र सेनाओं के उसके अनुभवों के संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे। सक्षम और निष्पक्ष पर्यवेक्षकों के बोर्ड द्वारा सेवा के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना मौखिक परीक्षा का उद्देश्य है।

मौखिक परीक्षा में पूरी तरह से प्रति परीक्षा (Cross Examination) की प्रणाली नहीं अपनाई जाती, बल्कि उम्मीदवार के ऐसे मानसिक गुणों का उद्घाटन करने के उद्देश्य से किए जाने वाले स्वभाविक किन्तु साथ ही निर्दिष्ट तथा सोद्देश्य वार्तालाप की प्रणाली अपनाई जाती है, अर्थात् जिससे मानसिक स्फूर्ति, पहलशक्ति, आलोचनात्मक ग्रहण शक्ति, स्पष्ट तथा तर्कसंगत प्रतिपादन करने की शक्ति, संतुलित निर्णय की शक्ति, रुचि की विविधता और गहनता, नेतृत्व और सामाजिक संगठन की योग्यता, बौद्धिक एवं नैतिक निष्ठा की जांच हो सके।

परिशिष्ट III

इस परीक्षा के द्वारा जिन सेवाओं में भर्ती की जा रही है उसका संक्षिप्त व्यौरा :—

1. भारतीय प्रशासनिक सेवा—(क) नियुक्तियां परख पर की जाएंगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी और उसे बढ़ाया भी जा सकेगा। सफल उम्मीदवार को परख की अवधि, में भारत सरकार के निर्णय के अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चित रीति से कार्य करना होगा और निश्चित परीक्षाएं पास करनी होंगी।

(ख) यदि सरकार की राय में किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्य-कुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है।

(ग) परख अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को इस सेवा में पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य, या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

(घ) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत, भारत में या विदेश में किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती हैं।

(ङ) वेतन-मान—

जूनियर—रु० 400-400-500-40-700-द० रो०-30-1000 (18 वर्ष)।

सीनियर—

(i) समय-मान—रु० 900 (छठे वर्ष या पहले)-50-1000-60-1600-50-1800 (22 वर्ष)।

(ii) सलेक्शन ग्रेड—1800-100-2000।

इनके अतिरिक्त अधिसमय-मान पद भी होते हैं जिनका वेतन रु० 2150 से रु० 3500 तक होता है और जिन पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति हो सकती है।

महंगाई भत्ता समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार मिलेगा।

परखाधीन अधिकारियों की सेवा जूनियर समय में प्रारम्भ होगी और उन्हें परख पर बितार्थ गई अवधि को समय-मान में वेतन वृद्धि छुट्टी या पेंशन के लिए गिनने की अनुमति होगी।

(च) भविष्य निधि—भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) नियमावली, 1955 से शासित होते हैं।

(छ) छुट्टी—भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1955 से शासित होते हैं।

(ज) डाक्टर परिचर्या—भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अखिल भारतीय, सेवा (डाक्टर परिचर्या) नियमावली, 1954 के अन्तर्गत अनमत्य डाक्टर परिचर्या की सुविधाएं पाने का हक है।

(झ) सेवा निवृत्ति लाभ—प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति किए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-व-सेवा-निवृत्ति लाभ) नियमावली 1958 द्वारा शासित होते हैं।

2. भारतीय विदेश सेवा—(क) नियुक्ति परख पर की जायेगी जिसकी अवधि आमतौर पर 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। सफल उम्मीदवारों को भारत में लगभग 21 मास तक प्रशिक्षण लेना होगा। इसके बाद उन्हें तृतीय सचिव या उप-कौमुल बनाकर उन भारतीयों मिशन में भेज दिया जायेगा जिनकी भाषायें उनके लिए अनिवार्य भाषाओं के रूप में नियत की गई हों। प्रशिक्षण की अवधि में परखाधीन अधिकारियों को एक या अधिक विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी इसके बाद ही वे सेवा में पक्के हो सकेंगे।

(ख) सरकार के लिए संतोषजनक रूप से परख-अवधि के समाप्त होने और निर्धारित परीक्षाएं पास करने पर ही परखाधीन अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का किया जायेगा। परन्तु यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे सेवा-मुक्त कर सकती है या परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है या यदि उसका कोई मूल पद (सबस्टेंटिव पोस्ट) हो तो उस पर वापस भेज सकती है।

(ग) यदि सरकार की राय में, किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके विदेश सेवा के लिए उपयुक्त होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है या यदि उसका कोई मूल-पद हो तो उसे उस पर वापस भेज सकती है।

(घ) वेतनमान—

जूनियर—रु० 400-400-500-40-700-द० रो०-30-1000।

सीनियर—रु० 900 (छठे वर्ष या पहले)—50-1000-60-1500-50-1800।

इनके अतिरिक्त अधिसमय-मान पद पर भी होते हैं जिनका वेतन रु० 1800 से रु० 3500 तक होता है और जिन पर भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति हो सकती है।

(ङ) परख-अवधि में परखाधीन अधिकारी को इस प्रकार वेतन मिलेगा :—

पहले वर्ष—रु० 400 प्रति मास।

दूसरे वर्ष—रु० 400 प्रति मास।

तीसरे वर्ष—रु० 500 प्रति मास।

नोट 1—परखाधीन अधिकारी की परख पर बिताई गई अवधि, समय-मान में वेतन-वृद्धि, छुट्टी या पेंशन के लिए गिनने की अनुमति होगी।

नोट 2—परखाधीन अधिकारी को परख-अवधि में वार्षिक वेतन-वृद्धि तभी मिलेगी जबकि वह निर्धारित परीक्षाएं (यदि कोई हो) पास कर लेगा और सरकार को संतोषप्रद प्रगति करके दिखाएगा। विभागीय परीक्षाएं पास करके अग्रिम वेतन-वृद्धियां भी अर्जित की जा सकती हैं।

नोट 3—परिबीक्षाधीन के तौर पर नियुक्ति से पूर्व सावधि पद के अतिरिक्त मूल रूप से स्थायी पद पर रहने वाले सरकारी कर्मचारी का वेतन एफ० आर० 22-बी० (1) के अधीन दिया जाएगा।

(च) भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी से भारत में या भारत के बाहर किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती हैं।

(छ) विदेश में सेवा करते समय, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को उनकी हैसियत (Status) के अनुसार विदेश भत्ते मिलेंगे जिससे कि वे नौकर-चाकरों और जीवन-निर्वाह के बड़े हुए खर्च को पूरा कर सकें और आतिथ्य (इंटरटेनमेन्ट) सम्बन्धी अपनी विशेष जिम्मेदारियों को भी निभा सकें। इसके

अतिरिक्त विदेश में सेवा करते समय, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को निम्नलिखित रियायतें भी मिलेंगी :—

(i) हैसियत के अनुसार मुफ्त मुसज्जित मकान।

(ii) सहायता प्राप्त डाक्टरी परिचर्या योजना (Assisted Medical Attendance Scheme) के अन्तर्गत डाक्टरी परिचर्या की सुविधाएं।

(iii) भारत आने के लिये वापसी हवाई यात्रा का किराया, जो अधिक-से-अधिक दो बार और विशेष आपाती। स्थितियों (Emergencies) में ही दिया जायेगा, जैसे—भारत में स्थित किसी निकटतम सम्बन्धी की मृत्यु या सख्त बीमारी अथवा पुत्री का विवाह।

(iv) भारत में पढ़ने वाले 8 से 18 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के लिए वर्ष में एक बार वापसी हवाई यात्रा का किराया, ताकि वे लम्बी छुट्टियों में माता-पिता से मिल सकें। परन्तु इस रियायत पर कुछ शर्तें लागू होंगी।

(v) 5 से 18 वर्ष तक की आयु वाले अधिक-से-अधिक दो बच्चों के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर शिक्षा/भत्ता।

(vi) विदेश में प्रशिक्षण के लिए जाने समय और सेवा में पक्का होने पर सज्जा-भत्ता (Outfit Allowance) अधिकारी की सेवा काल की विभिन्न अवस्थाओं में भी निर्धारित नियमों के अनुसार दिया जाता है। साधारण सज्जा-भत्ते के अतिरिक्त विशेष सज्जा-भत्ता भी उन अधिकारियों को दिया जा सकता है जिन्हें असाधारण रूप से कठोर जलवायु वाले देशों में तैनात किया जाए।

(vii) विदेश में कम-से-कम दो वर्ष सेवा करने के बाद, अधिकारियों, उनके परिवारों और नौकरों के लिए छुट्टी पर घर जाने का किराया।

(ज) समय-समय पर संशोधित पुनरीक्षित छुट्टी नियमावली, 1933 कुछ तरकीबों के साथ, इस सेवा के सदस्यों पर लागू होगी। विदेश में की गई सेवा के लिये भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को, भारतीय विदेश सेवा (PLCA) नियमावली 1961 के अन्तर्गत अतिरिक्त छुट्टियां मिलेंगी, जो पुनरीक्षित छुट्टी नियमावली के अन्तर्गत मिलने वाली छुट्टी के 50 प्रतिशत तक होगी।

(झ) भविष्य निधि—भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी, समन्वय भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली, 1960 द्वारा शासित होते हैं।

(ञ) सेवा निवृत्ति लाभ—प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किए गए भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी उदारीकृत (Liberalised) पेंशन नियमावली 1950 द्वारा शासित होते हैं।

(ट) भारत में रहते समय, अधिकारियों को वे ही रियायतें मिलेंगी जो उनके समकक्ष या समान हैसियत (Status) वाले सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती हैं।

3. भारतीय पुलिस सेवा—(क) नियुक्ति परख पर की जायेगी जिसकी अवधि दो वर्ष होगी और उसे बढ़ाया भी जा सकेगा। सफल उम्मीदवारों को परख की अवधि में भारत सरकार के निर्णय के अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चित रीति से कार्य करना होगा और निश्चित परीक्षाएं पास करनी होंगी।

(ख) } जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के खंड (ख) और
(ग) } (ग) में दिया गया है।

(घ) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत भारत में या विदेश में, किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती हैं।

(ङ) वेतनमान—

जूनियर—रु० 400-400-450-30-600-35-670-
रु० 10-35-950 (18 वर्ष)

सीनियर—रु० 740 (छठे वर्ष या पहले) 40-1100-
50/2-1250-50-1300 (22 वर्ष)।

सलेक्शन ग्रेड—रु० 1400

पुलिस उप-महानिरीक्षक—रु० 1600-100-2000।

पुलिस कमिशनर, कलकत्ता और बम्बई—रु० 1800-100-
2000।

पुलिस महानिरीक्षक—रु० 2500-125/2-2750।

निदेशक, खुफिया ब्यूरो—रु० 3000।

महंगाई भत्ता समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार मिलेगा।

(च) }
(छ) } जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के खंड (च)
(ज) } (छ), (झ) और (1) में दिया गया है।
(झ) }

4. केन्द्रीय सूचना सेवा ग्रेड II (श्रेणी-1)---

(क) केन्द्रीय सूचना सेवा के पद, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न माध्यम संगठनों (media organisations) में भारत भर में है। इन पदों के लिए पत्रकारिता और ऐसी ही अन्य व्यावसायिक योग्यता होनी जरूरी है। यह सेवा पहली मार्च, 1960 को बनाई गई थी।

(ख) इस सेवा में इस समय निम्नलिखित ग्रेड हैं:—

ग्रेड	वेतनमान
श्रेणी I	
सलेक्शन ग्रेड रु०	2500-125/2-2750
सीनियर प्रशासनिक ग्रेड	
(सीनियर मान) रु०	1800-100-2000
(जूनियर मान) रु०	1600-100-1800
जूनियर प्रशासनिक ग्रेड	
(सीनियर मान) रु०	1300-60-1600
(जूनियर मान) रु०	1100-50-1400

ग्रेड I	700-40-1100-50/2-1250
ग्रेड II	रु० 400-400-450-30-600- 35-670-रु० 10-35-950।
श्रेणी 2 (राजपत्रित)	
ग्रेड III	रु० 350-25-500-30-590- रु० 10-30-800।
श्रेणी 2 (अराजपत्रित)	
ग्रेड IV	रु० 270-10-290-15-410- रु० 10-15-485

(ग) सेवा के निम्नलिखित ग्रेडों में सीधी भर्ती नीचे स्पष्ट की गई प्रतिशतता के अनुसार की जाती है:

कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (कनिष्ठ वेतनक्रम)	12½%
ग्रेड I	25%
ग्रेड II स्थायी पदों पर	50%
ग्रेड IV	100%

ग्रेड III की रिक्तियां ग्रेड IV के अधिकारियों में से विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर प्रवरण के आधार पर, पदोन्नति द्वारा भरी जाएंगी।

ग्रेड II की 50% स्थायी तथा समस्त अस्थायी रिक्तियां, ग्रेड I की 75% रिक्तियों और कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (कनिष्ठ वेतनक्रम) की 87½% रिक्तियां तुरन्त नीचे के ग्रेड में ड्यूटी पोस्टों पर नियुक्ति अधिकारियों में से चयन द्वारा पदोन्नति के आधार पर भरी जाती है।

सलेक्शन ग्रेड, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (वरिष्ठ वेतन-क्रम)

तथा वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (कनिष्ठ वेतन क्रम और कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (वरिष्ठ वेतनक्रम) की रिक्तियां सम्बन्धित ग्रेड से तुरन्त नीचे के ग्रेड में ड्यूटी पोस्टों पर नियुक्त अधिकारियों में से चयन द्वारा भरी जाती हैं। यदि ऐसी पदोन्नति के लिये कोई उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध नहीं होता तो सलेक्शन ग्रेड तथा वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ऐसी रिक्तियों में संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से नियुक्ति की जायेगी। कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (वरिष्ठ वेतनक्रम) की रिक्तियां उक्त ग्रेड के कनिष्ठ वेतनक्रम में ड्यूटी पोस्टों पर नियुक्त अधिकारियों में से वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर भरी जायेंगी।

सरकार किसी ग्रेड में उस ग्रेड की संख्या के अधिक से अधिक 10% तक संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, ऐसी निश्चित की गई अवधि के लिए जो 5 वर्ष से अधिक न होगी, राज्यों के प्रकार संगठनों के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा भर सकती है। पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती द्वारा भर जाने वाले पदों की संख्या निर्धारित करते समय इस प्रकार भरे गये पदों को ध्यान में रखा जाता है।

(घ) (i) ग्रेड II में सीधे भरती किए गए उम्मीदवार दो वर्ष तक परीक्षोन्मादीन रहेंगे। परीक्षोन्मादीन काल में उन्हें भारतीय लोक संचार संस्थान (इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन)

किसी समाचार पत्र अथवा समाचार एजेंसी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न माध्यम एककों में और लाल बहादूर शास्त्री प्रशासन अकादमी मसूरी में प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण की कुल अवधि लगभग 20 मास होगी। प्रशिक्षण की अवधि तथा स्वरूप में सरकार परिवर्तन कर सकती है। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें लाल बहादूर शास्त्री प्रशासन अकादमी मसूरी की “पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा” (एड ग्राफ-द-कोर्स-टैस्ट) भारतीय लोक संचार संस्थान की प्रथम प्रशिक्षण और द्वितीय विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। विभागीय परीक्षा में भाषा ज्ञान की परीक्षा भी सम्मिलित रहेगी। विभागीय परीक्षा में असफल होने पर उम्मीदवार को सेवा से मुक्त किया जा सकता है अथवा उस स्थायी पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है जिस पर उसकी पदधारिता हो।

(ii) परख अवधि की समाप्ति पर, यदि स्थायी पद उपलब्ध हो तो सरकार सीधे भर्ती वाले अधिकारियों को, वर्तमान नियमों के अनुसार उनकी नियुक्ति में पक्का कर सकती है यदि परखाधीन अधिकारी का कार्य और आचरण सन्तोषजनक न रहा तो उसे सेवा मुक्त किया जा सकता है या परख की अवधि उतने समय के लिये बढ़ायी जा सकती है जितना कि सरकार ठीक समझे। यदि उसके कार्य और आचरण से उसके कार्यकुशल होने की सम्भावना न हो तो उसे तत्काल सेवा-मुक्त किया जा सकता है।

(iii) परिवीक्षाधीन को प्रारम्भ में ग्रेड II के वेतनमान में न्यूनतम वेतन मिलेगा। प्रथम विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के बाद परिवीक्षाधीनों को वेतन बढ़ा कर केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड II के वेतन क्रम में रु० 450 कर दिया जाएगा। द्वितीय विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर उसका वेतन रु० 480 से अधिक वृद्धि तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि वह अपनी सेवा के 4 वर्ष पूरे नहीं कर लेता अथवा अन्य आवश्यक समझी गई शर्तों को पूरा नहीं कर लेता। यदि कोई परिवीक्षाधीन लाल बहादूर शास्त्री प्रशासन अकादमी की “पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा” में उत्तीर्ण नहीं हुआ हो तो उसकी प्रथम वार्षिक वेतन-वृद्धि को, जिस तारीख को यह मिली होती उससे एक वर्ष के लिए अथवा विभागीय विनियमों के अधीन दूसरी वार्षिक वेतन वृद्धि अर्जित होने की तारीख तक, दोनों में से जो पहले हो रोक दिया जाएगा।

(iv) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर नियुक्ति से पूर्व, मौलिक आधार पर सावधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थायी पद पर नियुक्त था उसका वेतन मूल नियम 22 ख (I) की व्यवस्थाओं के अधीन विनियमित होगा।

(ड) सरकार इस सेवा के किसी भी सदस्य को किसी विशिष्ट अवधि तक, संघ राज्य क्षेत्र की प्रचार संगठन में किसी पद पर रख सकती है।

(च) सरकार, किसी अधिकारी को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अन्तर्गत किसी भी संगठन में किसी क्षेत्रीय पद पर रख सकती है।

(छ) जहां तक छुट्टी पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है केन्द्रीय सरकार सूचना सेवा के अधिकारियों को श्रेणी I और श्रेणी II के अन्य अधिकारियों के समान समझा जायेगा।

टिप्पणी :—परिवीक्षाधीनों को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिये कि उनकी नियुक्ति केन्द्रीय सूचना सेवा के गठन में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा आवश्यक समझ कर किए जाने वाले प्रत्येक परिवर्तन के अधीन होंगी और इस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप उन्हें किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा।

5. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा।

6. भारतीय सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क।

7. भारतीय रक्षा लेखा सेवा।

(क) नियुक्ति परख पर की जाएगी जिसकी अवधि 2 वर्ष की होगी। परन्तु यह अवधि बढ़ाई जा सकती है यदि परखाधीन अधिकारी न निर्धारित परीक्षाएं पास करके, अपने आपको पक्का किए जाने (Confirmation) के योग्य सिद्ध न किया हो। यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाएं पास करने में लगातार असफल होता रहा तो उसकी नियुक्ति खत्म कर दी जायेगी।

(ख) यदि, यथा-स्थिति सरकार या नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की राय में, परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण असन्तोषजनक हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की सम्भावना हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकती है।

(ग) परख अवधि के समाप्त होने पर, यथा स्थिति, सरकार या नियन्त्रक और महालेखा परीक्षा अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है/सकता है या यदि यथा-स्थिति सरकार या नियन्त्रक और महालेखा-परीक्षक की राय में उसका कार्य या आचरण असन्तोषजनक रहा हो तो उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती/सकता है या उसकी परख अवधि को जितना उचित समझे, बढ़ा सकती/सकता है परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगह पर की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में पक्का करने का दावा नहीं किया जा सकेगा।

(घ) लेखा परीक्षा के लेखा सेवा से अलग किये जाने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा में परिवर्तन हो सकते हैं। और कोई उम्मीदवार जो इस सेवा के लिए चुना जाय इस परिवर्तन से होने वाले परिणाम के आधार पर कोई दावा नहीं करेगा और उन्हें अलग किये गये केन्द्रीय और राज्य सरकार और नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक के अन्तर्गत साविधिक लेखा परीक्षा कार्यालय में काम करना पड़ेगा और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अन्तर्गत अलग किए गए लेखा कार्यालयों के संवर्ग में अन्तिम रूप से रहना होगा/पड़ेगा।

(ङ) भारतीय रक्षा लेखा सेवा के अधिकारियों से भारत में कहीं भी सेवा ली जा सकती है और उन्हें क्षेत्र-सेवा (फील्ड सर्विस) पर भारत में या भारत से बाहर भी भेजा जा सकता है।

(ख) वेतनमान—

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा—

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का समय-मान—

रु० 400-400-450-30-510-द० रो०-700-40-1100-50/2-1250 ।

जूनियर प्रशासनिक ग्रेड—रु० 1300-60-1600 ।

महालेखापाल—रु० 1800-100-2000-125—2250 ।

अपर उप नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक ग्रेड-1 2500-125/2-2,750 रु० ।

भारत के उप नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक—3000 रु० ।

नोट 1—परखाधीन अधिकारियों की सेवा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के समय-मान में कम से कम वेतन से प्रारम्भ होगी और वेतन वृद्धि के प्रयोजन से उनकी सेवा कार्यग्रहण की तारीख से गिनी जायेगी ।

नोट 2—परखाधीन अधिकारियों का 400 रु० से ऊपर का वेतन तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि वे समय-समय पर विहित नियमों के अनुसार विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर लेंगे ।

नोट 3—परखाधीन अधिकारियों की सेवा, ग्रेड II के समय-मान में कम-से-कम वेतन से प्रारम्भ होगी । यदि कोई परखाधीन अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो उसकी रु० 450 तक ले जाने वाली वेतन-वृद्धि एक साल के लिए उसकी वेतन-वृद्धि की तारीख स्थगित कर दी जायेगी अथवा विभागीय नियमों के अनुसार उसकी दूसरी वेतन-वृद्धि जब पड़ने वाली हो और इन दोनों में से जो पहले पड़े तब तक वेतन-वृद्धि स्थगित रहेगी ।

नोट 4—जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर नियुक्ति से पूर्व, मौलिक आधार पर सावधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थायी पद पर नियुक्त था उसका वेतन मूल नियम 22-ख (1) की व्यवस्थाओं के अधीन नियमित होगा ।

8. भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा-अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, रु० 400-400-450-30-क्लास 1, सहायक कलक्टर, केन्द्रीय 510-द० रो०-700-40-उत्पादन शुल्क, सहायक कलक्टर 1100-50/2-1250 । सीमा शुल्क ।

डिप्टी कलक्टर, सीमा शुल्क डिप्टी कलक्टर, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क । अतिरिक्त कलक्टर, अपिलेट कलक्टर, 1300-60-1600 ।

अपील कलक्टर, सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क-कलक्टर, रु० 1800-100-2000-सीमा शुल्क, कलक्टर केन्द्रीय 125-2250 । उत्पादन-शुल्क ।

(क) नियुक्तियां 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा के आधार पर की जायेंगी किन्तु यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी निर्धारित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण कर के स्थायीकरण का हकदार नहीं हो जाता तो 71GI/73—3

उक्त अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है । तीन वर्ष की अवधि में विभागीय प्रतियोगिताओं को उत्तीर्ण न कर लेने पर नियुक्ति रद्द भी की जा सकती है ।

(ख) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य अथवा आचरण संतोषजनक नहीं है उसके सक्षम अधिकारी बनने की संभावना नहीं है तो सरकार उसे तुरन्त सेवा-मुक्त कर सकती है ।

(ग) परिवीक्षाधीन अधिकारी का परिवीक्षाकार पूर्ण होने पर सरकार उसकी नियुक्ति को स्थायी कर सकती है अथवा यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा है तो सरकार या तो उसे सेवा-मुक्त कर सकती है अथवा उसके परिवीक्षाकाल में अपनी इच्छानुसार वृद्धि कर सकती है किन्तु अस्थायी रिक्तियों पर नियुक्ति किये जाने पर स्थायीकरण सम्बन्धी उसका कोई दावा नहीं स्वीकार किया जायेगा ।

(घ) भारतीय सीमा-शुल्क तथा उत्पादन शुल्क सेवा क्लास 1 के अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में सेवा करनी होगी तथा भारत में ही "फील्ड सर्विस" भी करनी होगी ।

नोट 1—एक परिवीक्षाधीन अधिकारी को प्रारम्भ में रु० 400-400-450-30-510-द० रो०-700-40-1100-50/2-1250 के समय वेतन में न्यूनतम वेतन मिलेगा तथा वार्षिक वृद्धि के लिए अपने सेवा काल को वह कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से मानेगा ।

नोट 2—परिवीक्षाधीन अधिकारी को समय वेतन मान में रु० 400 से अधिक वेतन तब नहीं दिया जायेगा जब तक कि वह समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले नियमों के अनुसार निर्धारित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं कर लेता/लेती ।

नोट 3—जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर भारतीय सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन कर सेवा, श्रेणी 1 में नियुक्ति से पूर्व, मौलिक आधार पर सावधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थाई पद पर नियुक्त था उसका वेतन मूल्य नियम 22 ख (1) का व्यवस्थाओं के अधीन विनियमित होगा ।

नोट 4—परिवीक्षा की अवधि में अधिकारी को विभागीय प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, सीमा शुल्क विभाग मादक पदार्थ (नारकोटिक्स) विभाग में तथा बुनियादी पाठ्यक्रम प्रशिक्षण (फाउंडेशन कोर्स ट्रेनिंग) के लिए लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी मसूरी में नियुक्त किया जायेगा । मसूरी में प्रशिक्षण समाप्त कर लेने पर उसे "पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा" उत्तीर्ण करनी होगी । उसे विभागीय परीक्षा के खण्ड I और खण्ड II में भी सफलता प्राप्त करनी होगी । पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा और विभागीय परीक्षा के किसी एक खण्ड में उत्तीर्ण हो जाने के बाद उसका वेतन पहिली अग्रिम वेतन वृद्धि देकर रु० 450 कर दिया जाएगा विभागीय परीक्षा के दोनों खण्डों में उत्तीर्ण हो जाने पर उसका वेतन दूसरी अग्रिम वेतन वृद्धि देकर रु० 480 कर दिया जाएगा—वेतन में रु० 480 से अधिक वृद्धि तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि वह अपनी सेवा के चार वर्ष पूरे नहीं कर लेता अथवा अन्य आवश्यक समझी जाने वाली शर्तों को पूरा नहीं कर लेता ।

यदि कोई परीक्षाधीन अधिकारी "पाठ्यक्रम संपूर्ण परीक्षा" उत्तीर्ण नहीं करता तो उसके प्रथम अग्रिम वेतन वृद्धि को, जिस तारीख से वह मिली होती उससे एक वर्ष के लिए अथवा विभागीय विनियमों के अधीन दूसरी अग्रिम वेतन-वृद्धि अर्जित होने की तारीख तक, दोनों में से जो भी पहले हो, रोक दिया जायगा।

नोट 5—परीक्षाधीन अधिकारियों को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि उनकी नियुक्ति भारतीय सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा, क्लास I के गठन में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा आवश्यक समझ कर किए जाने वाले प्रत्येक परिवर्तन के अधीन होगी और इस प्रकार के परिवर्तन के फल-स्वरूप उन्हें किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

भारतीय रक्षा लेखा सेवा :

समय-मान—

र० 400-400-450-480-५० र०-700-40-1100-1100-1150-1150-1200-1200-1250।

जूनियर प्रशासनिक ग्रेड—

र० 1300-60-1600।

र० 1600-100-1800 (सेलेक्शन ग्रेड)

सीनियर प्रशासनिक ग्रेड—

र० 1800-100-2000-125-2250।

रक्षा लेखा महानियंत्रक —र० 2750 (नियत)।

रक्षा लेखा महानियंत्रक—

नोट 1—परखाधीन अधिकारियों की सेवा, समयमान में कम-से-कम वेतन से प्रारम्भ होगी और वेतन वृद्धि के प्रयोजन से, उनकी कार्यग्रहण की तारीख से गिनती की जायेगी।

उसका वेतन मूल नियम 22-ख(1) की व्यवस्थाओं की अधीन विनियमित होगा जो सरकारी कर्मचारी परीक्षा के आधार पर नियुक्ति से पूर्व, मौलिक आधार पर सावधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थायी पद पर नियुक्त था।

नोट 2—परखाधीन अधिकारियों को 400 रुपये से ऊपर का वेतन तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार विभागीय परीक्षा पास नहीं कर लेंगे, इसके अलावा यदि कोई भी अधिकारी जो लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा नहीं पास करता उसकी पहली वेतन-वृद्धि जो उसे विभागीय परीक्षा का खण्ड पास कर लेने पर प्राप्त होती उसकी तिथि एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जायेगी अथवा खण्ड II पास कर लेने के बाद जो उसे दूसरी वेतन वृद्धि मिलती और इन दोनों में जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी।

6. भारतीय आयकर सेवा श्रेणी I—(क) नियुक्ति परख पर की जायगी जिसको अवधि 2 वर्ष की होगी। परन्तु वह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है, यदि परखाधीन अधिकारी, निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास करके अपने आपको पक्का किए जाने (Confirmation) के योग्य सिद्ध न कर सके। यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाएं पास करने में लगातार अपकृत होता रहा तो उसकी नियुक्ति खत्म कर दी जायगी।

(ख) यदि सरकार की राय में, परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण असंतोषजनक हो या उसे देखते हुए उसके कार्य-कुशल होने की सम्भावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है।

(ग) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या यदि सरकार की राय में, उसका कार्य या आचरण असंतोषजनक रहा हो तो उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है, परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में, पक्का करने का दावा नहीं किया जा सकेगा।

(घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियां करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी है तो वह अधिकारी ऊपर के खण्डों में उल्लिखित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

(ङ) वेतनमान—

आयकर अधिकारी, श्रेणी I—

र० 400-400-450-30-510-५० र०-700-40-1100-50/2-1250।

आयकर सहायक आयुक्त —र० 1300-60-1600।

आयकर के अपर आयुक्त—

र० 1600-100-1800।

आयकर आयुक्त —र० 1800-100-2000-125-2250।

परखाधीन अवधि में अधिकारी को लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकादमी, मसूरी तथा आयकर प्रशिक्षण कालेज, नागपुर में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। मसूरी में प्रशिक्षण समाप्त होने पर उसे पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास करनी होगी। इसके अतिरिक्त परखाधीन अवधि में विभागीय परीक्षा खण्ड I और खण्ड II भी पास करने होंगे पाठ्यक्रमान्त परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा खण्ड I पास कर लेने पर वेतन बढ़ाकर, 450 र० कर दिया जायगा। विभागीय परीक्षा खण्ड II पास कर लेने पर वेतन बढ़ाकर र० 480 कर दिया जाएगा। र० 480 के स्तर के ऊपर वेतन तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उस अधिकारी की सेवा 4 वर्ष पूरी न हो चुकी हो या दूसरी ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो आवश्यक समझा जाएगा।

यदि वह एकादमी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं कर लेता तो एक वर्ष के लिए उसकी वेतन वृद्धि स्थगित कर दी जाएगी अथवा उस तारीख तक जब कि विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे दूसरी वेतन वृद्धि मिलने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी।

नोट 1—परखाधीन अधिकारी को 400 र० से ऊपर का वेतन तब तक नहीं मिलेगा जब तक वह समय-समय पर विहित नियमों के अनुसार विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर लेगा।

नोट 2—परखाधीन अधिकारियों को भलीभांति समझ लेना चाहिए कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा आया-कर सेवा श्रेणी 1 के गठन में किए जाने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन से प्रभावित हो सकेगी जो कि समय-समय पर उचित समझे जाने के बाद भारत सरकार द्वारा किया जायेगा और वह उस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिकर का दावा नहीं कर सकेगी।

9. भारतीय आर्डनेन्स फैक्टरी सेवा श्रेणी I (गैर तकनीकी संलग्न)

(क) चुने हुए उम्मीदवार, सहायक प्रबंधक (परखाधीन) के रूप में नियुक्त किये जायेंगे परख की अवधि 2 वर्ष होगी जिसे आर्डनेन्स फैक्ट्रियों के महा-निदेशकों की सिफारिश पर सरकार द्वारा कम अथवा अधिक किया जा सकेगा। सहायक प्रबंधक (परखाधीन) को सरकार द्वारा दिया जाने वाला कोई भी प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, और सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली विभागीय तथा भाषा परीक्षाएं भी देनी पड़ सकती हैं। भाषा परीक्षाओं में हिन्दी की परीक्षा शामिल होगी। परख की अवधि समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर देगी। किन्तु यदि परख की अवधि के दौरान या उसके अन्त में उसका कार्य तथा आचरण सरकार के विचार में असंतोषजनक रहा हो, तो सरकार चाहे तो उसे सेवा से निकाल सकेगी और चाहे उसकी परख की अवधि को उतनी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जितनी वह ठीक समझे। किन्तु सेवा समाप्ति के आदेश देने से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारी को उन कारणों से अवगत कराया जायेगा। जिनके आधार पर उसे सेवा मुक्त करने का विचार किया गया और उसके विरुद्ध कारण बताने का अवसर दिया जायेगा।

(ख) भारतीय आर्डनेन्स फैक्टरी सेवा में सहायक प्रबंधक (परखाधीन) 400-400-450-30-600-35-670-६० रो०-35-950 रु० के निर्धारित वेतन क्रम में वेतन प्राप्त करेंगे, परख की अवधि के दौरान उन्हें विभाग की विभिन्न शाखाओं में और मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी में एक आधारित पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। पाठ्य-क्रमान्त परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा पास करने पर उन्हें अग्रिम वेतन वृद्धि प्राप्त करने का अधिकार होगा जिससे उनका वेतन पहली तथा दूसरी विभागीय परीक्षा के अंतिम पत्र की तारीख से बढ़ा कर 450 रु० और 480 रु० प्रतिमास हो जायेगा। आगे वेतन वृद्धियों का विनियमन समय मान के अन्तर्गत उनकी स्थिति के अनुसार तथा उनके उस ग्रेड में स्थायी किये जाने के बाद होगा।

यदि कोई सहायक प्रबंधक (परखाधीन) लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्ष के लिये अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत दूसरी वेतन वृद्धि प्राप्त होने वाली हो, इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी।

(ग) (1) चुने हुए उम्मीदवारों को यदि उस से कहा जाय तो, सशस्त्र सेना में, यदि प्रशिक्षण में कोई अवधि लगी हो तो ऐसी अवधि को मिलाकर कम से कम चार वर्ष की अवधि के लिए सेवा करनी पड़ेगी, किन्तु ऐसे व्यक्ति को (1) नियुक्ति की तारीख से 10 वर्ष गुजरने के बाद उपर्युक्त सेवा नहीं करनी होगी और (2) चालीस वर्ष हो जाने के बाद उपर्युक्त सेवा नहीं करनी होगी।

(2) इन उम्मीदवारों पर रखा सेवाओं में सिविलियन (क्षेत्र सेवा उत्तरदायित्व) नियम, 1957 भी लागू होंगे जो 9 मार्च, 1957 को का० अ० नि० सं० 92 के अधीन प्रकाशित हुए थे। उनमें दिये गये स्वास्थ्य मानकों के अनुसार उनकी स्वास्थ्य परीक्षा की जायेगी।

(घ) उनको दिये जाने वाले वेतन क्रम इस प्रकार है :—

कनिष्ठ वेतन मान

सहायक प्रबंधक तकनीकी स्टाफ अधिकारी	400-400-450-30-600-35-670-६० रो०-35-950 रु०
वरिष्ठ वेतन मान	
उप प्रबंधक/उपसहायक महानिदेशक आर्डनेन्स फैक्टरी	700-40-1100-50/2-1250 रु०।
प्रबंधक/वरिष्ठ उपसहायक महानिदेशक आर्डनेन्स फैक्टरी।	1100-50-1400 रु०
उप महाप्रबंधक/सहायक महानिदेशक आर्डनेन्स फैक्टरी ग्रेड-2	1300-60-1600-100-1800 रु०
सहायक महानिदेशक आर्डनेन्स फैक्टरी ग्रेड-1	1800-100-2000 रु०
उप महानिदेशक आर्डनेन्स फैक्टरी	2000-125-2250 रु०

10. भारतीय डाक सेवा

(क) चुने हुए उम्मीदवारों को इस विभाग में प्रशिक्षण लेना होगा जिसकी अवधि, आमतौर पर दो वर्ष से अधिक नहीं होगी। इस अवधि में इन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।

(ख) यदि सरकार की राय में, किसी प्रशिक्षणाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की सम्भावना न हो तो सरकार उसे तात्काल सेवा मुक्त कर सकती है।

(ग) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या यदि सरकार की राय में उसका कार्य आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है, परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में पक्का करने का दावा नहीं किया जा सकेगा।

(घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियाँ करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी ऊपर के खण्डों में उल्लिखित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

वेतनमान

समय-मान 400-400-450-30-510-द० रो०-700-40-1100-50/2-1250 (प्रशिक्षणाधीन अधिकारी इस समय-मान में वेतन लेंगे)।

डाक सेवा निदेशक : 1300-60-1600।

महापोस्ट मास्टर : रु० 1800-100-2000-115-2250।

सवस्य डाक तार बोर्ड : रु० 2250-125/2-2750।

वरिष्ठ सवस्य डाक तार बोर्ड : रु० 3000।

(च) भारतीय डाक सेवा श्रेणी-I के परखाधीन अधिकारी रु० 400-400-450-30-480-510-द० रो०-700-40-1100-50/2-1250 के निश्चित मान में अपना वेतन प्राप्त करेंगे। परखाधीन अवधि में उस विभाग को विभिन्न शाखाओं तथा लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकादमी मसूरी के आधारभूत पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण लेना पड़ेगा-मसूरी में प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास करनी होगी। विभागीय नियमों के अन्तर्गत विहित विभागीय परीक्षाएं भी इन्हें पास करनी होंगी।

पाठ्यक्रमान्त परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा पास कर लेने पर उनके वेतन बढ़ा कर रु० 450 कर दिया जाएगा। दो वर्ष की परखाधीन अवधि समाप्त कर लेने और स्थायी किए जाने के बाद उनका वेतन 480 के स्तर पर निश्चित कर दिया जाएगा। समय-मान के अन्तर्गत उनकी स्थिति के अनुसार इस के बाद उनका वेतन निश्चित होता रहेगा।

यदि कोई परखाधीन अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकादमी मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन-वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाएगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे जब दूसरी वेतन वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में जो भी अवधि पहले पड़े, तब तक स्थगित रहेगी।

जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर नियुक्ति से पूर्व, मौलिक आधार पर सावधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थायी पद पर नियुक्त था, उसका वेतन मूल नियम 22(ख)(1) की व्यवस्थाओं के अधीन विनियमित होगा।

(छ) परखाधीन अधिकारियों को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय डाक सेवा श्रेणी-1 के गठन में किए जाने

वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन से प्रभावित हो सकेगी जो कि समय-समय पर उचित समझे जाने के बाद, भारत सरकार द्वारा किया जाएगा और वे इस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिकर का दावा नहीं कर सकेंगे। चुने हुए उम्मीदवारों को, सरकार निर्देशानुसार सैन्य डाक सेवा के अंतर्गत भारत अथवा विदेश में कार्य करना होगा।

11. भारतीय रेलवे लेखा सेवा

(क) नियुक्ति परख पर की जाएगी, जिसकी अवधि 2 वर्ष की होगी। इस अवधि में दोनों में से किसी भी ओर से तीन महीने का नोटिस सेवा देकर समाप्त की जा सकेगी, परख अवधि बढ़ाई जा सकेगी, यदि परखाधीन अधिकारी निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास करके अपने आपको पक्का करने के योग्य सिद्ध नहीं कर देगा सरकार ऐसे परखाधीन अधिकारी की नियुक्ति खत्म कर सकती है जो अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष के भीतर सभी विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर लेता।

(ख) भारतीय रेलवे लेखा सेवा के परखाधीन अधिकारियों को भी रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ौदा में प्रशिक्षण लेना होगा और कालेज प्राधिकाारियों द्वारा निर्धारित परीक्षा पास करनी होगी। इस कालेज में परीक्षा देना अनिवार्य है और एक बार असफल होने पर दूसरा अवसर मिल सकता है जब कि अपवादिक परिस्थितियाँ हों और अधिकारी का कार्य ऐसा हो कि उसे यह छूट दी जा सकती हो। हालांकि, दो वर्ष का प्रशिक्षण संतोषजनक रूप से पूरा करने पर, उन्हें किसी कार्यकारी पद (Working Post) पर लगाया जा सकता है। परन्तु उन्हें तब तक पक्का नहीं किया जाता जब तक कि वे रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ौदा की परीक्षा और ऊंची तथा नीची विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर लेते।

(ग) परखाधीन अधिकारियों को देवनागरी लिपि में हिन्दी की अनुमोदित स्तर की एक परीक्षा पहले ही या परखावधि में पास कर लेनी चाहिए। यह परीक्षा या तो गृह मंत्रालय की ओर से शिक्षा निदेशालय, दिल्ली द्वारा संचालित 'प्रवीण' हिन्दी परीक्षा हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा हो। किसी भी परखाधीन अधिकारी को तब तक पक्का नहीं किया जा सकता या उसका वेतन 450 रु० नहीं किया जा सकता जब तक कि वह परीक्षा पास नहीं कर लेता। ऐसा न करने पर सेवा समाप्त की जा सकती है। इसमें कोई छूट नहीं दी जा सकती।

- (घ) इन नियमों के अनुसार भर्ती किए गए भारतीय रेलवे लेखा-सेवा अधिकारी के (परखाधीन) भी (क) पेंशन के लाभों के पात्र होंगे, और (ख) समय-समय पर संशोधित राज्य रेलवे भविष्य निधि (अंशदान रहित) के नियमों के अंतर्गत इस निधि में अभिदान कर सकेंगे।
- (ङ) इन नियमों के अधीन भर्ती किए गए अधिकारी समय-समय पर लागू उदार बनाए गए छुट्टी के नियमों के अनुसार छुट्टी के पात्र होंगे। परन्तु, वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, छुट्टी के नियमों में परिवर्तन किए जा सकते हैं। उन्हें वर्तमान छुट्टी नियमों को अपनाए रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि सरकार ऐसा निर्णय करेगी।
- (च) यदि किसी ऐसे कारण से जो कि उसके वश के बाहर न हो, भारतीय रेलवे लेखा सेवा का कोई परखाधीन प्राधिकारी परख या प्रशिक्षण में ही छोड़ना चाहें तो उसे अपने प्रशिक्षण का सारा खर्च और परख-अवधि में उसे दी गई सब रकमें वापस करनी होंगी।
- (छ) यदि सरकार की राय में, किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की सम्भावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है।
- (ज) परख अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है। या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है, या उसकी परख-वधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

(1) वेतन-मान :—

- (क) जूनियर :—रु० 400-400-450-30-600-35-670-द० रो०-35-950 (प्राधिकृत मान)।
सीनियर :—रु० 700 (छटे वर्ष या पहले) 40-1100 50/2-1250 (प्राधिकृत मान)।
जूनियर प्रशासनिक ग्रेड :—रु० 1300-60-1600- (प्राधिकृत मान)।
इंटरमीडियेट प्रशासनिक ग्रेड :—रु० 1600-100-1800।
सीनियर प्रशासनिक ग्रेड :—रु० 2000-100-2,500।
- (ख) यदि परखाधीन अधिकारी अपनी दो वर्ष की परख अवधि में निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर सकेगा तो रु० 400 से रु० 450 तक की उसकी वेतन-वृद्धि रोक दी जाएगी और परख-अवधि बढ़ा दी जाएगी। जब वह विभागीय परीक्षाएं पास कर लेगा और उसके बाद जब पक्का कर दिया जाएगा, तो अन्तिम विभागीय परीक्षा

समाप्त होने की तारीख के बाद अगले दिन से पक्का वेतन समय-मान में उस अवस्था (Stage) पर नियत कर दिया जाएगा जो उसे अन्यथा मिला होता पर उसे वेतन का बकाया नहीं मिलेगा। ऐसे मामलों में, भावी वेतन वृद्धियों की तारीख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

परख-अवधि में परखाधीन अधिकारी ज्यों ही, निर्धारित परीक्षाएं पास कर लेगा, त्यों ही उसको रु० 400-950 के जूनियर मान में रु० 400 से रु० 450 और रु० 450 से रु० 480 की, अग्रिम वृद्धियां मिल सकेंगी। अग्रिम वृद्धियां मिलने के बाद, सेवा के वर्ष को ध्यान में रखते हुए अधिकारी का वेतन, वेतनमान में उसकी सामान्य स्थिति के अनुसार विनियमित कर दिया जाएगा।

यदि कोई परखाधीन अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रम परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन वृद्धि प्राप्त हो तो उस तारीख से एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाएगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे जब दूसरी वेतन-वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े, तब तक स्थगित रहेगी।

नोट 1 :—परखाधीन अधिकारियों की सेवा जूनियर मान में कम से कम वेतन से प्रारम्भ होंगे और वेतन-वृद्धि के प्रयोजन से, वह उनकी कार्यग्रहण की तारीख से गिनी जाएगी। परन्तु उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा या परीक्षाएं पास करनी होंगी और उसके बाद ही उनका वेतन समयमान में रु० 400 प्रति मास से रु० 450 प्रति मास किया जा सकेगा।

नोट 2 :—तथापि, जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति से पहले सांविधिक पद के अतिरिक्त अन्य स्थायी पद पर मूल रूप से कार्य करता था, उसका वेतन नियम 2018 व (1) नियम II (मू० ति० 22-ख), में दिए गए उपबन्धों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

12. सैनिक भूमि और छावनी (सेवा श्रेणी I और श्रेणी II)

- (क) (i) नियुक्ति के लिए चुना गया उम्मीदवार परख पर रखा जाएगा जिनकी अवधि आमतौर पर 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी। इस अवधि में उसे छावनी और भूमि प्रशासन में सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा, जिसकी अवधि छः महीने से कम नहीं होगी।
- (ii) तथापि, जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति से पहले सांविधिक पद के अतिरिक्त अन्य स्थायी पद पर मूल रूप से कार्य करता था, उसका वेतन एफ० आर० 22-ख (I) में दिए गए उपबन्धों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

- (ख) परख-अवधि में उम्मीदवार को निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी :

(ग) (1) यदि सरकार की राय में परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की सम्भावना न हो, तो सरकार उसे सेवा-युक्त कर सकती है, परन्तु सेवा-मुक्ति का आदेश देने से पहले, उसे सेवा-मुक्ति के कारणों से अवगत कराया जाएगा और लिख कर "कारण बताने" का अवसर भी दिया जाएगा।

(ii) यदि परख अवधि की समाप्ति पर, अधिकारी के उपर उप-पैरा (ख) में उल्लिखित विभागीय परीक्षा पास न की हो तो सरकार अपने निर्णय से या तो उसे सेवा-मुक्त कर सकती है या यदि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, उसकी परख-अवधि बढ़ानी आवश्यक हो तो वह जितना उचित समझे, परख-अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा सकती है।

(iii) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है। परन्तु सेवा-मुक्ति का आदेश देने के पहले, अधिकारी को सेवा-मुक्ति के कारणों से अवगत कराया जाएगा और लिख कर "कारण बताने" का अवसर भी दिया जाएगा।

(घ) यदि उप-पैरा (ग) के अन्तर्गत सरकार ने कोई कार्य-वाई नहीं की तो निर्धारित परख-अवधि के बाद की अवधि में अधिकारी की नियुक्ति मास-प्रति-मास मानी जाएगी और दोनों में से किसी भी ओर से एक कलेंडर मास का लिखित नोटिस देकर समाप्त की जा सकेगी, परन्तु अधिकारी पक्का करने का दावा नहीं कर सकेगा।

(ङ) इस सेवा के सदस्य को उसकी परख-अवधि में वार्षिक वेतन-वृद्धि देय हो जाने पर भी, तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि वह विभागीय परीक्षा पास न कर लेगा। जो वृद्धि इस प्रकार नहीं मिली होगी, वह विभागीय परीक्षा पास करने की तारीख से मिला जाएगी।

(च) यदि कोई परखाधीन अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन-वृद्धि से प्राप्त होगी, इस तारीख से एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाएगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे जब दूसरी वेतन-वृद्धि प्राप्त होने वाली हो, और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े, तब तक स्थगित रहेगी।

(छ) वेतनमान इस प्रकार है:—

प्रशासनिक पद

- (i) निदेशक, सैनिक भूमि और छावनियां।
र० 1800-100-2000-125-22 50।
- (ii) संयुक्त निदेशक, सैनिक भूमि और छावनियां
र० 1600-100-1800।
- (iii) उपनिदेशक, सैनिक भूमि और छावनियां।
र० 1300-60-1600।
- (iv) सहायक निदेशक सैनिक भूमि और छावनियां।
र० 1100-50-1400।

श्रेणी-I

- (v) उप-सहायक निदेशक 400-400-450—
सैनिक भूमि और 30-510-द० र०
छावनियां, सैनिक 700-40-1100-50/2-
संपदा अधिकारी और 1250।
कार्यापालक अधिकारी

श्रेणी-II

- (vi) कार्यापालक अधिकारी। 350-25-500—
30-590-द० र०—
30-800-द० र०
830-35-900।
- (vii) सहायक सैनिक संपदा 350-25-500—30-
अधिकारी। 590-द० र० 30-
800-द० र०—830
35-900।

(ज) (i) श्रेणी I के अधिकारियों को, सामान्यतया उप-सहायक निदेशक, सैनिक संपदा अधिकारी श्रेणी I और श्रेणी II की उन छावनियों में कार्यपालक अधिकारी के पदों पर नियुक्त किया जाएगा जिन पर छावनी अधिनियम 1924 की धारा-13 की उप-धारा (4) के खण्ड (ङ) का उप-खण्ड (1) लागू होता है;

(ii) श्रेणी II के कार्यपालक अधिकारियों को सामान्यतया, उन छावनियों में नियुक्त किया जाएगा जो उपर (i) में उल्लिखित नहीं हैं।

(झ) (i) सभी पदोन्नतियां, इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गई विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के अनुसार, सरकार द्वारा चुन कर (By Selection) की जाएगी [वरीयता (सीनियरिटी) पर तभी विचार किया जाएगा जब कि दो या अधिक उम्मीदवारों के दावे गुणों की दृष्टि से बराबर होंगे]। श्रेणी-II से श्रेणी-I में पदोन्नति होने पर, वेतन, मूल नियमावली (Fundamental Rules) के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

(ii) साधारणतया, किसी भी अधिकारी को श्रेणी I से तब तक पदोन्नत नहीं किया जाएगा जब तक कि श्रेणी-2 में उसकी तीन वर्ष की सेवा पूरी न हो गई हो।

(अ) समय-समय पर संशोधित, पुनरीक्षित छुट्टी नियमावली, 1933 लागू होगी।

(ट) इस सेवा का कोई भी सदस्य, सरकार से पहले मंजूरी लिए बिना कोई भी ऐसा काम अपने जिम्मे नहीं लेगा जो कि उसके सरकारी काम से सम्बन्धित न हो।

(ठ) सैनिक भूमि और छावनी सेवा के अधिकारियों से भारत में कहीं भी सेवा ली जा सकती है और उन्हें क्षेत्र-सेवा (Field Service) पर भी भारत से किसी भी भाग में भेजा जा सकता है।

13. भारतीय रेलवे यातायात सेवा

(क) नियुक्ति के लिए चुने गये उम्मीदवारों को भारतीय रेलवे यातायात सेवा में परखाधीन अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाएगा : उनकी परख-अवधि तीन वर्ष की होगी। इस अवधि में, उन्हें पैरा (ड) में उल्लिखित प्रशिक्षण लेना होगा और कम-से-कम एक वर्ष तक किसी कार्यकारी पद पर काम करना होगा। यदि किसी मामले संतोषजनक रूप से प्रशिक्षण पूरा न करने के कारण, प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाई जाएगी तो उसके अनुसार, परख की कुल अवधि भी बढ़ जाएगी।

(ख) यदि किसी ऐसे कारण से, जो कि उसके वश के बाहर न हो, भारतीय रेलवे यातायात सेवा का परखाधीन अधिकारी परख या प्रशिक्षण बीच में ही छोड़ना चाहे तो उसे अपने प्रशिक्षण का सारा खर्च और परख-अवधि में उसे दी गई सब रकमें वापस करनी होंगी।

(ग) इस सेवा में नियुक्तियां परख पर की जाएंगी, जिसकी अवधि तीन वर्ष की होगी। इस अवधि में दोनों में से किसी भी ओर से तीन महीने का नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी। परखाधीन अधिकारियों को पहले दो वर्ष तक व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। जो अधिकारी इस प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक समाप्त कर लेंगे और अन्यथा भी उपयुक्त समझे जाएंगे उन्हें कार्यकारी पद का कार्यभार सौंप दिया जाएगा, यदि उन्होंने निर्धारित विभागीय और अन्य परीक्षाएं पास कर ली हों। ध्यान रहे कि वे परीक्षाएं नियमित; प्रथम प्रयास में ही पास कर ली जाएं। क्योंकि विशेष (एक्सेप्शनल) परिस्थितियों को छोड़, बाकी किसी भी हालत में, दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। किसी परीक्षा में असफल होने के परिणामस्वरूप, परखाधीन अधिकारी की सेवा समाप्त की जा सकती है और उनको वेतन-वृद्धि तो हर हालत में रुक ही जाएगी। किसी कार्यकारी पद पर एक वर्ष तक कार्य करने के बाद परखाधीन अधिकारियों को एक अन्तिम

परीक्षा पास करनी होगी। यह परीक्षा व्यावहारिक सैद्धांतिक दोनों प्रकार की होगी। जब परखाधीन अधिकारी सब तरह से नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे जायेंगे तो उन्हें पक्का कर दिया जाएगा। जिन मामलों में किसी कारण से परख-अवधि बढ़ाई गई हो, उनमें विभागीय परीक्षाएं पास करने और पक्का होने पर, समय-समय पर लागू होने वाले नियमों और आदेशों के अनुसार पहली और बाद की वेतन-वृद्धि ली जा सकेंगी।

(घ) परखाधीन अधिकारियों को, देवनागरी लिपि में अनुमोदित स्तर की हिन्दी की एक परीक्षा पहले ही परख-अवधि में पास कर लेनी चाहिए। यह परीक्षा या तो गृह मंत्रालय की ओर से शिक्षा निदेशालय, दिल्ली, द्वारा संचालित "प्रवीण" हिन्दी परीक्षा हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा हो।

किसी भी परखाधीन अधिकारी को तब तक पक्का नहीं किया जा सकता या उसका वेतन 450 रु० नहीं किया जा सकता जब तक कि वह यह परीक्षा पास नहीं कर लेता। ऐसा न करने पर सेवा समाप्त की जा सकती है। इसमें कोई छूट नहीं दी जा सकती।

(ङ) इन नियमों के अनुसार भर्ती किए गए भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी (परखाधीन) भी :—

(क) रेलवे पेंशन नियम द्वारा शासित होंगे और

(ख) समय-समय पर संशोधित, राज्य रेलवे भविष्य निधि (अंशदान रहित) के नियमों के अन्तर्गत इस निधि में अभिदान कर सकेंगे।

(च) कार्यग्रहण की तारीख से ही वेतन प्रारम्भ होगा। वेतन-वृद्धि के प्रयोजन से भी सेवा उसी तारीख से गिनी जाएगी।

(छ) इन नियमों के अधीन भर्ती किए गए अधिकारी समय-समय पर लागू उदार छुट्टी नियमों के अनुसार छुट्टी के पात्र होंगे।

(ज) अधिकारियों को आम तौर पर, उनकी सेवा की अवधि पर उसी रेलवे में रखा जाएगा जिसमें वे सर्वप्रथम नियुक्त कर दिए जाएंगे। और किसी अन्य रेलवे में स्थानान्तरित होने के लिए साधिकार दावा नहीं कर सकेंगे। परन्तु भारत सरकार को वह अधिकार है कि वह उन अधिकारियों को, सेवा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, भारत में या भारत से बाहर किसी परियोजना (Project) या रेलवे में स्थानान्तरित कर सके।

(अ) वेतन-मान :—

जूनियर —र० 400-400-450-30-600-35-670-

र० 35-950 (प्राधिकृत मान) ।

सीनियर—र० 700 (छठे वर्ष या पहले)—40-1100-50/2-1250 (प्राधिकृत मान) ।

जूनियर प्रशासनिक ग्रेड—र० 1300-60-1600- (प्राधिकृत मान) ।

इंटरमीडिएट प्रशासनिक ग्रेड—र० 1600-100-1800 (प्राधिकृत मान) ।

सीनियर प्रशासनिक ग्रेड—र० 2,000-100-2,500 (प्राधिकृत मान) ।

नोट 1—परखाधीन अधिकारियों की सेवा जूनियर मान में कम-से-कम वेतन से प्रारम्भ होगी और वेतन-वृद्धि के प्रयोजन से, वह उनकी कार्य-ग्रहण की तारीख से गिनी जायेगी । परन्तु उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा या परीक्षाएं पास करनी होंगी । और उसके बाद ही उनका वेतन-मान में र० 400 प्रतिमास से र० 450 प्रतिमास किया जा सकेगा ।

यदि परखाधीन अधिकारी अपने परख और प्रशिक्षण की अवधि के पहले दो वर्षों में, विभागीय परीक्षाएं, पास नहीं कर सकेगा तो र० 400 से 450 तक की उसकी वेतन-वृद्धि रोक दी जाएगी और परख-अवधि बढ़ा दी जाएगी । जब यह विभागीय परीक्षाएं पास कर लेगा और उसके बाद जब पक्का हो जाएगा तो अन्तिम विभागीय परीक्षा समाप्त होने की तारीख के बाद, अगले दिन से उसका वेतन समय-समय में उस अवस्था पर नियत कर दिया जाएगा जो उसे अन्यथा मिला होता पर उसे वेतन का बकाया नहीं मिलेगा । ऐसे मामलों में, भावी वेतन-वृद्धियों की तारीख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

परख-अवधि में, परखाधीन अधिकारी ज्यों ही निर्धारित परीक्षाएं पास कर लेगा, त्यों ही उसको र० 400 से 950 के जूनियर मान में र० 400 से र० 450 और र० 450 से र० 480 की अग्रिम वृद्धि मिल सकेगी । अग्रिम वृद्धियां मिलने के बाद सेवा के वर्ष को ध्यान में रखते हुए अधिकारी को वेतनमान में उसकी सामान्य स्थिति के अनुसार, विनियमित कर दिया जायेगा ।

यदि कोई परखाधीन अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकादमी मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख की उसे पहले वेतन-वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाएगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उससे जब दूसरी वेतन-वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी ।

नोट 2—जो सरकारी कर्मचारी परीक्षा के आधार पर अपनी नियुक्ति से पहले किसी सांविधिक पद के अतिरिक्त स्थाई आधार पर किसी स्थाई पर काम कर चुका है उसका वेतन नियम 2018 क(1) आर० 2 [एफ० 22-ख (1)] में की गई व्यवस्थाओं के अनुसार निर्धारित किया जाएगा ।

(इ) वेतन-वृद्धि केवल अनुमोदित सेवा के लिए ही और विभाग के नियमों के अनुसार ही दी जायेगी ।

(ट) प्रशासनिक ग्रेडों में पदोन्नति, स्वीकृति (Establishment) स्थापना में खाली जगहों होने पर ही की जायेगी और पूर्ण

रूप से चुना (Selection) के आधार पर ही की जायेगी । एकमात्र वरीयत के आधार पर ही ऐसा पदोन्नति के लिए दावा नहीं किया जा सकता ।

(ठ) भारतीय रेलवे यातायात सेवा के परखाधीन अधिकारियों के प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम ।

नोट 1—जिन उम्मीदवारों ने भारत में या और कहीं प्रशिक्षण या अनुभव पहले कभी प्राप्त कर रखा हो, उसके मामले में भारत सरकार को अपने निर्णय के अनुसार प्रशिक्षण-अवधि घटाने का अधिकार है ।

नोट 2—परखाधीन अधिकारियों को भी रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ौदा में दो दौर में प्रशिक्षण लेना होगा । इस कालेज में परीक्षा देना अनिवार्य है और एक बार असफल होने पर दूसरा अवसर तभी मिल सकता है जबकि आपवादिक परिस्थितियां हों और अधिकारी का कार्य अभिलेख ऐसा हो कि उसे यह छूट दी जा सकती है । परीक्षा में असफल होने पर परखाधीन अधिकारियों की सेवा समाप्त की जा सकेगी, उनके प्रशिक्षण और परख की अवधि आवश्यकतानुसार बढ़ा दी जाएगी और उन्हें किसी भी हालत में तब तक पक्का नहीं किया जाएगा जब तक कि वे परीक्षाएं पास नहीं कर लेंगे ।

नोट 3—नीचे जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम दिया गया है वह मुख्य रूप से मार्ग-दर्शन के प्रयोजन से बनाया गया है । इसमें महाप्रबन्धकों द्वारा अपने निर्णय के अनुसार स्थिति-विशेष को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन किए जा सकते हैं परन्तु सामान्य-तया प्रशिक्षण की कुल अवधि घटाई नहीं जानी चाहिए ।

नोट 4—प्रशिक्षण के दौरान परीक्षाधीन अधिकारी को गार्ड, यार्ड मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर, यार्ड फोरमैन, ट्रेन परीक्षक, सहायक लोको फोरमैन, सहायक नियन्त्रक आदि की हैसियत से कार्य करना होगा जिसका विवरण नीचे दिया गया है । प्रशिक्षण की समाप्ति के बाद जब परीक्षा अधिकारी को किसी कार्यकारी पद पर तैनात किया जाता है तो उसे अपने कार्य करने के लिए यात्रा करनी होगी पड़ती है तथा यात्रा के दौरान रास्ते के स्टेशनों पर "पड़ाव" की कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं । उसे दुर्घटना स्थलों की जांच के किसी भी समय जाना पड़ता है तथा नियन्त्रण कार्यालयों (Control Offices) और स्टेशनों का निरीक्षण करना पड़ता है । इस सब के लिए बहुत परिश्रम अपेक्षित होता है तथा रात को भी काम करना पड़ता है ।

(1) पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष

मद	अवधि (सप्ताह)
1. लाल बहादुर शास्त्री प्रशिक्षण अकादमी, मसूरी	17
2. रेलवे बड़ौदा स्टाफ कालेज (प्रथम दौर)	12
3. क्षेत्रीय स्कूल, गार्ड के कर्तव्य सीखने के लिये (प्रथम दौर)	4
4. गार्ड के रूप में कार्य करते हुए	3
5. बुकिंग/पार्सल आफिस गुड्स ग्रेड तथा ट्रांस- शिपमेंट रोड	10

यातायात लेखा तथा लेखाओं का यांत्रिक-निरीक्षक	5
7. क्षेत्रीय स्कूल में सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्य सीखने के लिये (द्वितीय दौर)	4
8. यार्ड मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर, याथर्ड फोरमैन तथा ट्रेनपरीक्षक के रूप में कार्य करते हुये	13
9. सहायक लोको फोरमैन के रूप में कार्य करते हुए	1
10. सहायक नियंत्रक	4
11. उप सहायक नियंत्रक विद्युत नियंत्रक का प्रशिक्षण	6
12. बड़ौदा स्टाफ कालिज (द्वितीय दौर)	6
13. पूर्वी रेलवे में प्रशिक्षण	
(i) कोल पाइलट का कार्य करते हुए 1. 5 सप्ताह	
(ii) अन्दाज और आसनसोल यार्ड कम्पेक्स का कार्य इसमें दुर्गापुर इस्पात कारखाना भी शामिल है	2. 5
(ख) धनबाद डिवीजन	
(i) कोयला अर्बटन की कार्याविधि इसमें पेह और करनपुरा जैसे यार्डों तथा पेह और दुगदा वाशरीज तक के क्षेत्रों का दौरा करना होगा	2
(ii) क्षेत्रीय कोयला अधीक्षक के कार्यालय का कार्य	
(ग) मुगलसराय मार्शलिंग यार्ड साथ ही भन्दुआ-दीह—देहरी ओनसन तक दौरे भी करने होंगे	1
14. दक्षिण पूर्वी रेलवे में प्रशिक्षण	
(i) चक्रधरपुर डिवीजन—बोडामुंडा यार्ड राउरकेला इस्पात कारखाना—इसके साथ साथ कैपटिव माइन्स के दौरे	1. 5
(ii) विलासपुर डिवीजन भिलाई मार्शलिंग यार्ड, भिलाई इस्पात कारखाना तथा चीरीमीरी और महेन्द्र-गढ़ कोयला खानों के क्षेत्रों का दौरा	1. 5
15. रेलवे जिसमें आवंटित किया गया—उसमें प्रशिक्षण	
(क) मुख्य कार्यालय (संचालन)	4. 00
(ख) मुख्य कार्यालय (वाणिज्यिक)	4. 00
(ग) विभिन्न प्रकार के परिक्षण के लिये यात्रा समय तथा अतिआवश्यक छुट्टी के लिये रखी गई समयावधि	2. 5
कुल	104 सप्ताह या 24 महीने

(2) यदि परखाधीन अधिकारी अपने दो वर्ष के प्रशिक्षण के अन्त में परीक्षा पास कर लेगा तो उसे अगले एक वर्ष के लिए किसी कार्यकारी पद का भार परख पर सौंप दिया जाएगा।

(3) परीक्षा, आवश्यकता अनुसार, पाठ्यक्रम पूरा होने पर तथा प्रशिक्षणअवधि में निश्चित समय पर ली जाएगी।

नोट—किसी परखाधीन अधिकारी को, स्वतन्त्र रूप से गार्ड, सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर, यार्ड फोरमैन, सहायक लोकोमोटिव फोरमैन या सहायक नियंत्रक का काम सौंपने से पहले यह आवश्यक है कि प्रशासन के किसी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा उक्त प्रत्येक पद के कार्य के सम्बन्ध में उसकी परीक्षा ली जाए और योग्य घोषित किया जाए।

14. दिल्ली और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा-ध्रेणी-II।

(क) नियुक्ति परख पर की जायेगी जिसकी अवधि दो वर्ष होगी और उस सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार बढ़ाई भी जा सकेगी। परख पर नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं देनी होंगी।

(ख) यदि सरकार की राय में, किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्य-कुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवामुक्त कर सकती है।

(ग) जब यह घोषित कर दिया जायेगा कि अमुक अधिकारी ने संतोषजनक रूप से अपनी परख-अवधि समाप्त कर ली है तो उसे सेवा में पक्का कर दिया जायेगा यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

(घ) उस सेवा के अधिकारी को, दिल्ली प्रशासन या अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह में इन क्षेत्रों में शासन/सरकार के अन्तर्गत सेवा करनी होगी।

(ङ) वेतनमान :—

ग्रेड I (सिलेक्शन ग्रेड)	₹ 1000 (नियत)
ग्रेड II समयमान	₹ 350-25-500-30-590-द० रो०-30-800

किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर भर्ती किये जाने वाले व्यक्ति को सेवा में नियुक्ति पर समय वेतनमान का न्यूनतम वेतन प्राप्त होगा, बशर्ते यदि वह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप से सार्वधिक पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था, सेवा में परीक्षा की अवधि में उसका वेतन मूल नियम 22-ख (1) के परन्तुक के अधीन विनियमित किया जायेगा। सेवा में नियुक्त किए गए अन्य व्यक्तियों के लिए वेतन और वेतन-वृद्धियां मूल नियमों के अनुसार विनियमित होंगी।

(च) सेवा के अधिकारियों को परिणोदित केन्द्रीय वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सरकार की दरों पर महंगाई भत्ता प्राप्त करने का हक होगा।

(छ) भूगर्भ भत्ता के अतिरिक्त, इस सेवा के अधिकारियों को प्रतिकर (नगर) भत्ता, किराया भत्ता, और पहाड़ी स्थानों तथा सुदूर स्थानों में रहने-सहन के बड़े हुए खर्च को पूरा करने के लिए अन्य भत्ते दिए जायेंगे, यदि उन्हें झुटी पर या प्रशिक्षण के लिए ऐसे स्थानों पर भेजा जायेगा और जिन स्थानों के लिए भत्ते अनुमत्य होंगे।

(ज) इस सेवा के अधिकारियों पर दिल्ली, और अण्डमान निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा नियमावली, 1971, और इस नियमावली को लागू करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली हिदायतें अथवा बनाये जाने वाले अन्य विनियम लागू होंगे। जो मामले विशिष्ट रूप से उक्त नियमों का विनियमों अथवा उनके अन्तर्गत दिये गये आदेशों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते, उनमें ये अधिकारी, उन नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे जो संघ के कार्यों से सम्बन्धित सेवा करने वाले तदनु रूप (corresponding) अधिकारियों पर लागू होते हैं।

15. केन्द्रीय सचिवालय सेवा अनुभाग अधिकारी, ग्रेड, श्रेणी-II

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में इस समय निम्नलिखित ग्रेड हैं :—

ग्रेड	वेतनमान
सलैक्शन ग्रेड उप-सचिव या समकक्ष	₹० 1100-50-1300-60-1600-100-1800
ग्रेड-1 अवर सचिव	₹० 900-50-1250
अनुभाग अधिकारी ग्रेड-1	₹० 350-25-500-30-590-₹० १०-30-800-₹० १०-30-830-35-900 ।
सहायक ग्रेड	₹० 210-10-270-15-300-₹० १०-15-450-₹० १०-20-530 ।

सलैक्शन ग्रेड और ग्रेड का नियन्त्रण अखिल सचिवालय आधार पर मन्त्रिमंडल सचिवालय कार्मिक विभाग करता है और अनुभाग अधिकारी/सहायक ग्रेड मन्त्रालय द्वारा नियन्त्रित किए जाते हैं।

केवल अनुभाग अधिकारी ग्रेड और सहायक ग्रेड में ही सीधी भर्ती की जाती है।

(ख) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों को दो वर्ष तक परख पर रखा जाएगा। इस परख अवधि में उनको सरकार के द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी, यदि परखाधीन अधिकारी प्रशिक्षण-अवधि में पर्याप्त न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सके तो उन्हें सेवा-मुक्त कर दिया जाएगा।

(ग) परख-अवधि समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो सरकार उसे

या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे बढ़ा सकती है।

(घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्ति करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी उपर्युक्त खण्डों में वर्णित सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

(ङ) अनुभाग अधिकारी को सामान्यतया "अनुभागों" का अध्यक्ष बनाया जाएगा और ग्रेड-I के अधिकारियों को, सामान्यतया शाखाओं का कार्य भार सौंपा जाएगा जिनमें एक या अधिक अनुभाग होंगे।

(च) अनुभाग अधिकारी, इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ग्रेड-1 में पदोन्नति पा सकेंगे।

(छ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 के अधिकारी, केन्द्रीय सचिवालय में सलैक्शन ग्रेड की सेवा में और अन्य ऊंचे, प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति पाने के पात्र होंगे।

(ज) जहां तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की छुट्टी, पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है, वे अन्य श्रेणी-I और II के अधिकारियों के समान ही समझे जाएंगे।

16. सीमा-शुल्क मूल्यांकन सेवा, क्लास II

(क) मूल्यांकन ग्रेड में ₹० 350-25-500-30-590-₹० १०-30-800-₹० १०-830-35-900 के वेतनमान में भर्ती की जाती है। नियुक्तियां दो वर्ष के लिए परीवीक्षा के आधार पर की जाती हैं। तथा परीवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी, यदि चाहे तो, बढ़ा भी सकता है। परीवीक्षा काल में उम्मीदवारों को केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा तथा विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी। उन्हें ₹० 375 से ऊपर का वेतन तब तक नहीं लेने दिया जाएगा जब तक वे निर्धारित विभागीय परीक्षा पूर्ण रूप से पास नहीं कर लेते।

(ख) यदि परीवीक्षा की मूल अथवा परिवर्द्धित अवधि की समाप्ति पर नियुक्ता प्राधिकारी यह समझता है कि चयन किया गया उम्मीदवार स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं है अथवा परीवीक्षा की उक्त मूल अथवा परिवर्द्धित अवधि के दौरान प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि उम्मीदवार परीवीक्षा की अवधि की समाप्ति पर स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं होगा तो वह उसे सेवा से अलग कर सकता है अथवा जो उचित समझे, वह आदेश दे सकता है।

(ग) परीवीक्षा की अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने पर तथा विभागीय परीक्षाएं पास कर लेने के बाद अधिकारियों को संबद्ध ग्रेड में स्थायी करने पर विचार किया जायेगा।

(घ) मूल्यांकन लागू नियमों के अनुसार भारतीय सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क-सेवा, श्रेणी-1 (400/1250 ₹०) के अलग उच्च ग्रेड में पदोन्नति के पात्र होंगे।

(ङ) अयकाण, पेंशन आदि के मामले में इन अधिकारियों पर केन्द्रीय सरकार के अन्य क्लास-II अधिकारियों पर लागू होने वाले नियम ही लागू होंगे। जहां तक उनकी सेवा की अन्य

शर्तों का प्रश्न है, उन पर सीमा-शुल्क मूल्यांकन सेवा, क्लास-II, की भरती नियमावली की व्यवस्थाएं लागू होंगी। इन नियमों में यह विशेष रूप से निर्दिष्ट है कि इस सेवा के अधिकारियों को "केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क बोर्ड" के अधीन किसी भी सामान या उच्च पद पर भारत में कहीं भी तैनात किया जा सकता है।

17. दिल्ली और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा श्रेणी-II

(क) नियुक्ति परख पर की जायेगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी और उस सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार बढ़ाई भी जा सकेगी। परख पर नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं देनी होंगी।

(ख) यदि सरकार की राय में, किसी परखाधीन अधिकारी का-कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्य-कुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है।

(ग) जब यह घोषित कर दिया जायेगा कि अमुक अधिकारी ने संतोषजनक रूप से अपनी परख-अवधि समाप्त कर ली है तो उसे सेवा में पक्का कर दिया जायेगा यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

(घ) उस सेवा के अधिकारी को, दिल्ली प्रशासन या अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह में इन क्षेत्रों में प्रशासन के अन्तर्गत सेवा करनी होगी।

(ङ) वेतनमान :—

ग्रेड I (सिलेक्शन ग्रेड)	₹० 900-50-1250।
ग्रेड II समय मान	₹० 400-25-500-30- 590-४० अ०-30-800-४० अ०-30-830-35-900।

किसी प्रतिभागिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर शर्तों किये जाने वाले व्यक्ति को सेवा में नियुक्ति पर समय वेतनमान का न्यूनतम वेतन प्राप्त होगा, बशर्ते यदि वह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप से सार्वधिक पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था, सेवा में परिवीक्षा की अवधि में उसका वेतन मूल नियम 22-ख (1) के परन्तुक के अधीन विनियमित किया जायेगा। सेवा में नियुक्त किए गए अन्य व्यक्तियों के लिए वेतन और वेतन-वृद्धियां मूल नियमों के अनुसार विनियमित होंगी।

(च) सेवा के अधिकारियों को परिपोषित केन्द्रीय वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सरकार की दरों पर महंगाई भत्ता प्राप्त करने का हक होगा।

(छ) महंगाई भत्ता के अतिरिक्त, इस सेवा के अधिकारियों को प्रतिकर (नगर) भत्ता, मकान किराया भत्ता, और पहाड़ी स्थानों तथा गुरूर स्थानों में रहन-सहन के बढ़े हुए खर्च को पूरा करने के लिए अन्य भत्ते दिये जाएंगे, यदि उन्हें ड्यूटी पर या प्रशिक्षण

के लिए ऐसे स्थानों पर भेजा जायेगा जिन स्थानों के लिए भत्ते अनुमत्य होंगे।

(ज) इस सेवा के अधिकारियों पर दिल्ली, और अण्डमान निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा नियमावली, 1971, और इस नियमावली को लागू करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली हिदायतें अथवा बनाये जाने वाले अन्य विनियम लागू होंगे। जो मामले विशिष्ट रूप से उक्त नियमों का विनियमों अथवा उनके अन्तर्गत दिये गए आदेशों या विषय आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते, उनमें ये अधिकारी उन नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे जो संघ के कार्यों से संबंधित सेवा करने वाले तदनुषंग (Corresponding) अधिकारियों पर लागू होते हैं।

18. रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा श्रेणी-II

(क) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में निम्नलिखित पद और वेतनमान है :—

सेवा	वेतनमान
(i) प्रवरण ग्रेड संयुक्त निदेशक/ उप-सचिव	₹० 1100-50-1300-60-1600-100-1800।
(ii) उप-निदेशक का ग्रेड	₹० 900-50-1250-200-वि० बे० प्रति मास।
(iii) सहायक निदेशक अवर सचिव	₹० 900-50-1250
(iv) अनुभाग अधिकारी	₹० 350-25-500-30-590-४० रो०-30-800-४० रो०-30-830-35-900।
(v) सहायक	₹० 210-10-270-15-300-४० रो०-15-150-४० रो०-20-530।

अनुभाग अधिकारियों और सहायकों के पदों पर सीधी भर्तियों की जाती है।

(ख) अनुभाग अधिकारियों के रूप में सीधे भर्तियाँ किये गये अधिकारियों को दो वर्ष तक परख पर रखा जायेगा। इस परख अवधि में उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी। यदि परखाधीन अधिकारी प्रशिक्षण-अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सके तो उन्हें सेवा-मुक्त कर दिया जायेगा।

(ग) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उन्हें या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

(घ) यदि सरकार ने नियुक्ति करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी ऊपर के खण्डों में वर्णित सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

(ङ) जिन अनुभाग अधिकारियों ने सचिवालय के अनुभागों में काम करके पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर रखा हो उनको सामान्यतया अनुभागों का अध्यक्ष बनाया जायेगा और सहायक निदेशक/अवर सचिव की सामान्यता शाखाओं का कार्यभार सौंपा जायेगा जिनमें एक या अधिक अनुभाग होंगे।

(च) अनुभाग अधिकारी, इस संबंध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार, सहायक निदेशक, अवर सचिव के रूप में पदोन्नति पा सकेंगे।

(छ) सहायक निदेशक/अवर सचिव रेलवे बोर्ड सचिवालय में ऊंचे पदों पर नियुक्ति पागे के लिए पात्र होंगे।

(ज) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा, रेलवे मंत्रालय तक ही सीमित है और इसके अधिकारी अन्य मंत्रालयों को स्थानान्तरित नहीं किये जा सकते जैसा कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी किये जा सकते हैं।

(झ) रेलवे मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारियों को, रेलवे अधिकारियों के समान ही, पास और सुविधा टिकट आदेश (Privilege ticket orders) लेने की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ञ) इन नियमों के अन्तर्गत भर्ती किये गये रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकारी (परबाधीन अधिकारी भी)।

(क) रेलवे पेंशन से अधिशासित होंगे, और

(ख) समय-समय पर संशोधित राज्य रेलवे भविष्य निधि (अंशदान-रहित) के नियमों के अन्तर्गत, इस निधि में अभिदान कर सकेंगे।

(ट) जहां तक छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकारियों को रेलवे के श्रेणी I और II के अन्य अधिकारियों के समान समझा जायेगा, परन्तु चिकित्सा असुविधाओं के मामले में, वे उन नियमों से शासित होंगे जो केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों पर लागू होते हैं जिनका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

19. भारतीय विदेश सेवा ग्रंथ 'बी०' सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड II तथा III, श्रेणी II (अनुभाग अधिकारी ग्रेड)।

(क) भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' (श्रेणी II) के सम्बन्धित ग्रेड II और III की अनुरक्षण रिक्तियों का 33 1/3 प्र० श० संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती भरी जाती है। इस ग्रेड का वेतनमान रु० 350-25-500-30-590-द० रो०-30-800-द० रो०-30-830-35-900 है।

(ख) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों को दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रखा जाएगा, जिस अवधि में उसको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी। यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण की अवधि में पर्याप्त प्रगति नहीं दिखाता तो उसे सेवा से हटाया जा सकता है। यदि वह पर्याप्त प्रगति दिखाता है तो उसे सेवा मुक्त कर दिया जाएगा।

(ग) परिवीक्षा की अवधि में समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी पद उपलब्ध होने पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार या तो उसे सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा की अवधि को उतना और बढ़ा सकती है जितना वह उचित समझे परिवीक्षा की कुल अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्त करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी उपर्युक्त खण्डों में निर्धारित सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

(ङ) इस सेवा में नियुक्त किए गए अधिकारी सामान्यतया अनुभागों के अध्यक्ष होंगे। विदेश मंत्रालय/विदेश व्यापार के मुख्यालय में कार्य करते समय उनके पद नाम अनुभाग अधिकारी और कभी-कभी प्रशासन अधिकारी होंगे। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में कार्य करते समय उनके पदनाम रजिस्ट्रार होंगे यद्यपि स्थानीय प्रयोजन के लिए राजनयिक हैसियत से उन्हें अटैची कहा जा सकता है।

(च) अनुभाग अधिकारी भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के ग्रेड 1 में रु० 900-50-1250 के वेतनमान में इस संबंध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार पदोन्नति के पात्र होंगे।

(छ) भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के ग्रेड 1 के अधिकारी बारी आने पर भारतीय विदेश सेवा (क) के धरिष्ठ वेतनमान वाले पदों पर नियुक्ति के लिए रु० 900 (छठा वर्ष या कम) 50-1000-60-1600-50-1800 के वेतन मान में इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार पात्र होंगे।

(ज) भारतीय विदेश सेवा, शाखा (ख) केवल विदेश मंत्रालय और विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए सीमित है और इस सेवा में नियुक्ति किए गए अधिकारी सामान्यतया विदेश व्यापार मंत्रालय को छोड़कर अन्य मंत्रालयों को स्थानान्तरित नहीं किए जा सकते हैं। तथापि, वे भारत के भीतर या बाहर सेवा के लिए कहीं भी भेजे जा सकते हैं।

(झ) भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियों को विदेश सेवा के समय उनके मूल वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर संस्वीकृत दरों पर विदेश भत्ता दिया जाता है जो सम्बन्धित देश में रहन-सहन के खर्च आदि पर आधारित होता है। इसके अतिरिक्त भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियों पर लागू किए गए रूप में भारतीय विदेश सेवा (पी० एल० सी० ए०) नियम, 1961, के अनुसार विदेशों में सेवा के समय विभाजित रियायतें भी मिलेंगी :—

(1) सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान के अनुसार मुफ्त सुराजित आवास।

- (ii) सहायता निश्चितता परिचर्या योजना के अधीन निश्चितता परिचर्या की सुविधायें ।
- (iii) भारत में किसी निगम सम्बन्धी की मृत्यु या बीमारी जैसी विशेष आपातक स्थितियों में, जिसकी व्याख्या सरकार करेगी, अधिकारी के पूरे सेवा-काल में अधिक से अधिक दो बार के लिये भारत के लिये और यहां से वापसी ड्यूटी के स्थान के लिये वापसी हवाई अड्डा के प्रिकट ।
- (iv) लम्बी छुट्टी के दौरान 8 और 21 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये जो भारत में अध्ययन कर रहे हैं अपने माता-पिता में मिलने के लिये कुछ शर्तों पर वार्षिक वापसी हवाई अड्डा के प्रिकट ।
- (v) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई दरों पर 5 वर्षों और 18 वर्षों के बीच की आयु के अधिकतम दो बच्चों की शिक्षा के लिये भत्ता ।
- (vi) विदेश सेवा के संबंध में निर्धारित नियमों के अनुसार और सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर सज्जा भत्ता असामान्य गरीब जलवायु वाले देशों में तैनात अधिकारियों को सामान्य सज्जा भत्ते के अलावा विशेष सज्जा भत्ता भी मिल सकता है ।
- (vii) निर्धारित नियमों के अनुसार अधिकारियों और उनके परिवारों के लिये गृह अवकाश किराया ।
- (ज) समय-समय पर यथा संशोधित परिशोधित अवकाश नियम, 1933, कुछ अपोषणों के साथ, इस सेवा के सदस्यों पर लागू होंगे । कुछ पड़ोसी देशों को छोड़ कर विदेश सेवा के लिये परिशोधित अवकाश नियमों के अधीन मिल सकने वाले अवकाश के अतिरिक्त जमा अवकाश का 50 प्रतिशत तक पाने के अधिकारी पात्र होंगे ।
- (ट) भारत में होने पर अधिकारी ऐसी सभी रियायतों के पात्र होंगे जो बराबर और सामान स्तर के अन्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिल सकते हैं ।
- (ठ) भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारी समय-समय पर यथा संशोधित सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवायें) नियम, 1960, और उनके अधीन जारी किये गये आदेशों द्वारा शासित होंगे ।
- (ड) इस सेवा में नियुक्त किये गये अधिकारी समय-समय पर यथा संशोधित उधार पेंशन नियम, 1930 और उन पर जारी किये गये आदेशों द्वारा शासित होंगे ।

20. गोवा, दमन और दियु सिविल सेवा, क्लास II

(क) नियुक्तियों दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के आधार पर की जायेंगी तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो बढ़ा भी सकेगा । परिवीक्षा के आधार पर नियुक्त उम्मीदवारों को गोवा, दमन तथा दियु संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा विभागीय परीक्षाएँ पास करनी होंगी ।

(ख) यदि प्रशासक की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का काम या आचरण संतोषजनक नहीं है अथवा उस से यह प्रकट होता है कि अधिकारी के सुयोग्य सिद्ध होने की संभावना नहीं है, तो प्रशासक उसे सेवा से तुरन्त अलग कर सकता है ।

(ग) जिस अधिकारी के लिये यह घोषित हो जायेगा कि उसने परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है, उसे सेवा में पुनर् प्रवेश दिया जायेगा । यदि प्रशासक की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा है तो वह उसे सेवा से अलग कर सकता है अथवा परिवीक्षा की अवधि, जितनी ठीक समझे, बढ़ा सकता है ।

(घ) इस सेवा के अधिकारी को गोवा, दमन तथा दियु संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी स्थान पर कार्य करना होगा ।

(ङ) वेतनमान —

ग्रेड I (चयन ग्रेड) — र० 700-40-1100-50/2-1250

ग्रेड II — र० 350-25-500-30-590-द० रो०—
30-800-द० रो०—30-830-35-900

किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर भर्ती किये जाने वाले व्यक्ति को, सेवा में नियुक्ति पर समय वेतनमान का न्यूनतम वेतन प्राप्त होगा वरन्त यदि वह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप से सांघिक पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था, सेवा में परिवीक्षा की अवधि में उसका वेतन मूल नियम 22-ख (1) में परंतुक के अधीन विनियमित किया जायेगा । सेवा में नियुक्त किये गये अन्य व्यक्तियों के लिये वेतन और वेतन वृद्धियाँ मूल नियमों के अनुसार विनियमित होंगी ।

इस सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955, के अनुसार भारतीय प्रशासन सेवा के सीनियर वेतनमान के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे ।

(च) इस सेवा के अधिकारियों पर गोवा, दमन, तथा दियु, सिविल सेवा नियमावली, 1967, तथा इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिये बनाये गये तथा अन्य विनियम या प्रशासक द्वारा जारी किये गये आदेश लागू होंगे ।

21. पांडिचेरी सिविल सेवा-क्लास II

(क) नियुक्तियों दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के आधार पर की जायेंगी तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो बढ़ा भी सकेगा परिवीक्षा के आधार पर नियुक्त उम्मीदवारों को पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा विभागीय परीक्षाएँ पास करनी होंगी ।

(ख) यदि प्रशासक की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का काम या आचरण संतोषजनक नहीं है अथवा उससे यह प्रकट होता है कि अधिकारी के सुयोग्य सिद्ध होने की संभावना नहीं है, तो प्रशासक उसे सेवा से तुरन्त अलग कर सकता है।

(ग) जिस अधिकारी के लिये यह घोषित हो जायेगा कि उसने परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है, उसे सेवा में पुष्ट कर दिया जायेगा, यदि प्रशासक की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा है तो वह उसे सेवा से अलग कर सकता है अथवा परिवीक्षा की अवधि, जितनी ठीक समझे, बढ़ा सकता है।

(घ) इस सेवा के अधिकारी को पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी स्थान पर कार्य करना होगा।

(ङ) वेतनमान :—

ग्रेड I — रु० 375-25-800।

किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर भर्ती किया जाने वाला व्यक्ति, को सेवा में नियुक्ति पर समय वेतनमान का न्यूनतम वेतन प्राप्त होगा बशर्ते यदि वह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप से सांविधिक पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था, सेवा में परिवीक्षा की अवधि में उसका वेतन मूल नियम 22-ख (1) के परंतुका के अधीन विनियमित किया जायेगा। सेवा में नियुक्त किये गये अन्य व्यक्तियों के लिये वेतन और वेतन वृद्धियां मूल नियमों के अनुसार विनियमित होंगी।

इस सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के अनुसार भारतीय प्रशासन सेवा के सीनियर वेतनमान के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे।

(च) इस सेवा के अधिकारियों पर पांडिचेरी सिविल सेवा नियमावली, 1967, तथा इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिये बनाये गये अन्य विनियम या प्रशासक द्वारा जारी किये गये आदेश लागू होंगे।

22. सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा अधीक्षक ग्रेड श्रेणी-II

(क) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में फिलहाल निम्नलिखित ग्रेड हैं :—

ग्रेड	वेतनमान
(1) संयुक्त निदेशक (श्रेणी-I)	रु० 1300-60-1600
(2) वरिष्ठ सिविलियन स्टाफ अधिकारी (श्रेणी-I)	रु० 1100-50-1400
(3) सिविलियन स्टाफ अधिकारी (श्रेणी I)	रु० 740-30-850-1150
(4) सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी (श्रेणी II) राज-पत्रित	रु० 350-25-500-30-590-रु० 10-30-800।
(5) सहायक (श्रेणी-II)-अराज-पत्रित	रु० 210-10-270-15-300-रु० 10-15-450-रु० 10-20-530

उपरोक्त सेवा सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय की अंतरसेवा संगठनों के लिये कर्मचारियों की आवश्यकता का पूर्ति करती है।

सीधी भर्ती केवल अधीक्षक ग्रेड तथा सहायक ग्रेड ही में की जाती है।

(ख) अधीक्षक ग्रेड 2 वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। इस अवधि के दौरान उन्हें ऐसे कोई भी प्रशिक्षण, प्राप्त करने अथवा परीक्षाओं पास करनी पड़ सकती हैं, जिनकी सरकार व्यवस्था करे। प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति न होने अथवा परीक्षाओं में उत्तीर्ण न हो पाने के फलस्वरूप परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा से निकाल दिया जायेगा।

(ग) परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने पर सरकार चाहे तो संबंधित अधिकारी को उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दे अथवा यदि उसका कार्य अथवा आचरण सरकार के विचार में संतोषजनक न रहा हो तो चाहे तो उसे सेवा से निकाल दे या परिवीक्षा की अवधि को उतने काल तक के लिये बढ़ा दे जितना सरकार उचित समझे।

(घ) यदि सेवा में नियुक्तियां करने का अधिकार सरकार द्वारा किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाये तो वह अधिकारी उपरोक्त धाराओं में बरिगर्त सरकार की शक्तियों में से किसी का भी प्रयोग कर सकता है।

(ङ) सशस्त्र सेवा मुख्यालय तथा प्रतिरक्षा विभाग के अन्तर सेवा संगठनों में अधीक्षक सामान्यतः 'अनुभागों' मुखिया होंगे जबकि सिविलियन स्टाफ अधिकारी एक या एकाधिक अनुभागों का कार्यभार सम्भालेंगे।

(च) अधीक्षक समय-समय पर तत्सम्बन्धी प्रचलित नियमों के अनुसार सिविलियन स्टाफ अधिकारी ग्रेड में पदोन्नति के हकदार होंगे।

(छ) सशस्त्र सेवा मुख्यालय सिविल सेवा के सिविलियन स्टाफ अधिकारी समय-समय पर तत्सम्बन्धी प्रचलित नियमों के अनुसार सेवा के वरिष्ठ सिविलियन स्टाफ अधिकारी ग्रेड में तथा अन्य प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के हकदार होंगे।

(ज) जहां तक छुट्टी, पेंशन तथा सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है उनका नियंत्रण सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के अधिकारी समय-समय पर प्रतिरक्षा सेवाओं के व्यय में से वेतन पाने वाले अधिकारियों के लिये लागू विनियमों तथा आदेशों द्वारा होगा।

परिशिष्ट IV

उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम

टिप्पणी 1.—ये विनियम उम्मीदवारों की सुरक्षा के लिये प्रकाशित किये जाते हैं और इसलिये प्रकाशित किये जाते हैं ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि उनका शारीरिक स्तर पर अपेक्षित स्तर तक का है। इन अधिनियमों का यह भी ध्येय है कि स्वास्थ्य परीक्षकों को ऐसे उम्मीदवारों को जो अधिनियमों में निर्धारित न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण न करता हो स्वास्थ्य परीक्षकों द्वारा आरोग्य घोषित न हो जाय मार्ग दर्शा सकें। तथापि, यह जानते हुए

कि उम्मीदवार इन अधिनियमों में दी हुई शर्तों के अनुसार अयोग्य नहीं है स्वास्थ्य बोर्ड को आज्ञा होगी कि भारत सरकार को स्पष्ट रूप से कारण लिख कर सिफारिश करें किन से वह बिना अनुविधा के सेवा में भर्ती किया जा सकता है।

2. तथापि, यह भी स्पष्टतया समझ लेना चाहिये कि स्वास्थ्य बोर्ड को रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् भारत सरकार को किसी भी उम्मीदवार को स्वीकार करने तथा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार है।

1. नियुक्ति के योग्य ठहराये जाने के लिये यह जरूरी है कि उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उम्मीदवार में कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिसे नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम करने में बाधा पड़ने की संभावना हो।

2. (क) भारतीय (एंग्लो-इंडियन समेत) जाति के उम्मीदवारों के आयु, कद और छाती के घेर के परस्पर संबंध के बारे में मेडिकल बोर्ड के ऊपर ही वह बात छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवारों की परीक्षा में मार्ग-दर्शन के रूप में जो भी परस्पर संबंध के आंकड़े सबसे अधिक उपयुक्त समझे, व्यवहार में लाये। यदि वजन, कद और छाती के घेर में विषमता हो तो जांच के लिये उम्मीदवार को अस्पताल में रखना चाहिये और छाती का एक्स-रे लेना चाहिये। ऐसा करने के बाद ही बोर्ड उम्मीदवार को योग्य अथवा अयोग्य करेगा।

विभिन्न सेवाओं का वर्गीकरण दो श्रेणियों "तकनीकी तथा अतकनीकी" के अधीन इस प्रकार से होगा :—

क—तकनीकी

(1) रेलवे इंजीनियरी सेवा (सिविल, विद्युत यांत्रिक तथा सिग्नल) भारतीय रेलवे यातायात सेवा, विशेष श्रेणी रेलवे अप्रेंटिस, और समुद्री विभाग के पद।

(2) केंद्रीय इंजीनियरी श्रेणी I और II तार इंजीनियरी श्रेणी I, विद्युत इंजीनियरी वर्ग I और II, भारत सर्वेक्षण, श्रेणी I और II समुद्रपार संचार सेवा की इंजीनियरी शाखा की श्रेणी I और II के पद पूर्ति और निपटान के महानिदेशक के निरीक्षण स्कन्ध के श्रेणी I और II के तकनीकी अधिकारी।

(3) भारतीय वन सेवा।

(4) भारतीय पुलिस सेवा।

आई० ए० एस०, आई० एफ० एस०, आई० ए० और ए० एस०, भारतीय सीमा-शुल्क सेवा, भारतीय रेलवे लेखा सेवा, भारतीय रेलवे भंडार सेवा, रेलवे सुरक्षा दल। रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा श्रेणी I और II और रेलवे में श्रेणी I और II के सभी अन्य पद भारतीय रक्षा लेखा सेवा आयकर अधिकारी (श्रेणी I ग्रेड II और श्रेणी II) सेवा, भारतीय डाक सेवा (श्रेणी I) सैनिक भूमि और छावनी सेवा, श्रेणी I और II, भारत भूविज्ञान सर्वेक्षण विभाग श्रेणी I और II, बेतार योजना तथा समन्वय संगठन के श्रेणी I और II के तकनीकी अधिकारी।

(ख) निश्चित सेवाओं के लिये कद और छाती के घेर का कम-से-कम मान नीचे दिया जाता है जिस पर पूर्ण न उतरने पर उम्मीदवार को मंजूर नहीं किया जा सकता।

	कद	छाती का घेर (पूरा फीटा कर)	फैलाव
	में० मी०	में० मी०	में० मी०
1. भारतीय रेल यातायात सेवा—			
(पुरुषों के लिये)	152	84	5
(स्त्रियों के लिये)	150	79	5
2. भारतीय पुलिस सेवा—			
दिल्ली, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा, श्रेणी-II			
(पुरुषों के लिये)	165	84	5
(स्त्रियों के लिये)	150	79	5

"गोरखा, गढ़वाली, असमी, नागालैंड, आदिम जातियों आदि से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम निर्धारित कद की लम्बाई में छूट दी जा सकेगी जिनकी औसत कद की लम्बाई दूसरों से छोटी होती है।"

3. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि से नापा जायेगा :—

वह अपने जूते उतार देगा और उसे माप-दंड (स्टैंडर्ड) से इस प्रकार सटा कर खड़ा किया जायगा कि उसके पांव आपस में जुड़े रहें और उसका वजन, सिवाय एड़ियों के पांवों की उंगलियों या किसी और हिस्से पर न पड़े। वह बिना अकड़ सीधा खड़ा होगा। और उसकी एड़ियां पिंडलियां नितंब और कंधे मापदंड के साथ लगें होंगे। उसकी ठोड़ी नीची रखी जायेगी ताकि सिर का स्तर (बटम आफ दि हैड लेवल) हारिजेंटल बार (आड़ी छड़) के नीचे आ जाय। कद सेंटीमीटरों और आधे सेंटीमीटरों में मापा जायेगा।

(4) उम्मीदवार की छाती नापने का तरीका इस प्रकार है :—

उसे इस भांति सीधा खड़ा किया जायगा कि उसके पांव जुड़े हों और उसकी भुजायें सिर से ऊपर उठी हों। फीते को छाती के गिर्द इस तरह लगाया जायगा कि पीछे की ओर इसका ऊपरी किनारा असफलक (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोणों (इन्फीरियर-एंगल्स) से लगा रहे और यह फीते को छाती के गिर्द ले जाने पर उसी आड़े समतल (हारिजेंटल प्लेन) में रहे फिर भुजाओं को नीचे किया जायगा और इन्हें शरीर के साथ लटका रहने दिया जायगा किन्तु इस बात का ध्यान रखा जायगा कि कंधे ऊपर या पीछे की ओर न किये जाए जिससे कि फीता न हिले। अब उम्मीदवार को कई बार गहरा सांस लेने के लिये कहा जायगा और छाती का अधिक-से-अधिक

फैलाव और से नोट किया जायगा और कम-से-कम और अधिक-से-अधिक फैलाव मीट्रीमीटरों में रिकार्ड किया जायगा, 84-89, 86-93.5 आदि नाम को रिकार्ड करने समय आधे मीट्रीमीटर से भिन्न फोतन को नोट नहीं करना चाहिये।

नोट :—अन्तिम निर्णय लेने से पहले उम्मीदवारों की ऊँचाई और छाती दो बार नापनी चाहिये।

5. उम्मीदवार का वजन भी लिया जायगा और उसका वजन किलोग्रामों में रिकार्ड किया जायगा। आधे किलोग्राम से कम के फेक्शन को नोट नहीं करना चाहिये।

6. (क) उम्मीदवार की नजर की जांच निम्नलिखित नियमों के अनुसार की जायगी। प्रत्येक जांच का परिणाम रिकार्ड किया जायेगा।

(ख) चश्मे के बिना नजर (नेकेड आई विजन) की कोई न्यूनतम सीमा (मिनिमम लिमिट) नहीं होगी, किन्तु प्रत्येक केस में मेडिकल बोर्ड या अन्य मेडिकल प्राधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जायगा क्योंकि इससे आँख की हालत के बारे में मूल सूचना (बेसिक इन्फार्मेशन) मिल जायेगी।

(ग) विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिये चश्मे के साथ और चश्मे के बिना दूर और नजदीक की नजर का मानक निम्नलिखित होगा :

सेवा की श्रेणी	दूर की नजर	नजदीक की नजर
	अच्छी खराब	अच्छी खराब
	आँख आँख	आँख आँख
	(ठीक की हुई दृष्टि)	(ठीक की हुई दृष्टि)।

आई० ए० एस०, आई० पी० एस० तथा केंद्रीय सेवायें :—

श्रेणी I और II और।

(i) तकनीकी	6/6	6/12	जे०-I	जे०-II
		या		
		6/9	6/9	

(ii) गैर तकनीकी—

(क) आई० ओ०				
एफ० एस०				
श्रेणी-I को				
छोड़ कर				
अन्य सेवायें	6/9	6/12	जे०-I	जे०-II

(ख) आई० ओ०				
एफ० एस०				
श्रेणी-I	6/6	6/18	जे०-I	जे०-II
	या			
	6/9	6/9		

(घ) (i) उपर्युक्त तकनीकी सेवाओं और लोक सुरक्षा से सम्बन्धित कोई अन्य सेवाओं के सम्बन्ध में (सिलिडर मिलाकर) मायोपिया कुल—4.00 डी० (प्लस) से अधिक नहीं हो। हाइपरमेट्रोपिया की कुल (सिलिडर मिलाकर) 4.00 डी० (प्लस) से अधिक नहीं होना चाहिये।

(ii) आँखों की परीक्षा करने में, पाँच परीक्षा की जानी चाहिये और उसका परिणाम रिकार्ड किये जाने चाहिये। व्याधिकृत द्वारा रोज़र होने पर जो कि बहु सकती है। और उम्मीदवार की दक्षता पर प्रभाव डाल सकता है उसे अयोग्य घोषित किया जाय।

(ऊ) दृष्टिक्षेत्र—सभी सेवाओं के लिये सम्मुखन विधि (कन्फेक्शन मैथड) द्वारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की जाएगी। तब ऐसी जांच का नतीजा असन्तोषजनक या संदिग्ध हो तब दृष्टिक्षेत्र की परिभाषी (पैरामीटर) पर निर्धारित किया जाना चाहिये।

(घ) रतौंधी (नाइट ब्लाइन्डनेस)—साधारणतया रतौंधी दो प्रकार की होती है (1) विटामिन “ए” की कमी होने के कारण, और (2) रेटीना के शारीरिक रोग के कारण रेटीनोइटिस पिगमेंटोसा होता है। जिसका सामान्य कारण ऊपर बताई गई (1) की स्थिति में फंडस में प्रसामान्य होता है, साधारणतया छोटी आयु वाले व्यक्तियों में और कम खुराक पाने वाले व्यक्तियों में दिखाई देता है और अधिक मात्रा में विटामिन “ए” के खाने से ठीक हो जाता है। ऊपर बताई गई (2) की स्थिति में फंडस में खराबी होती है और अधिकांश मामलों में केवल फंडस की परीक्षा से ही स्थिति का पता चल जाता है। उस श्रेणी का रोगी प्रौढ़ होता है और खुराक की कमी से पीड़ित नहीं होता है। सरकार में उंची नौकरियों के लिये प्रयत्न करने वाले व्यक्ति इस वर्ग में आते हैं।

उपर्युक्त (1) और (2) दोनों के लिये अंधेरा अनुकूलन परीक्षा से स्थिति का पता चल जायगा। उपर्युक्त (2) के लिये विशेषतया जब फंडस खराब न हो तो इलैक्ट्रो-रेटीनोग्राफी किये जाने की आवश्यकता होती है। इन दोनों जांचों में (अंधेरा अनुकूलन और रेटीनोग्राफी) में समय अधिक लगता है और विशेष प्रबन्ध और सामान की आवश्यकता होती है और इसलिए साधारण चिकित्सक जांच के लिए यह समय नहीं है। अतकनीकी बातों को ध्यान में रखते हुए मन्त्रालय/विभाग को चाहिए कि वे बताएं कि रतौंधी के लिए इन जांचों का करना अनिवार्य है या नहीं। यह बात इस बात पर निर्भर होगी कि पद से सम्बद्ध काम की आवश्यकता क्या है और जिन व्यक्तियों को सरकारी नौकरी दी जाने वाली है उनकी इयूटी जिस तरह की होगी।

कलर विजन—रंगों के सम्बन्ध में नजर की जांच जरूरी है। नीचे दी गई तालिका के अनुसार रंग का प्रत्यक्ष ज्ञान उच्चतर

(हायर) और निम्नतर (लोअर) ग्रेडों में होना चाहिए जो लैटर्न ड्राइक (एपर्चर) के आकार पर निर्भर हों।

ग्रेड	रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का उच्चतर ग्रेड	रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का निम्नतर ग्रेड
1. लैम्प और उम्मीदवार के बीच की दूरी	16	16
2. ड्राइक (एपर्चर) का आकार	1.3 मि०	1.3 मि०
3. दिखाने का समय	मीटर	मीटर
	5 सैकंड	5 सैकंड

लाल संकेत, हरे संकेत और सफेद रंग को आसानी से और हिष्किकाहट के बिना पहचान लेना संतोषजनक कलर विजन है। इन्जिहारा की प्लेटों के इस्तेमाल को जिन्हें एडिज ग्रीन लैटर्न जैसी उपर्युक्त लैटर्न और अच्छे रोशनी में दिखाया जाता है, कलर विजन की जांच करने के लिए बिल्कुल विश्वसनीय समझा जाएगा। तो दोनों जांचों में से किसी भी एक जांच को साधारणतया पर्याप्त समझा जा सकता है। लेकिन सबक, रेल और हवाई याता-यात से सम्बन्धित सेवाओं के लिए लैटर्न से जांच लाजमी है। शक वाले मामलों में जब उम्मीदवार को किसी एक जांच करने पर अयोग्य पाया जाए तो दोनों ही तरीकों से जांच करनी चाहिए। तथापि कलर विजन की जांच के लिए इन्जिहारा प्लेट एडिज की हरी लालटेन दोनों का प्रयोग भारतीय रेल यातायात सेवा में उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए किया जाएगा।

(ज) दृष्टि की पकड़ से भिन्न आंख की अवस्थाएं (आक्यूलर कंडीशन्स) —

(i) आंख की उस बीमारी को या बड़ती हुई बर्तन त्रुटि (प्रोग्रेसिव रिफ्रेक्टिव एरर) को, जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की पकड़ के कम होने की सम्भावना हो, अयोग्यता का कारण समझना चाहिए।

(ii) भेंगापन (स्किवट) — तकनीकी सेवाओं में जहां द्विनेत्री (वाइनाकुलर) दृष्टि का होना अनिवार्य हो, दृष्टि की पकड़ निर्धारित स्तर की होने पर भी भेंगापन को अयोग्यता का कारण समझना चाहिए। यह रेलवे सुरक्षा दल के उम्मीदवारों के लिए भी लागू होगा। दृष्टि की पकड़ निर्धारित स्तर की होने पर भेंगापन को अन्य सेवाओं के लिए अयोग्यता के कारण नहीं समझना चाहिए।

(iii) एक आंख: — यदि किसी व्यक्ति के एक आंख है या उसकी एक आंख तो ऐसी है जिसकी दृष्टि पकड़ सामान्य है और दूसरी आंख एम्बायलायपिक है अर्थात् उसकी दृष्टि पकड़ सामान्य से कम हो, तो इसके फलस्वरूप उस व्यक्ति में गहराई ग्रहण करने के लिए प्रिविगेथ दृष्टिशक्ति का अभाव होता है। कई सिविल पदों

के लिए ऐसी दृष्टिशक्ति आवश्यक नहीं होती। मेडिकल बोर्ड ऐसे व्यक्ति की उपयुक्तता की सिफारिश कर सकते हैं बशर्ते कि सामान्य आंख में —

(क) चश्मे से या बिना चश्मे के दूर की दृष्टि शक्ति 6/6 और नजदीक की जे० 1 हो, बशर्ते कि दूर की दृष्टि शक्ति के लिए किसी भी याभ्योत्तर वृत्त चमेरीडियन में मूल दृष्टि को विकरित करने की 4 इकाइयों () से अधिक न हो,

(ख) दृष्टि का क्षेत्र पुरा हो,

(ग) रंगों की दृष्टि शक्ति सामान्य हो,

बशर्ते कि बोर्ड को संतोष हो कि उम्मीदवार संबंधित पद-विशेष के सभी कर्तव्यों को पूर्ण कर सकता है।

दृष्टि शक्ति की पकड़ के उपर्युक्त घटे हुए स्तर उन पदों सेवाओं के लिए उम्मीदवार व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे जिन्हें "तकनीकी" वर्गीकृत किया गया हो। सम्बन्धित मन्त्रालय/विभाग को बोर्ड को सूचित करना होगा कि व्यक्ति "तकनीकी", पद का उम्मीदवार है अथवा नहीं।

(2) कोन्टैक्ट लेंस (Contact Lenses)

उम्मीदवार की स्वास्थ्य परीक्षा के समय कोन्टैक्ट लेंस के प्रयोग की आज्ञा नहीं होगी। आंख की जांच करते समय यह आवश्यक है कि दूर की नजर के लिए टाइप किए हुए अक्षर 16 फुट से प्रकाशित हों।

(7) ब्लड प्रेशर

ब्लड प्रेशर के सम्बन्ध में बोर्ड अपने निर्णय से काम लेगा। नार्मल उच्चतर सिस्टोलिक प्रेशर के आकलन की काम चलाऊ विधि नीचे दी जाती है।

(i) 15 से 25 वर्ष के व्यक्तियों में औसत ब्लड प्रेशर लगभग 100—आयु होता है।

(ii) 25 वर्ष से ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर के आकलन का सामान्य नियम यह है कि 110 में आधी आयु जोड़ दी जाए। यह तरीका बिल्कुल संतोषजनक दिखाई पड़ता है।

ध्यान दीजिए—सामान्य नियम के रूप में 140 से ऊपर के सिस्टोलिक प्रेशर की ओर 90 से ऊपर के डायस्टोलिक प्रेशर को संदिग्ध मान लेना चाहिए, और उम्मीदवार को योग्य या अयोग्य ठहराने के सम्बन्ध में अपनी अन्तिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखें? अस्पताल में रखने की रिपोर्ट से यह पता लगाना चाहिए कि घबराहट (एक्साइटमेंट) आदि के कारण ब्लड प्रेशर थोड़े समय रहने वाला है या इसका कारण कोई (कायिक आर्गेनिक बीमारी) है, [ऐसे सभी कसों में हृदय की एक्सरे और विद्युत् हृत्लेखी (इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक) परीक्षाएं और रक्त एरिया निकास (लायरेस) की जांच भी नेमी रूप से की जानी चाहिए। फिर भी उम्मीदवार को योग्य होने या न होने के बारे में अन्तिम फैसला केवल मेडिकल बोर्ड ही करेगा।]

ब्लड प्रेशर (रक्त दाब) लेने का तरीका

नियमन: पारेवाले दाबमापी (मर्करी मोनोमीटर) किस्म का आला (इंस्ट्रूमेंट) इस्तेमाल करना चाहिए। किसी किस्म के व्यायाम या घबराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिए। रोगी बैठा या लेटा हो बशर्ते कि वह और विशेषकर उसकी भुजा शिथिल और आराम से हो। कुछ कुछ हारिजेंटल स्थिति में रोगी के पाश्वर्क पर भुजा को आराम से सहारा दिया जाता है। भुजा पर से कन्धे तक कपड़े उतार देने चाहिए। कफ में से पूरी तरह हवा निकालकर बीच की रबड़ को भुजा के अन्दर की ओर रखकर और इसके निचले किनारे को कोहनी के मोड़ से एक या दो इंच ऊपर करके लगाना चाहिए। इसके बाद कपड़े की पट्टी को फैलाकर समान रूप से लपेटना चाहिए ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फूल कर बाहर को न निकले।

कोहनी के मोड़ पर प्रगंड धमनी (ब्रकिअल आर्टरी) को दबा-दबा कर ढूँढा जाता है और तब इसके ऊपर बीचों बीच स्टेथेस्कॉप को हल्के से लगाया जाता है जो कफ के साथ न लगे। कफ में लगभग 200 mm.Hg. हवा भरी जाती है और इसके बाद इसमें से धीरे-धीरे हवा निकाली जाती है। हल्की क्रमिक ध्वनियां सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर पारे का कालम टिका होता है वह सिस्टोलिक प्रेशर दर्शाता है। जब और हवा निकाली जाएगी तो ध्वनियां तेज सुनाई पड़ेंगी। जिस स्तर पर यह साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्की दबी हुई सी लुप्त प्राय हो जाएं, वह डाय-स्टोलिक प्रेशर है। ब्लड-प्रेशर काफ़ी थोड़ी अवधि में ही ले लेना चाहिए क्योंकि कपल के लम्बे समय का दबाव रोगी के लिए क्षोभकर होता है और इससे रीडिंग गलत हो जाती है। यदि दोबारा पड़ताल करनी जरूरी हो तो कफ में से पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट के बाद ही ऐसा किया जाए। (कभी-कभी कफ में से हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं, दाब गिरने पर ये गायब हो जाती हैं और निरंतर स्तर पर पुनः प्रकट हो जाती हैं। इस "साइलेंट गैप" से रीडिंग में गलती हो सकती है।)

8. परीक्षक की उपस्थिति में किए गए मूत्र की परीक्षा की जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए। जब मेडिकल बोर्ड को किसी उम्मीदवार के मूत्र में रासायनिक जांच द्वारा शक्कर का पता चले तो बोर्ड इसके दूसरे सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा और मधुमेह (डायबीटीज) के ब्योतक चिन्हों और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट करेगा। यदि बोर्ड उम्मीदवार को ग्लूकोज मेह (ग्लाइकोसुरिया) के सिवाए, अपेक्षित मेडिकल फिटनेस के स्टैंडर्ड के अनुरूप पाए तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ फिट घोषित कर सकता है कि ग्लूकोस मेह अमधु मेही (नानडाय-बेटिक) हो और बोर्ड केस को मेडिसन के किसी ऐसे निविष्ट विशेषज्ञ के पास भेजेगा जिनके पास अस्पताल और प्रयोगशाला की सुविधाएं हों। मेडिकल विशेषज्ञ स्टैंडर्ड ब्लड शुगर टालरेंस टेस्ट समेत जो भी क्लिनिकल या लेबोरेटरी परीक्षाएं जरूरी समझेगा और अपनी रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेज देगा जिस पर मेडिकल बोर्ड की 'फिट' या 'अनफिट' की अन्तिम राय आधारित होगी। दूसरे अवसर पर उम्मीदवार के लिए बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा। औषधि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को कई दिन तक अस्पताल में पूरी देख-रेख में रखा जाय।

9. जो स्त्री उम्मीदवार जांचों के फलस्वरूप 12 सप्ताह या उससे अधिक अवधि की गर्भवती पाई जाए उसे तब तक के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाय जब तक उसकी गर्भावस्था समाप्त न हो जाए। गर्भावस्था के समाप्त होने के 6 सप्ताह बाद यदि वह पंजीकृत चिकित्सक से स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दे तो अयोग्य प्रमाण-पत्र के लिए उसकी फिर से जांच की जाए।

10. निम्नलिखित अतिरिक्त बातों का प्रेक्षण करना चाहिए

(क) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है या नहीं और कान की बीमारी का कोई चिन्ह है या नहीं। यदि कोई कान की खराबी हो तो इसकी परीक्षा कान-विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए। यदि सुनने की खराबी का इलाज शल्य क्रिया (आपरेशन) या हिर्यारिंग ऐण्ड के इस्तेमाल से हो सके तो उम्मीदवार को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता बशर्ते कि उसके कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो। यह उपबन्ध रेल सेवाओं के मामले में लागू नहीं होता। चिकित्सा-परीक्षा प्राधिकारी के मार्ग-दर्शन के लिए इस संबंध में निम्नलिखित मार्गदर्शक जानकारी दी जाती है :—

(1) एक कान में प्रकट यदि उच्च फ्रीक्वेंसी में अथवा पूर्ण बहरापन, दूसरा कान हो तो गैर तकनीकी काम के सामान्य होना। लिए योग्य।

(2) दोनों कानों में यदि 1000 से 4000 तक की स्पीच फ्रीक्वेंसी में बह-प्रत्यक्ष बोध, रापन 30 डेसीबेल तक हो तो जिसमें श्रवण तकनीकी तथा गैर तकनीकी यंत्र (हिर्यारिंग ऐण्ड) द्वारा कुछ सुधार संभव हो। लिए योग्य।

(3) सैन्ड्रल अथवा मार्जिनल टाइम के टिम्पेनिक मेम्बरने में छिद्र

(i) एक कान सामान्य हो दूसरे कान में टिम्पेनिक मेम्बरने छिद्र विद्यमान हो तो अस्थायी रूप में अयोग्य। कान की शल्य चिकित्सा की स्थिति सुधरने से दोनों कानों में मार्जिनल या अन्य छिद्र वाले उम्मीदवार को अस्थायी रूप में अयोग्य घोषित करके उस पर नीचे दिए गए नियम 4 (ii) के अधीन विचार किया जा सकता है।

(ii) दोनों कानों में मार्जिनल या एटिक छिद्र होने पर अयोग्य।

(iii) दोनों कानों में सैन्ड्रल छिद्र होने पर अस्थायी रूप में अयोग्य।

- (4) एक ओर से/दोनों ओर से मस्टायड केविटी सबनार्मल श्रवण वाले कान। (i) किसी एक कान से सामान्य रूप से सुनाई देता हो, दूसरे कान से मस्टायड केविटी होने पर तकनीकी तथा गैर तकनीकी दोनों प्रकार के कामों के लिए योग्य। (ii) दोनों ओर से मस्टायड केविटी तकनीकी काम के लिए अयोग्य, यदि किसी भी कान की श्रवणता श्रवण यंत्र लगाकर अथवा बिना लगाए सुधर कर 30 डेसीबेल हो जाने पर गैर तकनीकी कामों के लिए योग्य।
- (5) बहते रहने वाला कान — आपरेशन किया गया/बिना आपरेशन वाला तकनीकी तथा गैर तकनीकी दोनों प्रकार कानों के लिए अस्थायी रूप में अयोग्य।
- (6) नासा पट की हड्डी संबंधी विरूपताओं (बोनी डिफॉर्मिटीज) सहित अथवा उससे रहित नाक की जीर्ण प्रदाहक/एलर्जिक दशा (i) प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। (ii) यदि लवणों सहित नासा पट अपसरण विद्यमान होने पर अस्थायी रूप में अयोग्य।
- (7) टॉसिल्ला और/अथवा स्वरयंत्र (लैन्सि) की जीर्ण प्रदाहक दशा। (i) टॉसिल्ला और/अथवा स्वरयंत्र की जीर्ण प्रदाहक दशा—योग्य। (ii) यदि आवाज में अत्यधिक कर्कशता विद्यमान हो तो अस्थायी रूप में अयोग्य।
- (8) कान, नाक, गले (ई० एन टी०) के हल्के अथवा अपने स्थान पर दुर्दम्य ट्यूमर (i) हल्का ट्यूमर—अस्थायी रूप में अयोग्य। (ii) दुर्दम्य ट्यूमर—अयोग्य।
- (9) आस्टोक्लिथ-सिस श्रवण-यंत्र की सहायता से या आपरेशन के बाद श्रवणता 30 डेसीबेल के अन्दर होने पर योग्य।
- (10) कान, नाक अथवा गले के जन्मजात दोष (i) यदि कामकाज में बाधक न हो तो योग्य। (ii) भारी मात्रा में हकलाहट हो तो अयोग्य।
- (11) नेजल पोली अस्थायी रूप में अयोग्य।
- (ख) उम्मीदवार बोलने में हकलाता है या नहीं।
- (ग) उसके दांत अच्छी हालत में हैं या नहीं, और अच्छी तरह चबाने के लिए जरूरी होने पर नकली दांत लगे हैं या नहीं। अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा जाएगा।
- (घ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नहीं और छाती काफी फैलती है या नहीं तथा उसका दिल और फेफड़े ठीक हैं या नहीं।
- (ङ) उसे पेट की कोई बीमारी है या नहीं।
- (च) उसे रपचर (हार्निया या फटन) है या नहीं।
- (छ) उसे हाइड्रोसील बड़ी हुई वरिक्डोसील थिरा (बेन) या बवासीर है या नहीं।
- (ज) उसकी शाखाओं, हाथों और पैरों की बनावट और विकास अच्छा है या नहीं और उसकी संधियां भली भांति स्वतन्त्र रूप से हिलती हैं या नहीं।
- (झ) उसे कोई चिरस्थायी त्वचा की बीमारी है या नहीं।
- (ञ) कोई जन्मजात कुरचना या दोष है या नहीं।
- (ट) उसमें किसी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान हैं या नहीं जिनसे कमजोर गठन का पता लगे।
- (ठ) फारगर टीके के निशान हैं या नहीं।
- (ड) उसे कोई संचारी (कम्यूनिकेबल) रोग है या नहीं।

11. दिल और फेफड़ों की किसी ऐसी विलक्षणता का पता लगाने के लिए जो साधारण शारीरिक परीक्षा से ज्ञात न हो सभी केसों में नेमी रूप से छाती की एक्स-रे परीक्षा की जानी चाहिए।

जब कोई दोष मिले तो उसे प्रमाण-पत्र में अवश्य नोट किया जाए। मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिए कि उम्मीदवार से अपेक्षित दक्षतापूर्ण इयूटी में इससे बाधा पड़ने की संभावना है या नहीं।

12. जहां तक मिली-जुली प्रतियोगिता परीक्षा के उम्मीदवारों का सम्बन्ध है, उनके लिए ऊपर पैरा 11 के नीचे की टिप्पणी में बताई गई अपील करने की कार्यविधि लागू नहीं होती। इस परीक्षा के उम्मीदवार को अपील की शुल्क 50 रु० भारत सरकार के इस सम्बन्ध में निर्धारित ढंग से जमा करना होता है। यह फीस केवल उन उम्मीदवारों को वापस मिलेगी जो अपीलीय स्वास्थ्य-परीक्षा बोर्ड द्वारा आरोग्य घोषित किए जायेंगे। शेष दूसरों के मामलों में यह जफ्त करली जाएगी। यदि उम्मीदवार चाहे तो

अपने आरोग्य होने के दावे के समर्थन में स्वस्थता प्रमाण-पत्र संलग्न कर सकते हैं। उम्मीदवारों को प्रथम स्वास्थ्य-परीक्षा बोर्ड द्वारा भेजे गए निर्णय के 21 दिन के अन्दर अपीलें करनी चाहिए अन्यथा दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के लिए अपीलीय स्वास्थ्य-परीक्षा बोर्ड द्वारा दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा केवल नई दिल्ली में ही होगी। और इसका खर्च उम्मीदवारों को ही देना पड़ेगा दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के सम्बन्ध में की जाने वाली यात्राओं के लिए कोई यात्रा-भत्ता या दैनिक-भत्ता नहीं दिया जाएगा। अपीलों के निर्धारित शुल्क के साथ प्राप्त न होने पर अपीलीय या स्वास्थ्य-परीक्षा बोर्ड द्वारा की जाने वाली स्वास्थ्य-परीक्षा के प्रबन्ध के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय कार्मिक विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाई की जाएगी।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्टें

मेडिकल परीक्षक के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती है :—

1. शारीरिक योग्यता (फिटनेस) के लिए अपनाये जाने वाले स्टैंडर्ड में सम्बन्धित उम्मीदवार की आयु और सेवा-काल (यदि हो) के लिए उचित गुंजाइश रखनी चाहिये।

किसी ऐसे व्यक्ति को पञ्चिक सर्विस में भर्ती के लिए योग्य नहीं समझा जाएगा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी (अपार्टिंग अथॉरिटी) को, यह तसल्ली नहीं होगी कि उसे ऐसी कोई बीमारी या शारीरिक दुर्बलता (वाइली इन्फार्मिटी) नहीं है जिससे वह उस सेवा के लिए अयोग्य हो या अयोग्य होने की संभावना हो।

यह बात समझ लेनी चाहिए कि योग्यता का प्रश्न भविष्य से भी उतना ही संबद्ध है जितना वर्तमान से है और मेडिकल परीक्षा का एक मुख्य उद्देश्य निरन्तर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थायी नियुक्ति के उम्मीदवारों के मामलों में अकाल मृत्यु होने पर समय पूर्व पेंशन की अदायगियों को रोकना है। साथ ही यह भी नोट किया जाय कि यहां प्रश्न केवल निरन्तर कारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को अस्वीकृत करने की सलाह उस हालत में नहीं दी जानी चाहिए जब कि उसमें कोई ऐसा दोष हो जो, केवल बहुत कम स्थितियों में निरन्तर कारगर सेवा में बाधक पाया गया हो।

महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी लेडी डाक्टर को मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा।

भारतीय रक्षा लेखा सेवा (इण्डियन डिफेंस अकाउंट्स सर्विस) के उम्मीदवारों को भारत में और भारत से बाहर क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) करनी होगी? ऐसे उम्मीदवारों के मामले में मेडिकल बोर्ड को इस बारे में अपनी राय विशेष रूप से रिकार्ड करनी चाहिए, कि उम्मीदवार क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) के योग्य है या नहीं। डाक्टरी बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए।

ऐसे मामलों में जब कि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके

अस्वीकार किए जाने के आधार पर उम्मीदवार को बताये जा सकते हैं किन्तु डाक्टरी बोर्ड ने जो खराबी बताई हो उनका विस्तृत ज्योरा नहीं दिया जा सकता।

ऐसे मामलों में जहां डाक्टरी बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बनाने वाली छोटी-मोटी खराबी चिकित्सा (ओपध या शल्य) द्वारा दूर हो सकती है वहां डाक्टरी बोर्ड द्वारा इस आशा का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिये। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूचित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है और वह खराबी दूर हो जाये जो एक दूसरे मेडिकल बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बहने में संबंधित प्राधिकारी स्वतन्त्र है।

यदि कोई उम्मीदवार अस्थायी रूप से अयोग्य करार दिया जाये तो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारणतया कम-से-कम छः महीने से कम नहीं होनी चाहिए। मिश्रित अवधि के बाद जब दुबारा परीक्षा हो तो ऐसे उम्मीदवारों को और आगे की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता के सम्बन्ध में अथवा वे इस नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं ऐसा निर्णय अंतिम रूप से दिया जाना चाहिए।

(क) उम्मीदवार का कथन और घोषणा

अपनी मेडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित स्टेटमेंट देना चाहिए और उसके साथ लगी हुई घोषणा (डिक्लरेशन) पर हस्ताक्षर करने चाहिए। नीचे दिए गए नोट में उल्लिखित चेतावनी की ओर उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

1. अपना पूरा नाम लिखें
(साफ अक्षरों में)

2. अपनी आयु और जन्म स्थान बतायें

2. (क) क्या आप गोरखा, गढ़वाली, असमी, नागालैंड आदि जातियों आदि से सम्बन्धित हैं जिनका औसत कद दूसरों से छोटा होता है। 'हां' या 'नहीं' में उत्तर दीजिए और यदि उत्तर 'हां' में है तो उस जाति का नाम बताइए।

3. (क) क्या आपको कभी चेचक, रुक-रुक कर होने वाला या कोई दूसरा बुखार, ग्रंथियों (ग्लैंड्स) का बढ़ना या इनमें पीप पड़ना, थूक में खून आना, दमा, बिल की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मुर्छा के दौर, रूमेटिज्म, एपेंडिसाइटिस हुआ है?

अथवा

(ख) दूसरी कोई ऐसी बीमारी या दुर्घटना, जिसके कारण शय्या पर लेटे रहना पड़ा हो और जिसका मेडिकल या सर्जिकल इलाज किया गया हो, हुई है?

4. आपको चेचक आदि का अंतिम टीका कब लगा था?

5. क्या आपको अधिक काम या किसी दूसरे कारण से किसी किस्म की अधीरता (नर्वसनेस) हुई है?

6. अपने परिवार के संबंध में निम्नलिखित व्योरा दें :—

यदि पिता जीवित हो तो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	यदि पिता की मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण
--	--

आपके कितने भाई जीवित हैं, उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपके कितने भाइयों की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण
---	--

यदि माता जीवित हो तो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	यदि माता की मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु के समय उसकी आयु और मृत्यु का कारण
--	---

आपकी कितनी बहनें जीवित हैं, उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपकी कितनी बहनों की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण
---	---

7. क्या इसके पहले किसी मेडिकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा की है ?

8. यदि ऊपर के प्रश्न का उत्तर 'हां' हो तो बताइए किस सेवा/सेवाओं के लिए आपकी परीक्षा की गई थी ?

9. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था ?

10. कब और कहाँ मेडिकल बोर्ड हुआ ?

11. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया गया हो अथवा आपको मालूम हो

मैं घोषित करता हूँ कि जहाँ तक मेरा विश्वास है, ऊपर विधे गये सभी जबाब सही और ठीक हैं।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

मेरे सामने हस्ताक्षर किये गये।

बोर्ड के चेयरमैन के हस्ताक्षर

नोट—उपर्युक्त कथन की प्रामाण्यता के लिए उम्मीदवार जिम्मेदार होगा। जान-बूझकर किसी सूचना को छुपाने से वह नियुक्ति खो बैठने की जोखिम लेगा और यदि वह नियुक्त हो भी जाये तो बाधक्य निवृत्ति भत्ता (सुपरएनुएशन अलाउंस) या उपदान (ग्रेचुअटी) के सभी दावों से हाथ धो बैठेगा।

(ख) की शारीरिक परीक्षा की/ मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

1. सामान्य विकास : अच्छा बीच का कम पोषण पतला औसत मोटा कद (जूते उतार कर) वजन अत्युत्तम वजन कब था ? वजन में कोई हाल ही में हुआ परिवर्तन तापमान छाती का घेर

(1) पूरा सांस खींचने पर

(2) पूरा सांस निकालने पर

2. त्वचा—कोई जाहिरा बीमारी

3. नेत्र :

(1) कोई बीमारी

- (2) रतौधी
- (3) कलर विजन का दोष
- (4) दृष्टि क्षेत्र (फील्ड आफ विजन)
- (5) दृष्टि की पकड़ (विजुअल एक्विटी)

दृष्टि की पकड़ चश्मे के बिना	चश्मे में चश्मे की पावर		
	गोल	सिलि०	अक्ष
दूर की नजर	दा० ने० बा० ने०		
पास की नजर	दा० ने० बा० ने०		
हाइपरमेट्रोपिया (व्यक्त)	दा० ने० बा० ने०		

4. कान : निरीक्षण सुनना
दायां कान बायां कान
5. ग्रंथियां थाइराइड
6. दांतों की हालत
7. श्वसन तंत्र (रस्पिरेटरी सिस्टम) क्या शारीरिक परीक्षा करने पर सांस के अंगों में किसी विलक्षणता का पता लगा है ? यदि पता लगा है तो विलक्षणता का पूरा ब्यौरा दें।
8. परिसंचरण तंत्र (सर्कुलेटरी सिस्टम)
- (क) हृदय : कोई आंगिक क्षति (आर्गेनिक लीजन) ?
गति रेट :
खड़े होने पर :
25 बार कुदाये जाने के बाद
कुदाये जाने के 2 मिनट बाद
- (ख) ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक डायस्टोलिक
9. उदर (पेट) : घेर दाब वेदना (टेंडरनेस) हर्निया
- (क) दबा कर मालूम पड़ना, जिगर तिल्ली ...
गुर्दे ट्यूमर
- (ख) बवासीर के मस्से फिलचुला
10. तांत्रिक तंत्र (नर्वस सिस्टम) तांत्रिका या मानसिक अशक्तता का संकेत।
11. चाल तंत्र (लोकोमीटर सिस्टम)
कोई विलक्षणता

12. जनन-तन्त्र (जेनिटो युरिनरी सिस्टम)/हाइड्रोसोल, वेरिकोसोल आदि का कोई संकेत। मूत्र परीक्षा :

- (क) कैसा दिखाई पड़ता
- (ख) स्पेसिफिक ग्रेविटी (अपेक्षित गुरुत्व)
- (ग) एल० यमेन
- (घ) शक्कर
- (ङ) कास्ट
- (च) कोशिकाएं (सेल्स)

13. छाती की एक्स-रे रिपोर्टें

14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिसमें वह उस सेवा की दक्षतापूर्वक निभाने के लिए अयोग्य हो सकता है जिसके लिए वह उम्मीदवार है ?

नोट :—यदि उम्मीदवार कोई महिला है और यदि वह 12 सप्ताह या उससे अधिक समय से गर्भवती है तो उसे विनियम 6 के अनुसार अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाए।

15. (i) उन सेवाओं का उल्लेख करें जिनके लिए उम्मीदवार की परीक्षा की गई है :—

- (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा,
- (ख) भारतीय पुलिस सेवा और दिल्ली और हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा,
- (ग) केन्द्रीय सेवार्य, श्रेणी I और II

(ii) क्या यह निम्नलिखित सेवाओं में दक्षतापूर्वक और निरंतर काम करने के लिए सब तरह से योग्य पाया गया है :—

- (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा।
- (ख) भारतीय पुलिस सेवा और दिल्ली और हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा (कद, छाती का घेर, नजर, रंग, दिखाई न देना और चाल, खास तौर से देखें)।
- (ग) भारतीय रेलवे यातायात सेवा (कद, छाती, नजर, रंग दिखाई न देना, खास तौर से देखें)।

(घ) दूसरी केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी I/II

(iii) क्या उम्मीदवार क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) के लिए योग्य है।

नोट :—बोर्ड को अपना जांच परिणाम निम्नलिखित तीन वर्गों में से किसी एक वर्ग में रिटार्ड करना चाहिए।

- (i) योग्य (फिट)
- (ii) अयोग्य (अनफिट) जिसका कारण
- (iii) अस्थायी रूप से योग्य, जिसका कारण

स्थान अध्यक्ष (प्रेसिडेंट)

तारीख सदस्य

सदस्य

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 3 मई 1973

सं० 51/1/73-ए० एन० एल० (1)—राष्ट्रपति, निम्न-लिखित गैर-सरकारी सदस्यों को, गृह मंत्री से संबद्ध लक्कादीव, मिनिकाय और अमिनदिवी द्वीप-समूह संघ शासित क्षेत्र के लिए सलाहकार समिति में 1 अप्रैल, 1973 से 31 मार्च, 1974 तक की अवधि के लिए सहर्ष मनोनीत करते हैं :

1. अंड्रोथ के श्री के० नाल्लाकोया ।
2. मिनिकाय के श्री ब्रादूवेंगंदुवर अली मानिकफान ।
3. अमिन के श्री पट्टाक्कल पूकोया
4. कावरट्टी के श्री काथीथोडा अहमद ।
5. किल्टन के श्री एन० कोया

सं० 51/1/73-ए० एन० एल०-(II)—राष्ट्रपति, निम्न-लिखित गैर-सरकारी सदस्यों को लक्कादीव, मिनिकाय और अमिनदिवी द्वीप-समूह के प्रशासक से संबद्ध सलाहकार परिषद में 1 अप्रैल, 1973 से 31 मार्च, 1974 तक की अवधि के लिए सहर्ष मनोनीत करते हैं :—

1. कल्पेनी के श्री पी० हमजाकोया ।
2. कादमत के श्री एम० सैयद अली ।
3. चेतलट के श्री सी० मुथुकोया ।
4. बिल्ला के श्री चेरीयाबिय्यायीयोदा सैयद बुहारी ।
5. अगात्ती के श्री अथेनचेस्ता अचापदा कास्मी ।
6. अमिन की श्रीमती पुथिया इदायक्कल कादीजबी ।
7. कल्पेनी की कुमारी टी० पी० पाथुमाबी ।

जी० के० भनोत, संयुक्त सचिव

वित्त मंत्रालय**सरकारी उद्यम कार्यालय**

नयी दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 1973

संकल्प

सं० एफ० 6(23)-समन्वय/73—भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि वित्त मंत्रालय (सरकारी उद्यम कार्यालय) के संकल्प सं० एफ० 6(90)-समन्वय/71, दिनांक 31 दिसम्बर, 1971 के अन्तर्गत नियुक्त की गयी कार्य समिति का कार्यकाल 31 दिसम्बर, 1973 तक बढ़ा दिया जाये ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र के भाग 1, खण्ड 1 में प्रकाशित कराया जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतिलिपि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य सरकारों/संघीय राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों तथा अन्य सभी सम्बन्धित वर्ग को भेजी जाये ।

पी० सी० भट्टाचार्य, अवर सचिव

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 मई 1973

सं० 4(1)/73-ई० पी० जैड०—केन्द्रीय सरकार श्री एच० एन० रे, सचिव (ध्यय), वित्त मंत्रालय को, श्री एम० आर० यार्दी के स्थान पर सान्ताग्रूज एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथारिटी के एक सदस्य के रूप में एतद्वारा नियुक्त करती है और भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० 4(1)/73-ई० पी० जैड० दिनांक 15 फरवरी, 1973 में और आगे निम्नोक्त संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रमांक (4) के सामने दी गई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नोक्त प्रविष्टि की जाए, अर्थात् :—

“(4) श्री एच० एन० रे,
सचिव (ध्यय),
वित्त मंत्रालय ।”

ना० सा० वैद्यनाथन्, उप-सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली-29, दिनांक 4 मई 1973

संकल्प

सं० डी० एस० टी० 8/(1)/72-जे० आर० सी०—इस विभाग के संकल्प क्र० डी० एस० टी० 8/1/72-जे० आर० सी० दिनांक 11 दिसम्बर, 1972 के क्रम में भारत सरकार ने संयुक्त पुनरीक्षण समिति, जिसकी स्थापना भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग तथा भारतीय प्राणि सर्वेक्षण विभाग के संगठनात्मक एवं क्रियाविधि ढांचे के पुनरीक्षण के लिए की गयी है, की अन्तिम रिपोर्टें प्रस्तुत करने की अवधि 31 अगस्त, 1973 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है ।

अ० रामाचन्द्रन, सचिव

रेल मंत्रालय**(रेलवे बोर्ड)**

नई दिल्ली, दिनांक 5 मई 1973

संकल्प

सं० ई० (आर० बी०) 1-73/21/40—1-2-73 के संकल्प सं० ई० (आर० बी०) 1-70/21/86 पार्ट का अतिश्रमण करते हुए भारत सरकार ने गैर सरकारी स्थायी स्वैच्छिक सहायता समिति को तत्काल पुनः प्रवर्तित करने और पुनर्गठित करने का विनिश्चय किया है ।

श्री एम० गोविंद रेड्डी पुनर्गठित समिति के अध्यक्ष और श्री कामेश्वर प्रसाद सिंह इसके सदस्य सचिव होंगे । समिति के सदस्यों के नाम बाद में अधिसूचित किये जायेंगे ।

2. यह समिति रेलों में बिना टिकट यात्रा तथा चोरी और उठाईगिरी की रोकथाम की ओर अपना ध्यान केन्द्रित करेगी ।

आवेश

4. आवेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भीरत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

एच० एफ० पिटो, सचिव
रेलवे बोर्ड एवं पदेन संयुक्त सचिव ।

RAJYA SABHA SECRETARIAT*New Delhi, the 7th May 1973*

No. RS.18/73-T.—Shri Mahendra Mohan Choudhury, an elected Member of the Rajya Sabha representing the State of Assam, has resigned his seat in the Rajya Sabha with effect from the 4th May, 1973.

B. N. BANERJEE, Secy.**LOK SABHA SECRETARIAT****(ESTIMATES COMMITTEE BRANCH-I)***New Delhi, the 9th May 1973*

No. 3/1/ECI/73.—The following Members of the Lok Sabha have been elected to serve on the Committee on Estimates for the term ending on the 30th April, 1974:—

1. Shri R. N. Barman
2. Shri Rajagopalrao Boddepalli
3. Swami Brahmanand
4. Shrimati Jyotsna Chanda
5. Shri Bhaoosahaib Dhamankar
6. Shri Giridhar Gomango
7. Shri D. B. Chandra Gowda
8. Shri Krishna Chandra Halder
9. Shri Hari Singh
10. Shri M. M. Joseph
11. Shri Tulsiram Dashrath Kamble
12. Haji Lutfal Haque
13. Shri Nageshwararao Meduri
14. Shri Prasanbhai Mehta
15. Shri Mohammad Tahir
16. Shri Surendra Mohanty
17. Shrimati Shakuntala Nayar
18. Shri Krishna Chandra Pandey
19. Shri Anantrao Patil
20. Shri Jharkhande Rai
21. Shri P. Gangā Reddy
22. Ch. Sadhu Ram
23. Shri Ebrahim Sulaiman Sait
24. Shri P. A. Saminathan
25. Shri P. Ranganath Shenoy
26. Shri Awadesh Chandra Singh
27. Shri R. K. Sinha
28. Shri Kamal Nath Tewari
29. Shri M. G. Uikey
30. Shri G. P. Yadav.

G. D. SHARMA, Dy. Secy.**CABINET SECRETARIAT****(Department of Personnel and Administrative Reforms)****RULES***New Delhi, the 26th May 1973*

No. 15/1/73-AIS(I).—The rules for a combined competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1973 for selection of Released Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers who were commissioned in the Armed Forces after 1st November, 1962, but before 10th January, 1968, or who had joined any pre-Commission training before the latter date, but were commissioned on or after that date, for the purpose of filling vacancies reserved for them in the following Services are, with the concurrence of the Ministries concerned and the Comptroller and Auditor General of India in respect of the Indian Audit and Accounts Service, published for general information in pursuance of the provisions contained in rule 7A of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, and the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, and the provisions contained in rule 5 of the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers (Reservation of Vacancies) Rules, 1971. The aforesaid provisions shall cease to be in force on and from

the 29th January 1974, unless extended by Government—

- (i) The Indian Administrative Service,
- (ii) The Indian Foreign Service,
- (iii) The Indian Police Service,
- (iv) The Central Information Service, (Grade II), Class I,
- (v) The Indian Audit & Accounts Service,
- (vi) The Indian Customs & Central Excise Service,
- (vii) The Indian Defence Accounts Service,
- (viii) The Indian Income-tax Service (Class I),
- (ix) The Indian Ordnance Factories Service, Class I, (Assistant Managers—Non-Technical),
- (x) The Indian Postal Service,
- (xi) The Indian Railway Accounts Service,
- (xii) The Military Lands and Cantonments Service, Class I,
- (xiii) The Indian Railway Traffic Service,
- (xiv) The Delhi and Andaman & Nicobar Islands, Police Service, Class II,
- (xv) The Central Secretariat Service, Section Officers' Grade, Class II,
- (xvi) The Customs Appraisers' Service, Class II,
- (xvii) The Delhi and Andaman & Nicobar Islands Civil Service, Class II,
- (xviii) The Indian Foreign Service, Branch 'B', Integrated Grades II and III of the General Cadre, Class II (Section Officers' Grade),
- (xix) The Railway Board Secretariat Service Class II,
- (xx) The Armed Forces Headquarters Civil Service Assistant Civilian Staff Officers' Grade, Class II,
- (xxi) The Military Lands and Cantonments Service, Class II,
- (xxii) The Goa, Daman and Diu Civil Service, Class II, and
- (xxiii) The Pondicherry Civil Service, Class II,

A candidate may apply for admission to the examination in respect of any one or more of the Services mentioned above. He may specify in his application as many of these Services as he may wish to be considered for. Candidates are warned that they will not be considered for appointment to any Service not specified by them.

N.B. I.—Candidates are required to specify clearly in their applications the order of preferences for the services for which they wish to be considered. They are advised to indicate as many Services as they wish to, so that having regard to their ranks in the order of merit, due consideration can be given to their preferences when making appointments.

N.B. II.—No request for addition to or alteration in the order of preferences for the Services originally indicated by a candidate in his application will be considered unless such a request is received in the Cabinet Secretariat (Department of Personnel and Administrative Reforms) within 10 days of the date of announcement of the final result of the examination.

A candidate who, on the results of the written part of the examination, qualifies for the *Viva Voce* for the Indian Administrative Service/Indian Police Service will be separately asked by the Cabinet Secretariat (Department of Personnel and Administrative Reforms) to communicate to them the order of preferences in which he would like to be considered for allotment to various States.

2. Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Castes) (Part C States) Order 1951, the Constitution (Schedule Tribes) Order, 1950, and

Constitution (Scheduled Tribes) (Part C States) Order, 1951, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956 read with the Bombay Reorganisation Act, 1960 and the Punjab Reorganisation Act, 1966; the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964 the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968 and the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.

3. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix II to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. Subject to the provisions of these Rules, the following categories of Emergency Commissioned and Short Service Commissioned Officers who were commissioned in the Armed Forces after 1st November, 1962 but before 10th January, 1968, or who had joined any pre-Commission training before the latter date but who were commissioned on or after that date, will be eligible to appear at this examination :—

- (i) Officers who have been released during 1973 prior to the date of this Notification or are due to be released thereafter till the end of 1974.
- (ii) Officers mentioned in rule 9 to the extent and in accordance with the provisions of that rule.

NOTE 1.—For the purpose of these Rules, “release” means

- (i) release as per the scheduled year of release,
- (ii) invalidment owing to a disability attributable to, or aggravated by military service,

from the Armed Forces after a spell of service and not during or at the end of training, or during or at the end of Short Service Commission granted to cover the period of such training prior to being taken in actual service nor does it cover cases of officers released on account of misconduct, or inefficiency or at their own request.

NOTE 2.—The expression “scheduled year of release” means—

- (i) in so far as it relates to the Emergency Commissioned Officers, the year in which they are due for release in accordance with the phased programme approved by the Government of India in the Ministry of Defence, and
- (ii) in so far as it relates to the Short Service Commissioned Officers, the year in which their normal tenure as Short Service Commissioned Officers is to expire.

NOTE 3.—The candidature of a person shall be cancelled, if after submitting his application he is granted permanent Commission in the Armed Forces, or he resigns from the Armed Forces or he is released therefrom on account of misconduct, inefficiency or at his own request.

NOTE 4.—Engineers and Doctors employed under the Central Government or State Governments or Government owned industrial undertakings who are required to serve in the Armed Forces for a minimum prescribed period under the Compulsory Liability Scheme and who are granted Short Service Commission under the relevant rules during the period of such service will not be eligible for admission to this examination

NOTE 5.—Officers belonging to the Volunteer Forces of the Armed Forces and called upon for service will not be eligible for admission to this examination

5. (1) For the Indian Administrative Service Indian Police Service, a candidate must be a citizen

(2) For other Services, a candidate must be either—

- (a) a citizen of India, or
- (b) a subject of Sikkim or
- (c) a subject of Nepal, or
- (d) a subject of Bhutan or
- (e) a Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or
- (f) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka (formerly known as Ceylon) and the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (c), (d),

(e) and (f) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Provided further that candidates belonging to categories (c), (d) and (e) above will not be eligible for appointment to the Indian Foreign Service.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also provisionally be appointed subject to the necessary certificate being given to him by the Government.

6. (a) A candidate must not have attained the age of 24 years on the first August of the year in which he joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training).

Provided that a candidate applying for admission to this examination under Rule 10(b) below must not have attained on the aforesaid date the age of :—

- (i) 24 years, if he were, but for discontinuance of his studies on joining the Armed Forces, due to appear at an examination for the award of any of the qualifications prescribed in Rule 10(a) below in the year in which he joined the pre-Commission training or got the Commission (where there was only post-Commission training);
- (ii) 23 years, if he were, but for the discontinuance of his studies on joining the Armed Forces, due to appear at an examination for the award of any of the qualifications prescribed in Rule 10(a) below in the year following the year in which he joined the pre-Commission training or got the Commission (where there was only post-Commission training);
- (iii) 22 years, if he were, but for discontinuance of his studies on joining the Armed Forces, due to appear at an examination for the award of any of the qualifications prescribed in Rule 10(a) below, in the second year following the year in which he joined the pre-Commission training or got the Commission (where there was only post-Commission training);
- (iv) 21 years if he were, but for discontinuance of his studies on joining the Armed Forces, due to appear at an examination for the award of any of the qualifications prescribed in Rule 10(a) below, in the third year following the year in which he joined the pre-Commission training or got the Commission (where there was only post-Commission training);

ears, if he were, but for discontinuance of his studies on joining the Armed Forces due to appear at an examination for the award of any of the qualifications prescribed in Rule 10(a) below in the fourth year following the year in which he joined the pre-Commission training or got the Commission (where there was only post-Commission training); and

- (vi) 19 years, if he, were, but for discontinuance of his studies on joining the Armed Forces, due to appear at an examination for the award of any of the qualifications prescribed in Rule 10(a) below in the fifth year following the year in which he joined the pre-Commission training or got the Commission (where there was only post-Commission training).

(b) The age limit prescribed above will be relaxable :—

- (i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;
- (ii) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide displaced person from erstwhile East Pakistan and had migrated to India on or after 1st January 1964 but before 25th March, 1971;
- (iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide displaced person from erstwhile East Pakistan and had migrated to India on or after 1st January, 1964 but before 25th March, 1971;
- (iv) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondicherry and has received education through the medium of French at some stage;
- (v) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Sri Lanka (formerly known as Ceylon) and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October 1964;
- (vi) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Sri Lanka (formerly known as Ceylon) and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;
- (vii) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu;
- (viii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda or the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar);
- (ix) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June 1963;
- (x) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;
- (xi) up to a maximum of three years in the case of defence services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof;
- (xii) up to a maximum of eight years in the case of defence services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof who belongs to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes;
- (xiii) up to a maximum of three years, if a candidate who joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training) in 1963, is a bona fide displaced person from Pakistan. This concession is limited to the first admissible chance at the examination;
- (xiv) up to a maximum of eight years if a candidate who joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training) in 1963, belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide displaced person from Pakistan. This concession is limited to the first admissible chance at the examination;

- (xv) up to a maximum of four years if a candidate who joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training) in 1963 or 1964 or 1965, is a resident of the Andaman and Nicobar Islands. This concession is limited to the first admissible chance at the examination in the case of a candidate who joined the pre-Commission training, or got the Commission (where there was only post-Commission training) in 1965; and

- (xvi) up to a maximum of three years if a candidate, who joined the pre-Commission training, or got the Commission (where there was only post-Commission training) in 1963 or 1964 or 1965, is an Indian citizen and is a repatriate from Sri Lanka (formerly known as Ceylon). This concession is limited to the first admissible chance at the examination in the case of a candidate who joined the pre-Commission training, or got the Commission (where there was only post-Commission training) in 1965.

NOTE 1.—The provisions contained in clauses (xiii) and (xiv) of Rule 6(b) will not apply to candidates mentioned at Sl. Nos. (ii), (iii), (iv), (v) and (vi) in proviso to Rule 6(a).

NOTE 2.—The provisions contained in clauses (xv) and (xvi) of Rule 6(b) will not apply to candidates mentioned at Sl. Nos. (iii), (iv), (v) and (vi) in proviso to Rule 6(a) who joined pre-Commission training or got the Commission (where there was only post-Commission training) after 1963.

The provisions contained in clauses (xv) and (xvi) of Rule 6(b) will not apply to candidates mentioned at Sl. No. (ii) in proviso to Rule 6(a) who joined pre-Commission training or got the Commission (where there was only post-Commission training) after 1964.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

7. No candidate shall be permitted to compete more than two times at the examination.

Provided that a candidate who had not attained the age specified in Rule 6 above on the first August of the year in which he joined the pre-Commission training in the Armed Forces, or got the Commission (where there was only post-Commission training), but had attained that age on the 1st August of the year succeeding the year in which he joined the pre-Commission training or got the Commission (where there was only post-Commission training) shall be permitted to compete only once at the examination.

NOTE.—In computing the number of attempts by a candidate under this Rule an attempt, if any, made by such candidate at the I.A.S. etc. (Released Emergency Commissioned/Short Service Commissioned Officers) Examination held prior to 1973 shall be taken into account.

8. (1) A candidate who is eligible to take only one chance must take the examination held in the year preceding the year of his release.

(2) A candidate who is eligible to take two chances must take the examination held in the year preceding the year of his release and the year of his release.

9. Notwithstanding anything contained in Rule 8—

(a) A Short Service Commissioned Officer who has been invalided owing to a disability attributable to or aggravated by military service may subject to the exception mentioned in the Notes below this rule, take the examination to be held, in 1973.

- (i) as his only chance, if invalided during 1972 after the closing date prescribed for receipt of applications for the 1972 examination, or during 1973 prior to the closing date prescribed for receipt of applications for the 1973 examination and if eligible to take one chance.

- (ii) as his first chance, if invalided during 1972 after the closing date prescribed for receipt of applications for the 1972 examination or during 1973 prior to the closing date prescribed for receipt of applications for the 1973 examination, and if eligible to take two chances.

- (iii) as his second chance, if invalidated during 1971 after the closing date prescribed for receipt of applications for the 1971 examination, or during 1972 prior to the closing date prescribed for receipt of applications for the 1972 examination and if eligible to take two chances;
- (iv) as his second chance, if invalidated during 1972 after the closing date prescribed for receipt of applications for the 1972 examination, and if he was due for release during 1973.

NOTE 1.—The provisions contained in (a) above will not apply to candidates invalidated owing to a disability attributable to or aggravated by military service during 1971, 1972 and 1973 who were due for release in 1971, 1972 and 1973 respectively.

NOTE 2.—The provisions contained in clauses (i) and (ii) of (a) above will not apply to candidates invalidated owing to a disability attributable to or aggravated by military service during 1972 who were due for release in 1973.

NOTE 3.—The provisions contained in clause (iii) of (a) above will not apply to candidates invalidated owing to a disability attributable to or aggravated by military service during 1971 who were due for release in 1972.

(b) An Emergency Commissioned/Short Service Commissioned Officer who joined the pre-Commission training in the Armed Forces before 10th January 1968 but was commissioned on or after 10th January 1968, may take the examination to be held in 1973, subject to the conditions indicated below:—

- (i) as his second chance, if he was released in 1972 and was eligible to take two chances;
- (ii) as his second chance, if invalidated during 1970 after the closing date prescribed for receipt of applications for the 1970 examination, or during 1971 prior to the closing date prescribed for receipt of applications for the 1971 examinations, and if eligible to take two chances.

NOTE.—The provisions contained in item (ii) above will not apply to candidates invalidated owing to a disability attributable to or aggravated by military service during 1970 and 1971 who were due for release in 1970 and 1971 respectively.

N.B. Candidates who in terms of the provisions of this rule, are eligible to take their second chance in 1974, may avail of the same, if the provisions of the Rules referred to in rule 1 of these Rules are extended by Government beyond the 28th January, 1974.

10. (a) A candidate must hold a degree of any of the Universities enumerated in Appendix I or must possess any of the qualifications mentioned in Appendix I-A.

Provided that—

- (i) In exceptional cases the Union Public Service Commission may treat a candidate, who has not any of the foregoing qualifications, as a qualified candidate if he has passed examination conducted by other institutions, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.
- (ii) a candidate who is otherwise qualified but who has taken a degree from a foreign university which is not included in Appendix I, may also apply to the Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

(b) A candidate who, when he appeared before a Services Selection Board as a candidate for the grant of Emergency Commission/Short Service Commission in the Armed Forces was studying in a recognised institution e.g., a university/an institution affiliated to a university for the award of any of the qualifications prescribed in sub-Rule (a) of this Rule, but who having discontinued his studies because of joining the Armed Forces, had not acquired such qualification will also be eligible to appear at the examination.

NOTE.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at this examination *vide* Sub-Rule (a) of this Rule, but has

not been informed of the result may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply provided the qualifying examination is completed before the commencement of this examination. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination, as soon as possible and in any case not later than two months after the commencement of this examination.

11. A candidate who is appointed to the I.A.S. or I.F.S. on the results of an earlier examination will not be eligible to compete at this examination.

A candidate who is appointed to a Service mentioned in column (ii) below on the results of an earlier examination will be eligible subject to the provisions of these rules to compete at this examination only for Services mentioned against that Service in column (iii) below.

Sl. No.	Service to which appointed	Service for which eligible to compete
(i)	(ii)	(iii)
1. Indian Police Service		I.A.S., I.F.S. and other Central Services, Class I.
2. Central Services Class I		I.A.S., I.F.S. and I.P.S. other than I.F.S.
3. Central Services, Class II including Civil and Police Services in Union Territories		I.A.S., I.P.S., I.F.S. and other Central Services Class I.

12. A candidate serving in the Armed Forces must submit his application for this examination to the Officer Commanding his unit who will forward it to the Union Public Service Commission. A candidate who is himself the officer Commanding his unit must submit his application through his next superior officer.

All other candidates in Government Service whether in permanent or temporary capacity or as work-charged employees other than casual or daily-rated employees must obtain prior permission of the Head of the Department to appear for the Examination.

13. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

14. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

15. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission.

16. A candidate who is or has been declared by the Commission guilty of impersonation or of submitting fabricated documents or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination or of using or attempting to use unfair means in the examination hall or of misbehaviour in the examination hall may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution:—

(a) be debarred permanently or for a specified period;

(i) by the Commission, from admission to any examination or appearance at any interview held by the Commission for selection of candidates; and

(ii) by the Central Government from employment under them;

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules, if he is already in service under Government.

17. Candidates who obtain such minimum qualifying marks

in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for the *viva voce*.

18. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate, and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes can not be filled on the basis of the general standard be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota subject to the fitness of these candidates for appointment to the Services, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

19. (a) If on the result of the examination, a sufficient number of qualified candidates is not available to fill the vacancies reserved for released Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers, the unfilled vacancies shall be filled in the manner prescribed by the Government in his behalf.

(b) If the number of qualified candidates is larger than the number of vacancies reserved for released Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers, the names of those who are not appointed shall be kept on the waiting list(s) for appointment against the quota of vacancies reserved for them in the succeeding year(s), provided reservations in favour of released Emergency Commissioned/Short Service Commissioned Officers are continued beyond 28-1-1974 by the Government of India.

20. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

21. Due consideration will be given, at the time of making appointments on the results of this examination, to the preferences expressed by a candidate for various Services at the time of his application.

Provided that candidate who is appointed to the I.A.S. or I.F.S. on the results of an earlier examination will not be considered for allotment to any other Service on the results of this examination.

Provided further that a candidate who is appointed to a Service mentioned in column (ii) below on the results of an earlier examination will be considered only for allotment to Services mentioned against that service in column (iii) below, on the results of this examination.

Sl. No.	Service to which appointed	Service to which allotment will be considered
1.	Indian Police Service	I.A.S. I.F.S., and other Central Services, Class I
2.	Central Services Class I Other than I.F.S.	I.A.S., I.F.S., and I.P.S.
3.	Central Services, Class II including Civil and Police Services in Union Territories.	I.A.S., I.P.S., I.F.S. and other Central Services Class I.

22. Success in the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service.

23. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate who after such medical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Any candidate called for the *viva voce* by the Commission may be required to undergo medical examination.

Note.—In order to prevent disappointment candidates are advised to have themselves examined by a Government Medical Officer of the standing of a Civil Surgeon, before applying for admission to the examination. Particulars of the nature of the medical test to which candidates will be subjected before appointment and of the standards required are given in Appendix IV to these Rules. For the disabled

ex-Defence Services personnel the standards will be relaxed consistent with the requirements of each Service.

24. No person

- who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

25. Under no circumstances, the officers appointed to the Indian Foreign Service will be allowed to marry persons other than those of Indian nationality.

26. Candidates are informed that some knowledge of Hindi prior to entry into Service would be of advantage in passing departmental examinations which candidates have to take after entry into Service.

27. Brief particulars relating to the Services to which recruitment is being made through this examination are given in Appendix III.

V. RANGANATHAN, Under Secy.

APPENDIX I

List of Universities approved by the Government of India (vide Rule 10)

INDIAN UNIVERSITIES

Any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India and other educational institutions established by an Act of Parliament, or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956.

UNIVERSITIES IN BURMA

The University of Rangoon.
The Mandalay University.

ENGLISH AND WELSH UNIVERSITIES

The Universities of Birmingham, Bristol, Cambridge, Durham, Leeds, Liverpool, London, Manchester, Oxford, Reading, Sheffield and Wales.

SCOTTISH UNIVERSITIES

The Universities of Aberdeen, Edinburgh, Glasgow and St. Andrews.

IRISH UNIVERSITIES

The University of Dublin (Trinity College).
The National University of Ireland.
The Queen's University, Belfast.

UNIVERSITIES IN BANGALADESH

The University of Punjab.
The University of Sind.

UNIVERSITIES IN BANGALADESH

The Dacca University.
The Rajshahi University.

UNIVERSITY IN NEPAL

The Tribhuvan University, Kathmandu.

APPENDIX 1-A

List of qualifications recognised for admission to the examination (vide Rule 10).

- Shastri of Kashi Vidyapith, Varanasi.
- French Examination "Propedeutique."

3. Diploma in Rural Services of the National Council of Rural Higher Education.

4. Diploma in Rural Services of the Visva Bharati University.

5. National Diploma in Commerce of All India Council for Tech. Education.

6. National Diploma in Engineering or Technology of the All India Council for Technical Education, recognised by the Government for recruitment to superior Services and posts under the Central Government.

7. Higher Course of Sri Aurobindo International Centre of Education, Pondicherry, provided that the Course has been successfully completed as a "full student."

8. Diploma in Mining Engineering of the Indian School of Mines, Dhanbad.

9. Diploma in the field of Humanities and Natural Sciences attesting graduation from a Higher Educational Establishment in the U.S.S.R. without defending first scientific thesis but having passed the State Examinations.

10. Shastri (with English) or Old Shastri or Sampurna Shastri examination with special examination in additional subjects with English as one of the subjects, i.e. Varishta Shastri of Varanaseya Sanskrit Vishwa Vidyalaya, Varanasi.

11. Alankar degree of Gurukul Vishwa Vidyalaya, Kangri, Hardwar.

12. Bachelor of Arts (B.A.) and the Bachelor of Science (B.S.) degrees awarded by the American University of Beirut, Lebanon.

APPENDIX II

Plan of the Examination

1. The competitive examination comprises:

(a) Written examination in three subjects as shown in para 2 below carrying a maximum of 450 marks.

(b) *Viva voce* for such of the candidates as may be called by the Commission carrying a maximum of 250 marks of which 50 marks shall be assigned to the Evaluation of the Record of Service in the Armed Forces.

2. The subjects of the written examination, the time allowed and the maximum marks allotted to each subject will be as follows:

Subject	Time allowed	Maximum Marks
(i) Essay	3 hours	150
(ii) General English	3 hours	150
(iii) General Knowledge	3 hours	150

3. The syllabus for the examination will be as in the attached Schedule.

4. (a) The question papers in 'Essay' and 'General Knowledge', vide items (i) and (iii) respectively in para 2 above, may be answered in English, or in any one of the languages mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution, viz., Assamese, Bengali, Gujarati, Hindi, Kanada, Kashmiri, Malayalam, Marathi, Oriya, Punjabi, Sanskrit, Sindhi, Tamil, Telugu and Urdu. Candidates exercising the option to answer both the papers in a language other than English must choose the same language for both the papers. The option will apply to a complete paper and not to a part thereof.

(b) The question paper in 'General English' vide item (ii) in para 2 above must be answered in English.

NOTE I—A candidate desirous of answering the question paper(s) mentioned in para 4(a) above in a language other than English must clearly indicate, in column 34 of the Application Form, the name of that language against the paper(s) concerned. If no entry is made in the said column in respect of either or both of the papers, it will be assumed that the paper/papers will be answered in English. The option once exercised shall be treated as final and no request for alteration or addition in the said column shall be entertained.

NOTE II—Candidates exercising the option to answer the paper(s) referred to in para 4(a) above in any of the languages mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution will be required to write their answers in the respective script indicated below:—

Language	Script
1. Assamese	Assamese
2. Bengali	Bengali
3. Gujarati	Gujarati
4. Hindi	Devanagari
5. Kannada	Kannada
6. Kashmiri	Persian
7. Malayalam	Malayalam
8. Marathi	Devanagari
9. Oriya	Oriya
10. Punjabi	Gurmukhi
11. Sanskrit	Devanagari
12. Sindhi	Devanagari or Arabic
13. Tamil	Tamil
14. Telugu	Telugu
15. Urdu	Persian

*Candidates exercising the option to answer the paper(s) referred to in para 4(a) above in *Sindhi*, must also indicate in column 33 of the application form, the name of the *particular script* (Devanagari or Arabic) which they will adopt.

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

7. If a candidate's handwriting is not easily legible a deduction will be made on this account from the total marks otherwise accruing to him.

8. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

9. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with the due economy of words in all subjects of the examination.

SCHEDULE

(vide PARA 3 OF APPENDIX II)

PART 'A'

1. *Essay*.—Candidates will be required to write an essay. A choice of subjects will be given. They will be expected to keep closely to the subjects of the essay, to arrange their ideas in orderly fashion, and to write concisely. Credit will be given for effective and exact expression.

2. *General English*.—Candidates will be required to answer question designed to test their understanding of English and workmanlike use of words. Some of the questions will be devised to test also their reasoning power, their capacity to perceive implications, and their ability to distinguish between the important and the less important. Passages will usually be set for summary or precis. Credit will be given for concise and effective expression.

3. *General Knowledge*.—Including knowledge of current events and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. The paper will also include questions on History of India, and Geography of a nature which candidates should be able to answer without special study, and questions on the teachings of Mahatma Gandhi.

PART 'B'

Viva Voce: The candidates will be examined by a Board who will have before them a record of the career of each candidate, including service in the Armed Forces. The candidate will be asked questions on matters of general interest as also on his experience in the Armed Forces. The object of the *Viva Voce* is an assessment of the suitability of the candidate for the Services for which he has applied by a Board of competent and unbiased observers.

The technique of the *Viva Voce* is not that of a strict cross examination, but of a natural though directed and purposive conversation, which is intended to reveal the mental qualities of the candidate e.g., mental alertness and initiative, critical powers of assimilation, clear and logical exposition, balance of judgement, variety and depth of interest, ability for social cohesion and leadership, intellectual and moral integrity.

APPENDIX III

The Appendix briefly describes the conditions of service as applicable to candidates recruited through the regular I.A.S. etc. Examination. The seniority and pay of the candidates who may be appointed on the results of this examination would be regulated in accordance with the special orders issued by the Government in this behalf.

1. *Indian Administrative Service.*—(a) Appointments will be made on probation for a period of two years which may be extended. Successful candidates will be required to undergo probation at such place and in such manner and pass such examinations during the period of probation as the Government of India may determine.

(b) If, in the opinion of Government, the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) On the conclusion of his period of probation, Government may confirm the officer in the Service or, if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) An officer belonging to the Indian Administrative Service will be liable to serve anywhere in India or abroad either under the Central Government or under a State Government.

(e) Scales of pay :—

Junior Scale—Rs. 400—400—500—40—700—EB—30—1,000 (18 years).

Senior Scale—

(i) Time Scale—Rs. 900 (6th year or under)—50—1,000—60—1,600—50—1,800 (22 years).

(ii) Selection Grade—Rs. 1,800—100—2,000.

In addition there are super-time scale posts carrying pay between Rs. 2,150 and Rs. 3,500, to which Indian Administrative Service Officers are eligible for promotion.

Dearness allowance will be admissible in accordance with the orders issued from time to time.

A probationer will start on the Junior time scale and permitted to count the period spent on probation towards leave, pension or increment in the time scale.

(f) *Provident Fund.*—Officers of the Indian Administrative Service are governed by the All India Services (Provident Fund) Rules, 1955.

(g) *Leave.*—Officers of the Indian Administrative Service are governed by the All India Services (Leave) Rules, 1955.

(h) *Medical Attendance.*—Officers of the Indian Administrative Service are entitled to medical attendance benefits admissible under the All India Services (Medical Attendance) Rules, 1954.

(i) *Retirement benefits.*—Officers of the Indian Administrative Service appointed on the basis of Competitive Examination are governed by the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958.

2. *Indian Foreign Service.*—(a) Appointment will be made on probation for a period which will not ordinarily exceed 3 years. Successful candidates will be required to pursue a course of training in India for approximately twenty-one months. Thereafter they may be posted as Third Secretaries or Vice-Consuls in Indian Missions whose languages are allotted to them as compulsory languages. During their period of training the probationers will be required to pass one or more departmental examinations before they become eligible for confirmation in Service.

(b) On the conclusion of his period of probation to the satisfaction of Government and on his passing the prescribed examinations, the Probationer is confirmed in his appointment. If however, his work or conduct has, in the opinion of the Government, been unsatisfactory, Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such period as they may think fit or may revert him to his substantive post, if any.

(c) If, in the opinion of Government the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or above then he

is not likely to prove suitable for the Foreign Service, Government may either discharge him forthwith or may revert him to his substantive post, if any.

(d) Scales of pay :—

Junior Scale—Rs. 400—400—500—40—700—EB—30—1,000.

Senior Scale—Rs. 900 (6th year or under)—50—1,000—60—1,600—50—1,800.

In addition there are super-time scale posts carrying pay between Rs. 1,800 and Rs. 3,500 to which I.F.S. Officers are eligible for promotion.

(e) A probationer will receive the following pay during probation :—

First Year—Rs. 400 per mensem.

Second Year—Rs. 400 per mensem.

Third Year—Rs. 500 per mensem.

NOTE 1.—A probationer will be permitted to count the periods spent on probation towards leave, pension or increment in the time scale.

NOTE 2.—Annual increments during probation will be contingent on the probationer passing the prescribed tests, if any, and showing progress to the satisfaction of Government. Increments can also be earned in advance by passing the departmental examination.

NOTE 3.—The pay of a Government servant who held a permanent post other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment as a probationer will be regulated subject to the provision of F.R. 22-B(I).

(f) An officer belonging to the Indian Foreign Service will be liable to serve anywhere inside or outside India.

(g) During service abroad I.F.S. officers are granted foreign allowances according to their status to compensate them for the increased cost of living and of servants and also to meet their special responsibilities in regard to entertainment. In addition, the following concessions are also admissible to I.F.S. officers during service abroad :—

(i) Free furnished accommodation according to status.

(ii) Medical attendance facilities under the Assisted Medical Attendance Scheme.

(iii) Return air passage to India up to a maximum of two, for special emergencies such as the death or serious illness of an immediate relation in India or marriage of daughter.

(iv) Annual return air passage for children between the ages of 8 and 21 studying in India to visit the parents during the long vacations, subject to certain conditions.

(v) An allowance for the education of children up to a maximum of two children between the ages of 5 and 18 at rates prescribed by Government from time to time.

(vi) Outfit allowance at the time of departure for training abroad and on confirmation in the service. Outfit allowance is also granted at various stages of an officer's career in accordance with the prescribed rules. Special outfit allowance is admissible in addition to the ordinary outfit allowance to officers posted in countries where abnormally hard climatic conditions exist.

(vii) Home leave passages for officers, their families and servants after a minimum of 2 years service abroad.

(h) The Revised Leave Rules, 1933, as amended from time to time will apply to Members of the Service subject to certain modifications. For Service abroad I.F.S. Officers are entitled under the I.F.S. (PLCA) Rules, 1961, to an additional credit of leave to the extent of 50 per cent of leave admissible under the Revised Leave Rules.

(i) *Provident Fund.*—Officers of the Indian Foreign Service are governed by the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960.

(j) *Retirement Benefits.*—Officers of the Indian Foreign Service appointed on the basis of competitive examination are governed by the Limerised Pension Rules, 1950.

k) While in India officers are entitled to such concessions as are admissible to other Government Servants of equal and similar status.

3. *Indian Police Service*.—(a) Appointment will be made on probation for a period of two years which may be extended. Successful candidates will be required to undergo probation at such place and in such manner and pass such examinations during the period of probation as Government may determine.

(b)

(c)

As in clauses (b) and (c) for the Indian Administrative Service.

(d) An officer belonging to the Indian Police Service will be liable to serve anywhere in India or abroad either under the Central Government or under a State Government.

(e) Scales of pay :—

Junior Scale.—Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950 (18 years).

Senior Scale.—Rs. 740 (6th year or under)—40—1,100—50/2—1,250—50—1,300 (22 years).

Selection Grade.—Rs. 1,400.

Deputy Inspector General of Police.—Rs. 1,600—100—2,000.

Commissioners of Police, Calcutta and Bombay.—Rs. 1,800—100—2,000.

Inspector General of Police.—Rs. 2,500—125/2—2,750.

Director, Intelligence Bureau.—Rs. 3,000.

Dearness allowance will be admissible in accordance with the orders issued from time to time.

(f) As in clauses (f), (g), (h), and (i) for the Indian Administrative Service.

(h)

(i)

4. *The Central Information Service, Grade II (Class I)*.—(a) The Central Information Service consists of posts all over India in various media organisations of the Ministry of Information and Broadcasting requiring journalistic and similar professional qualifications. The service was constituted with effect from 1st March, 1960.

(b) The Service has at present the following grades :

Grade	Scale of Pay
Class I	
Selection Grade	Rs. 2500—125/2—2750.
Senior Administrative Grade (Senior Scale)	Rs. 1,800—100—2,000.
Junior Administrative Grade (Junior Scale)	Rs. 1,600—100—1,800
Grade I	Rs. 1,300—60—1,600
Grade II	Rs. 1,100—50—1,400
Grade III	Rs. 700—40—1,100—50/2—1,250.
Grade IV	Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950.
Class II (Gazetted)	
Grade III	Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800.
Class II (Non-Gazetted) Grade IV	Rs. 270—10—290—15—410—EB—15—485.

(c) Direct recruitment is provided to the percentage of vacancies as specified below, in the following grades of the service :—

Junior Administrative Grade (Junior Scale)	12-1/2%
Grade I	25%
Grade II	50%
Grade IV	100%

Vacancies in Grade III are filled by promotion, on selection basis, on the recommendations of a Departmental Promotion Committee from amongst Grade IV officers.

50% permanent and all temporary vacancies in Grade II, 75% vacancies in Grade I and 87 1/2% vacancies in the Junior Administrative Grade (Junior Scale) are filled by promotion by selection from amongst officers holding duty posts in the next lower grades.

Vacancies in the Selection Grade, Senior Administrative Grade (Senior Scale), and Senior Administrative Grade (Junior Scale), and Junior Administrative Grade (Senior Scale) are filled by selection from amongst officers holding duty posts in the respective next lower grade, in case no suitable officer is available for such promotion, recruitment to such vacancies in the Selection Grade and Senior Administrative Grade is to be made in consultation with the Union Public Service Commission. Vacancies in the Junior Administrative Grade, (Senior Scale) are filled by promotion on the basis of seniority-cum-fitness from amongst officers holding duty posts in the Junior Scale of that Grade.

The Government can fill, in consultation with the Union Public Service Commission, in any grade a number of posts not exceeding 10% of the strength of that grade, by the appointment of officers of State Publicity Organisations on deputation, for such period not exceeding five years, as the Government may specify. The posts so filled are taken into account in determining the number of posts to be filled by promotion or by direct recruitment.

(d) (i) Direct recruits to Grade II will be on probation for two years. During probation they will be given training in the Indian Institute of Mass Communications on a newspaper or news agency, in different media units of the Ministry of Information and Broadcasting and at the Lal Bahadur Shastri Academy of Administration, Mussoorie. The total period of training will be about 20 months. The period and nature of training will be liable to alteration by Government. During the training, they will have to pass the 'end-of-the-course test' at the Lal Bahadur Shastri Academy of Administration, Mussoorie, and first and second departmental tests at the Indian Institute of Mass Communications, which will include a language test. Failure to pass the departmental test during the training period involves liability to discharge from service or reversion to substantive post, if any, on which the candidate may hold lien.

(ii) On the conclusion of period of probation Government may confirm the direct recruits in their appointments in accordance with the rules in force. If the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory, he may be discharged from service or his period of probation extended for such period as the Government may deem fit. If his work or conduct is such as to show that he is unlikely to become an efficient Grade II officer of the Service, he may be discharged forthwith.

(iii) Probationers shall start on the minimum of the time scale of Grade II. On passing the first departmental test, the pay of Probationers will be raised to Rs. 450/- in the scale of pay of Grade II of the Central Information Service. On passing the second Departmental test, the pay will be fixed at the stage of Rs. 480/-. The pay beyond the stage of Rs. 480/- will not be allowed unless they have completed 4 years of service, subject to other conditions as may be found necessary. In case any of the Probationer does not pass the 'end-of-the-course-test' at the Lal Bahadur Shastri Academy of Administration, Mussoorie, his first increment will be postponed by one year from the date on which he would have drawn it or up to the date on which under the departmental regulations the second increment accrues, whichever is earlier.

(iv) The pay of a Government servant who held a permanent post, other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment as probationer, will, however, be regulated subject to the provisions of F.R. 22-B(I).

(e) Government may require any member of the Service to hold for a specified period a post in the publicity organisation of a Union Territory.

(f) Government may post an officer to hold a field post in any organisation under the Ministry of Information and Broadcasting.

(g) As regards leave, pension and other conditions of service officers of the Central Information Service will be treated like other Class I and Class II officers.

NOTE.—It should be clearly understood by probationers that their appointment would be subject to any change in the constitution of the Central Information Service which the Government of India may think proper to make from time to time, and that they would have no claim for compensation in consequence of any such changes.

5. *Indian Audit and Accounts Service.*

6. *Indian Customs and Central Excise Service.*

7. *Indian Defence Accounts Service.*

(a) Appointments will be made on probation for a period of 2 years, provided that this period may be extended if the officer on probation has not qualified for confirmation by passing the prescribed departmental examinations. Repeated failures to pass the departmental examinations within a period of 3 years will involve loss of appointment.

(b) If, in the opinion of Government or the Comptroller and Auditor General, as the case may be, the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory, or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) On the conclusion of his period of probation Government or the Comptroller and Auditor General as the case may be may confirm the officer in his appointment or if his work or conduct has, in the opinion of Government or the Comptroller and Auditor General, as the case may be, been unsatisfactory Government may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit, provided that in respect of appointments to temporary vacancies there will be no claim to confirmation.

(d) In view of the possibility of the separation of Audit from Accounts and other reforms the constitution of the Indian Audit and Accounts Service is liable to undergo changes and any candidate selected for that Service will have no claim for compensation in consequence of any such changes and will be liable to serve either in the separated Accounts offices under the Central or State Government or in the Statutory Audit Offices under the Comptroller and Auditor General and to be absorbed finally if the exigencies of service required it in the cadres on which posts in the separated Accounts Offices under the Central or State Governments may be borne.

(e) The Indian Defence Accounts Service carries with it a definite liability for service in any part of India as well as for Field Service in or out of India.

(f) Scales of pay :—

Indian Audit and Accounts Service :

Time Scale of I.A. & A.S.—Rs. 400—400—450—30—510—EB—700—40—1,100—50/2—1,250.

Junior Administrative Grade.—Rs. 1,300—60—1,600.

Accountant General.—Rs. 1,800—100—2,000—125—2,250.

Additional Deputy Comptroller & Auditor General's Grade.—Rs. 2,500—125/2—2,750.

Deputy Comptroller & Auditor General of India Rs. 3,000.

NOTE 1.—Probationary Officers will start on the minimum of the time scale of I.A. & A.S. and will count their service for increments from the date of joining.

NOTE 2.—The officers on probation will not be allowed pay above the stage of Rs. 400 unless they pass the departmental examination in accordance with the rules which will be prescribed from time to time.

NOTE 3.—In the case of probationers who do not pass the 'End-of-the-Course' Test at the Lal Bahadur Shastri Academy of Administration, Mussoorie, the first increment raising their pay to Rs. 450 shall be postponed by one year from the date on which they would have drawn it or up to the date on which, under the Departmental regulations, the second increment accrues to them, whichever is earlier. The failed candidates will not be required to take the test again.

NOTE 4.—The pay of a Government servant who held a permanent post, other than a tenure post, in a substantive capacity prior to his appointment as probationer, will however be regulated subject to the provisions of F.R. 22(B)(1).

Indian Customs and Central Excise Service :

Time Scale :—

Superintendent of Central Excise, Class I. Assistant Collector of Central Excise, Assistant Collector of Customs.—Rs. 400—400—450—30—510—EB—700—40—1,100—50/2—1,250.

Deputy Collector of Customs, Deputy Collector of Central Excise, Additional Collector.—Rs. 1,300—60—1,600.

Appellate Collector of Customs & Central Excise, Collector of Customs, Collector of Central Excise.—Rs. 1,800—100—2,000—125—2,250.

(a) Appointments will be made on probation for a period of 2 years, provided that this period may be extended if the officer on probation has not qualified for confirmation by passing the prescribed departmental examinations. Repeated failures to pass the departmental examinations within a period of 2 years will involve loss of appointment.

(b) If, in the opinion of the Government, the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory, or shows that he is unlikely to become efficient Government may discharge him forthwith.

(c) On the conclusion of his/her period of probation Government may confirm the officer in his/her appointment or if his/her work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him/her from the Service or may extend his/her period of probation for such further period as Government may think fit, provided that in respect of appointments to temporary vacancies there will be no claim to confirmation.

(d) The Indian Customs and Central Excise Service Class I. carries with it a definite liability for service in any part of India.

NOTE 1.—A probationary officer will start on the minimum of the time scale of pay of Rs. 400—400—450—30—510—EB—700—40—1,100—50/2—1,250, and will count his/her service for increments from the date of joining.

NOTE 2.—An officer on probation will not be allowed pay in the time scale above the stage of Rs. 400/- unless he/she passes the prescribed departmental examinations in accordance with the rules which will be prescribed from time to time.

NOTE 3.—The pay of a Government servant who held a permanent post, other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment as a probationer in the Indian Customs and Central Excise Service, Class I will be regulated subject to the provisions of F.R. 22-B(1).

NOTE 4.—During the period of probation an officer will be posted to Central Excise Department/Customs Department/Narcotics Department for departmental training and to the Lal Bahadur Shastri Academy of Administration, Mussoorie for a Foundational Course training. At the end of the training at Mussoorie he/she will have to pass the 'end-of-the-course' test. He/she will have to pass Part I and Part II of the Departmental Examination. On passing the 'end-of-the-course' test and one of the parts of the Departmental Examination he/she will be granted a first advance increment raising his/her pay to Rs. 450/-. On passing both the parts of the Departmental Examination, he/she will be granted the second advance increment raising his/her pay to Rs. 480/-. His/her pay beyond the stage of Rs. 480/- will not be allowed unless he/she has completed 4 years of service, subject to such other conditions as may be found necessary.

In case, a probationer does not pass the 'end-of-the-course' test at the Academy, his/her first advance increment will be postponed by one year from the date on which he/she would have drawn it or up to the date on which under the departmental regulations, the second advance increment accrues, whichever is earlier.

NOTE 5.—It should be clearly understood by the probationers that their appointment would be subject to any change in the constitution of the Indian Customs & Central Excise Service, Class I, which the Government of India may think proper to make from time to time, and that they would have no claim for compensation in consequence of any such change.

Indian Defence Accounts Service :

Time Scale :—

Rs. 400—400—450—480—510—EB—700—40—1,100—1,100—1,150—1,150—1,200—1,200—1,250.

Junior Administrative Grade.

Rs. 1,300—60—1,600.

Rs. 1,600—100—1,800 (Selection Grade).

Senior Administrative Grade.

Rs. 1,800—100—2,000—125—2,250.

Controller General of Defence Accounts—Rs. 2,750 (fixed).

NOTE 1.—Probationary officers will start on the minimum of the time scale and will count their service for increments from the date of joining. The pay of a Government servant who held a permanent post, other than a tenure post in a

NOTE 2.—The officers on probation will not be allowed to pay above the stage of Rs. 400 unless they pass the departmental examination in accordance with the rules in force from time to time; provided further that in the case of an officer who does not pass the 'end-of-the-course' test at the Lal Bahadur Shastri Academy of Administration, Mussoorie his first increment shall be postponed by one year from the date on which he would have drawn it on passing Part I of the Departmental Examination or up to the date on which the second increment accrues to him on passing Part II of the aforesaid examination, whichever is earlier.

8. *Indian Income-tax Service, Class I.*—(a) Appointments will be made on probation for a period of 2 years, provided that his period may be extended if the officer on probation has not qualified for confirmation by passing the prescribed departmental examinations. Repeated failures to pass the departmental examinations within a period of 3 years will involve loss of appointment.

(b) If, in the opinion of Government, the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or show that he is unlikely to become an efficient Income Tax officer the Government may discharge him forthwith.

(c) On the conclusion of his period of probation, Government may confirm the officer in his appointment or if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit, provided that in respect of appointments to temporary vacancies there will be no claim to confirmation.

(d) If the power to make appointments in the service is delegated by Government to any officer, that officer may exercise any of the powers of Government described in the above clauses.

(e) Scales of Pay :—

Income-tax officer Class I—

Rs. 400—400—450—30—510—EB—700—40—1,100—50/2—1,250.

Assistant Commissioner of Income Tax—

Rs. 1,300—60—1,600.

Additional Commissioner of Income Tax—

Rs. 1600—100—1800.

Commissioner of Income-tax—

Rs. 1,800—100—2,000—125—2,250.

(f) During the period of probation, an officer will undergo training at the Lal Bahadur Shastri Academy of Administration, Mussoorie and the Indian Revenue Service (Direct Taxes) Staff College, Nagpur. At the end of training at Mussoorie, he/she will have to pass the 'end-of-the-course' test. In addition, I & II departmental examination will also have to be passed during the period of probation. On passing the end-of-the-course test and the 1st departmental Examination, his/her pay will be raised to Rs. 450. On passing the 2nd departmental examination, the pay will be raised to Rs. 480. The pay beyond the stage of Rs. 480 will not be allowed unless he/she is confirmed and has completed 4 years of service, subject to such other conditions as may be found necessary.

In case he/she does not pass the end-of-the-course test at the Academy, the first increment will be postponed by one year from the date on which he/she would have drawn it or up to the date on which under the departmental regulations, the second increment accrues, whichever is earlier.

NOTE 1.—The officer on probation will not be allowed to pay above the stage of Rs. 400 unless he passes the departmental examinations in accordance with the rules which will be prescribed from time to time.

NOTE 2.—It should be clearly understood by probationers that their appointment would be subject to any change in the constitution of the Income-tax Service Class I which the Government of India may think proper to make from time to time and that they would have no claim for compensation in consequence of any such changes.

9. *Indian Ordnance Factories Service, Class I (Non-Technical Cadre).*

(a) Selected candidates will be appointed as Assistant Managers (on probation). The period of probation will be two years which may be reduced or extended by the Government on the recommendation of the Director General, Ordnance Factories. An Assistant Manager (on probation) will undergo such training as shall be provided by Government and may be required to pass such departmental and language tests as Government may prescribe. The language tests will include a test in Hindi.

On the conclusion of his period of probation, Government will confirm the officer in his appointment. If, however, during or at the end of the period of probation his work or conduct has, in the opinion of Government, been unsatisfactory, Government may either discharge him or extend his period of probation for such period as Government may think fit, provided that before orders of discharge are passed, the officer shall be apprised by competent authority of the grounds on which it is proposed to discharge him and be given an opportunity to show cause against it.

(b) The Assistant Managers (on probation) in the Indian Ordnance Factories Service would draw pay in the prescribed scale of pay of Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950. During the period of probation, they will be required to undergo training in the various branches of the Department and in the Lal Bahadur Shastri Academy of Administration, Mussoorie in a foundational course of training. On passing the 'end-of-the-course-test' and the Departmental Examination, they will be entitled to grant of advance increment rising their pay to Rs. 450/- per month and Rs. 480/- per month from the date following the date on which the last paper of the 1st and 2nd Departmental examination, in which they pass, is held. Grant of further increment will be regulated according to their position in the time scale and after they have been confirmed in the grade.

In case any of the Assistant Managers (On probation) does not pass the 'end-of-the-course-test' at the Lal Bahadur Shastri Academy of Administration, Mussoorie, his first increment will be postponed by one year from the date on which he would have drawn it or up to the date on which under the departmental regulations, the second increment accrues, whichever is earlier.

(c) (i) Selected candidates shall, if so required be liable to serve as Commissioned Officers in the Armed Forces for a period of not less than four years including the period spent on training, if any; provided that such person (i) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment and (ii) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

(ii) The candidates shall also be subject to Civilians in Defence Services (Field Service Liability) Rules 1957, published under S.R.O. No. 92 dated 9th March 1957. They will be medically examined in accordance with the medical standards laid down therein.

(d) The following are the rates of pay admissible:—

Junior Scale		
Assistant Manager Technical	Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950.	
Staff Officer.		
Senior Scale :		
Deputy Manager/Deputy Assistant Director, General, Ordnance Factories.	Rs. 700—40—1,100—50/2—1,250.	
Manager/Senior Deputy Assistant Director General, Ordnance Factories.	Rs. 1,100—50—1,400.	
Deputy General Manager/Assistant Director General, Ordnance Factories, Grade II.	Rs. 1,300—60—1,600—100—1,800.	
Assistant Director General Ordnance Factories, Grade I.	Rs. 1,800—100—2,000.	
Deputy Director General, Ordnance Factories.	Rs. 2,000—125—2,250.	

10. *Indian Postal Service*—(a) Selected candidates will be under training in this department for a period which will not ordinarily exceed two years. During this period they will be required to pass the prescribed departmental test.

(b) If, in the opinion of Government, the work, or conduct of an officer under training is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) On the conclusion of his period of training Government may confirm the officer in his appointment or if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the service or may extend his period of training for such further period as Government may think fit, provided that in respect of appointments to temporary vacancies there will be no claim to confirmation.

(d) If the power to make appointments in the service is delegated by Government to any officer, that officer may exercise any of the powers of Government described in the above clauses.

(e) Scales of Pay—

Time Scale : Rs. 400—400—450—30—510—EB—700—40—1,100—50/2—1,250 (Officers under training will draw pay in this time scale).

Directors of Postal Services : Rs. 1,300—60—1,600.

Postmasters-General : Rs. 1,800—100—2,000—125—2,250.

Members, Posts and Telegraphs Board : Rs. 2,500—125/2—2,750.

Senior Member, Posts and Telegraphs Board : Rs. 3,000.

(f) The probationers in the Indian Postal Service, would draw pay in the prescribed pay scale of Rs. 400—400—450—30—480—510—EB—700—40—1,100—50/2—1,250. During the period of probation, they will be required to undergo training in the various branches of the Department and in the Lal Bahadur Shastri Academy of Administration, Mussoorie, in a foundational course of training. At the end of training at Mussoorie they will have to pass the 'end-of-the-course' test. They will also have to pass the Departmental examination as prescribed under the Departmental Rules. On passing the 'end-of-the-course' test and the Departmental examination, their pay will be raised to Rs. 450. On confirmation, if they are confirmed on completion of the probationary period of two years their pay will be fixed at the stage of Rs. 480. Further regulation of their pay will, however, be determined by their position in the time scale.

In case, any of the probationers does not pass the 'end-of-the-course' test at the Lal Bahadur Shastri Academy of Administration, Mussoorie, his first increment will be postponed by one year from the date on which he would have drawn it or up to the date on which under the departmental regulations, the second increment accrues, whichever is earlier.

Provided that the pay of a Government servant who held a permanent post, other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment as a probationer will, be regulated subject to the provisions of F.R. 22-B(1).

(g) It should be clearly understood by the officers on probation that their appointment would be subject to any change in the constitution of the Indian Postal Service, which Government of India may think proper to make from time to time and that they would have no claim for compensation in consequence of any such changes.

(h) Selected candidates will be liable to serve in the Army Postal Service in India or abroad as required by Government.

11. *Indian Railway Accounts Service*—(a) Appointments will be made on probation for a period of 2 years during which the service will be liable to termination on three months notice on either side. The period of probation may be extended if the officer on probation has not qualified for confirmation by passing the prescribed departmental examinations.

Government may terminate the appointment of a Probationary Officer who fails to pass all the Departmental Examinations within three years of the date of appointment.

(b) Probationers of the Indian Railway Accounts Service will also be required to undergo training in two phases at the Railway Staff College, Baroda and to pass the tests prescribed by the College authorities. The tests in the Col-

lege are compulsory and a second chance, in the event of failure will not be given except in exceptional circumstances, and provides the record of the officer is such that such a relaxation may be made. They may, however, be put on to a working post on satisfactory completion of two years' training but they may not be confirmed till they have passed the tests at the Railway Staff College, Baroda, and passed the higher and lower departmental examinations.

(c) Probationers should have already or should pass during the period of probation an examination in Hindi in the Devnagari script of an approved standard. This Examination may be the 'Praveen' Hindi Examination conducted by the Directorate of Education, Delhi, on behalf of the Ministry of Home Affairs or one of the equivalent Examinations recognised by the Central Government.

No probationary officer can be confirmed or his pay in the time scale raised to Rs. 450 p.m. unless he fulfils this requirement; and failure to do so will involve liability to termination of service. No exemption can be granted.

(d) Officers (including probationers) of the Indian Railway Accounts Service recruited under these rules—

(a) will be governed by the Railway Pension Rules; and

(b) shall subscribe to the State Railway Provident Fund (non-contributory) under the rules of that Fund; as amended from time to time.

(e) Officers recruited under these rules shall be eligible for leave in accordance with the liberalised leave rules as in force from time to time.

(f) If for any reason not beyond his control a probationer in the Indian Railway Accounts Service wishes to withdraw from training or probation, he will be liable to refund the whole cost of his training and any other moneys paid to him during the period of his probation.

(g) If, in the opinion of Government the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory, or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(h) On the conclusion of his period of probation Government may confirm the officer in his appointment or if his work or conduct has in the opinion of Government, been unsatisfactory, Government may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(i) Scales of pay :—

(a) Junior Scale : Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950 (Authorised Scale).

Senior Scale : Rs. 700 (6th year and under)—40—1,100—50/2—1,250 (Authorised Scale).

Junior Administrative Grade : Rs. 1,300—60—1,600 (Authorised Scale).

Intermediate Administrative Grade : Rs. 1,600—100—1,800.

Senior Administrative Grade : Rs. 2,000—100—2,500.

(b) Increment from Rs. 400 to Rs. 450 will be stopped if they fail to pass the prescribed Departmental Examinations within the two years' probationary period. The probationary period will be extended and on their passing prescribed Departmental tests and being subsequently confirmed, their pay will, from the date following that on which the last departmental examinations ends, be fixed at the stage in the time scale which they would have otherwise attained but no arrears of pay would be allowed to them. In such cases the date of future increments will not be affected.

Advance increments from Rs. 400 to 450 and from Rs. 450 to Rs. 480 in the Junior Scale of Rs. 400—950 may, however, be granted during the period of probation as soon as the probationary officer passes the prescribed examinations. After the grant of advance increments, the pay of the officer will be regulated according to his normal position in the pay scale with reference to the year of service.

In case, any of the probationers does not pass the 'end-of-the-course' test at the Lal Bahadur Shastri Academy of Administration, Mussoorie, his first increment will be post-

poned by one year from the date on which he would have drawn it or up to the date on which under the departmental regulations the second increment accrues, whichever is earlier.

NOTE 1.—Probationary officers will start on the minimum of the Junior Scale and will count their service for increments from the date of joining. They will, however, be required to pass any departmental examination or examinations that may be prescribed before their pay can be raised from Rs. 400 p.m. to Rs. 450 p.m. in the time scale.

NOTE 2.—The pay of a Government servant who held a permanent post, other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment as probationer will, however, be regulated subject to the provisions of Rule 2018-A(1)-R.II F.R. 22-B(I).

12. *Military Lands and Cantonments Service (Class I and Class II)*—(a) (i) A candidate selected for appointment shall be required to be on probation for a period which shall not ordinarily exceed 2 years. During this period he shall be required to undergo such course of training in Cantonment and Land Administration as may be prescribed by Government for a period of not less than six months.

(ii) The pay of a Government servant who held a permanent post, other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment as probationer, will however, be regulated subject to the provisions of FR 22-B(1).

(b) During the period of probation a candidate will be required to pass the prescribed departmental examination.

(c) (i) If in the opinion of Government the work or conduct of an Officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him after apprising him of the grounds on which it is proposed to do so, and after giving him an opportunity to show cause in writing before such order is passed.

(ii) If at the conclusion of the period of probation an Officer has not passed the Departmental Examination mentioned in sub-para (b) above Government may, in its discretion, either discharge him from service or if the circumstances of the case so warrant, extend the period of probation for such period not exceeding one year as Government may consider fit.

(iii) On the conclusion of the period of probation Government may confirm an officer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him after apprising him of the grounds on which it is proposed to do so and after giving him an opportunity to show cause in writing before such order is passed, or extend the period of probation for such further period as Government may consider fit.

(d) If no action is taken by Government under Sub-para. (c) above, the period after the prescribed period of probation shall be treated as an engagement from month to month terminable on either side on the expiration of one calendar month's notice in writing provided that the Officer shall have no claim to confirmation.

(e) No annual increment which may become due will be admissible to a member of the Service during his probation, unless he has passed the departmental examination. An increment which was not thus drawn will be allowed from the date of passing the departmental examination.

(f) In case, any of the Probationers does not pass the 'end-of-the-course' test at the Lal Bahadur Shastri Academy of Administration, Mussoorie, his first increment will be postponed by one year from the date on which he would have drawn it or up to the date on which under the departmental regulations, the second increment accrues, whichever is earlier.

(g) The scales of pay are as under :—

<i>Administrative Posts</i>	
(i) Director, Military Lands and Cantonments.	Rs. 1,800—100—2,000—125—2,250.
(ii) Joint Director Military Lands and Cantonments.	Rs. 1,600—100—1,800
(iii) Deputy Director, Military Lands and Cantonments.	Rs. 1,300—60—1,600
(iv) Assistant Director, Military Lands and Cantonments.	Rs. 1,100—50—1,400

Class I

(v) Deputy Assistant Directors, Military Lands and Cantonments, Military Estate Officers, and Executive Officers.	Rs. 400—400—450—30—510—EB—700—40—1,100—50/2—1,250.
---	--

Class II

(vi) Executive Officers.	Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—830—35—900.
(vii) Assistant Military Estates Officers.	Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—830—35—900.

(h) (i) Class I Officers will normally be appointed as Deputy Assistant Directors, Military Estates Officers, and a Executive Officers to Class I Cantonments and Class II Cantonment to which sub-clause (i) of clause (e) of subsection (4) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 is applicable, (ii) Class II Executive Officers will normally be appointed to Cantonments other than those mentioned in (i) above.

(i) (i) All promotions will be made by selection (seniority being considered only when the claims of two or more candidates are equal on merits) by Government on the recommendations of a Departmental Promotion Committee appointed in this behalf by the Government. On promotion from Class II to Class I, pay will be regulated under the Fundamental Rules.

(ii) No officer will normally be promoted to Class I unless he has completed three years of service in Class II.

(j) The Revised Leave Rules, 1933, as amended from time to time will apply.

(k) No member of the Service shall undertake any work not connected with his official duties without the previous sanction of Government.

(l) The Military Lands & Cantonments Service carries with it a definite liability for service in any part of India as well as for Field Service in India.

13. *Indian Railway Traffic Service*

(a) Candidates selected for appointment will be appointed as probationary officers in the Indian Railway Traffic Service for a period of three years; during which they will undergo the training as indicated in para. (m) and put in a minimum period of one year's probation in a working post. If the period of training has to be extended in any case due to the training having not been completed satisfactorily the total period of probation will be correspondingly extended.

(b) If for any reasons not beyond his control a probationer in the Indian Railway Traffic Service wishes to withdraw from training or probation, he will be liable to refund the whole cost of his training and any other moneys paid to him during the period of his probation.

(c) Appointments to the service will be on a probation for a period of three years during which the service of the officers will be liable to termination by three months notice on either side. Probationary Officers will be required to undergo practical training for the first two years. Those who complete this training successfully and are otherwise considered suitable, will be placed in charge of a working post provided they have passed the prescribed departmental and other examinations. It must be noted that these examinations should as a rule be passed at the first chance and that save under exceptional circumstances a second chance will not be allowed. Failure to pass any of the examination may result in the termination of the service and will, in any case involve stoppage of increment.

At the end of one year in a working post, the Probationary Officers will be required to pass a final examination both practical and theoretical and will as a rule, be confirmed if they are considered fit for appointment in all respects. In cases where the probationary

period is extended for any reason, the drawal of the first and subsequent increments on their passing the departmental examinations, and on being confirmed, will be subject to the rules and orders in force from time to time.

- (d) Probationers should have already passed or should pass during the period of probation an examination in Hindi in the Dev Nagri script of an approved standard. This Examination may be the 'Praveen' Hindi Examination conducted by the Directorate of Education, Delhi, on behalf of the Ministry of Home Affairs or one of the equivalent examinations recognised by the Central Government.

No probationary officer can be confirmed or his pay in the time scale raised to Rs. 450 p.m. unless he fulfils the requirement; and failure to do so will involve liability to termination of service. No exemption can be granted.

- (e) Officers (including probationers) of the Indian Railway Traffic Service recruited under these rules :—

(a) will be governed by the Railway Pension Rules; and

(b) shall subscribe to the State Railway Provident Fund (non-contributory) under the rules of that Fund :

as amended from time to time.

- (f) Pay will commence from the date of joining service. Service for increments will also count from that date.

- (g) Officers recruited under these rules shall be eligible for leave in accordance with the liberalised leave rules as in force from time to time.

- (h) Officers will ordinarily be employed throughout their service on the railway to which they may be posted on first appointment and will have no claim as a matter of right to transfer to some other Railway. But the Government of India reserve the right to transfer such officers in the exigencies of service to any other railway or project in or out of India.

- (i) Scales of pay :—

Junior Scale : Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950 (Authorised Scale).

Senior Scale : 700—(6th year and under)—40—1,100—50/2—1,250 (Authorised Scale).

Junior Administrative Grade : Rs. 1,300—60—1,600 (Authorised Scale).

Intermediate Administrative Grade : Rs. 1,600—100—1,800 (Authorised Scale).

Senior Administrative Grade : Rs. 2,000—100—2,500 (Authorised Scale).

NOTE 1.—Probationary officers will start on the minimum of the Junior Scale and will count their service for increments from the date of joining. They will, however, be required to pass any departmental examination or examinations that may be prescribed before their pay can be raised from Rs. 400 p.m. to Rs. 450 p.m. in the time scale.

Increment from Rs. 400 to Rs. 450 will be stopped if they fail to pass the Departmental Examination within the first two years of the training and probationary period. The probationary period will be extended and on their passing the prescribed Departmental test and being subsequently confirmed their pay will from the date following that on which the last departmental examination ends, be fixed at the stage in the time scale which they would have otherwise attained but no arrears of pay would be allowed to them. In such cases the date of future increments will not be affected.

Advance increments from Rs. 400 to Rs. 450 and from Rs. 450 to 480 in the Junior Scale of Rs. 400—950 may, however, be granted during the period of probation as soon as the probationary officer passes the prescribed examinations. After the grant of advance increment, the pay of the Officer will be regulated according to his normal position in the pay scale, with reference to the year of Service.

In case, any of the probationers, does not pass the end-of-the-course test at the Lal Bahadur Shastri Academy of Administration, Mussoorie, his first increment will be postponed by one year from the date on which he would have drawn it or up to the date on which under the departmental regulations, the second increment accrues, whichever is earlier.

NOTE 2.—The pay of a Government servant who held a permanent post, other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment as probationer, will, however, be regulated subject to the provisions of Rule 2018-A(1)-R-II-[F. R. 22-B(1)].

- (j) The increments will be given for approved service only and in accordance with rules of the Department.

- (k) Promotions to the administrative grade are dependent on the occurrence of vacancies in the sanctioned establishment and are made wholly by selection; mere seniority does not confer any claim for such promotion.

- (l) Courses of training for probationers in the Indian Railway Traffic Service.

NOTE 1.—The Government of India reserve the right to reduce at their discretion, the period of training in the case of candidates who have had previous training or experience either in India or elsewhere.

NOTE 2.—Probationers will also have to undergo training at the Railway Staff College, Baroda, in two phases. The test in the Staff College is compulsory and a second chance in the event of failure, will not be given except in exceptional circumstances and provided the record of the Officer is such that such a relaxation may be made. Failure to pass the test may involve the termination of service and in any case the officers will not be confirmed till they pass the test, their period of training and/or probation being extended as necessary.

NOTE 3.—The programme of training given below have been drawn up chiefly for the purpose of guidance; they may be varied at the discretion of General Managers to suit particular cases provided that the total aggregate period of training is not ordinarily curtailed.

NOTE 4.—During the period of training, the probationer has to work as a Guard, Yard Master, Assistant Station Master, Station Master, Yard Foreman, Train Examiner, Assistant Loco Foreman, Assistant Controller, etc. as detailed below. After completion of training when the probationer is posted against a working post, his duties involve travelling with no facilities for camping at way-side stations. He has to visit sites of accidents at odd hours and inspect Control Offices and stations. The work is arduous and will involve night duties.

(1) Length of Course—Two years.

S. No.	Item	Period (Weeks)
1.	Lal Bahadur Shastri Academy of Administration, Mussoorie	17
2.	Railway Staff College, Baroda (First Phase)	12
3.	Area School to learn Guard's duties (Phase I)	4
4.	Working as Guard	3
5.	Booking/Parcel Office, Goods Shed and Transhipment Shed	10
6.	Traffic Accounts and Travelling Inspector of Accounts	5
7.	Area School to learn duties of Assistant Station Master (Phase II)	4
8.	Working as Yard Master, Assistant Station Master, Station Master, Yard Foreman and Train Examiner	13
9.	Working as Assistant Loco Foreman	1
10.	Assistant Controller	4
11.	Deputy Chief Controller, Power Controller	6
12.	Railway Staff College, Baroda, Phase-II	6
13.	Training on the Eastern Railway.	

(a) *Asansol Division*

- | | |
|---|-------|
| (i) Coal Pilot Working 1.5 weeks | } 2.5 |
| (ii) Working of Andal & Asansol Yards complex including Durgapur Steel Plant. | |

(b) *Dhanbad Division*

- | | |
|---|-----|
| (i) Coal allotment procedure including field trip to yards, such as PEH and Karanpura including washeries such as PEH and Dugda | } 2 |
| (ii) Working of coal Area Supdt's organisation. | |

- | | |
|--|---|
| (c) Mughalsarai Marshalling Yard including visits to Manduadih—Dehri-on-sona | 1 |
|--|---|

14. *Training on South Eastern Railway*

- | | |
|--|-----|
| (i) Chakradharpur Division Bondamunda Yard, Rourkela Steel Plant, including visit to Captive Mines | 1.5 |
|--|-----|

(ii) *Bilaspur Division*

- | | |
|---|-----|
| Bhilai Marshalling Yard, Bhilai Steel Plant and visit to Chirimiri and Manendracolliery areas | 1.5 |
|---|-----|

15. *Training in allotted Railways*

- | | | |
|---|------|-------|
| (a) Headquarters Office (Optg.) | 4.00 | } 8.0 |
| (b) Headquarters Office (Commercial) | 4.00 | |
| (c) Period set apart for journey time for taking up various items of training and inescapable leave | 2.5 | |

TOTAL	104.0
	Weeks
	or
	24 months

(2) Provided he passes the examination at the end of his two years training a probationer will be given charge of a working post on probation for a further year.

(3) Examination will be held as may be required at the close of courses as well as at intervals during the period of training.

NOTE.—Before a probationer is put to work independently as a Guard, Assistant Station Master, Station Master, Yard Foreman, Assistant Locomotive Foreman or Assistant Controller, he must be examined by a responsible officer of the administration in the respective duties for each of these posts and declared qualified.

14. *Delhi and Andaman & Nicobar Islands Police Service, Class II.*—(a) Appointments will be made on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority. Candidates appointed on probation will be required to undergo such training and pass such departmental tests as the Central Government may prescribe.

(b) If in the opinion of Government the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) The officer who has been declared to have satisfactorily completed his period of probation may be confirmed in the service. If his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) An officer belonging in the Service will be required to serve in Delhi or Andaman & Nicobar Islands under the Administration/Government of any of these territories. He may also be required to serve in any police/intelligence organisation of the Government of India.

(e) *Scales of pay :—*

Grade I (Selection Grade)—Rs. 1,000/- fixed.

Grade II—Time scale—Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800.

A person recruited on the result of competitive examination shall, on appointment to the Service, draw pay at the minimum of the time-scale, provided that if he held a permanent post, other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment to the Service, his pay during the period of his probation in the Service shall be regulated under the proviso of Fundamental Rule 22-B(1). The pay and increments in the case of other persons appointed to the Service shall be regulated in accordance with the Fundamental Rules.

(f) Officers of the Service are entitled to get dearness allowance at the Central Government rates applicable to employees drawing pay in revised Central scales of pay.

(g) In addition to dearness allowance officers of the Service are entitled to draw compensatory (city) allowance, house rent allowance and allowances to compensate for higher cost of living in hill stations, expensiveness incidental in remote localities etc. if they are posted at places, either for training or on duty, where such allowances are admissible.

(h) Officers of the Service are governed by the Delhi, and Andaman & Nicobar Islands Police Service Rules 1971, and such other regulations as may be made or instructions issued by the Central Government for the purpose of giving effect to those Rules. In regard to matter not specifically covered by the aforesaid Rules or by regulations or orders issued thereunder or by special orders they are governed by the rules, regulations and orders applicable to corresponding officers serving in connection with the affairs of the Union.

15. *The Central Secretariat Service Section Officers' Grade Class II—*

(a) The Central Secretariat Service has, at present the following grades :—

Grade	Scale of pay
Selection Grade—Deputy Secretary or equivalent	Rs. 1100—50—1,300—60—1600—100—1800
Grade I—Upper Secretary	Rs. 900—50—1250.
Section Officer's Grade	Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900.
Assistant's Grade	Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530.

Selection Grade and Grade I are controlled by the Cabinet Secretariat (Department of Personnel and Administrative Reforms) on an all-Secretariat basis. Section Officer/Assistant's Grades, however, are controlled by the Ministries.

Direct recruitment is made to the Section Officers' Grade and to the Assistants' Grade only.

(b) Direct recruit to the Section Officers' Grade will be on probation for 2 years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests will result in the discharge of the probationers from service.

(c) On the conclusion of his period of probation Government may confirm the officer in his appointment or if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) If the power to make appointment in the Service is delegated by Government to any officer, that officer may exercise any of the powers of Government described in the above clauses.

(e) Section Officers will normally be heads of 'Sections' while officers of Grade I will normally be in charge of Branches consisting of one or more sections.

(f) Section Officers will be eligible for promotion to Grade I in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(g) Officers of Grade I of the Central Secretariat Service will be eligible for appointment to the Selection Grade of the Service and to other higher administrative posts in the Central Secretariat.

(h) As regards leave, pension and other conditions of service officers of the Central Secretariat Service will be treated similarly to other Class I and Class II Officers.

16. Customs Appraisers' Service, Class II.

(a) Recruitment is made in the grade of appraiser in the scale of Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—830—35—900. Appointments are made on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority. During the period of probation the candidates will be required to undergo such training and pass such departmental tests as the Central Board of Excise & Customs may prescribe. They will not be allowed to draw pay above the stage of Rs. 375/- unless they pass the prescribed departmental Examination in full.

(b) If on the expiration of the period of probation or any extension thereof the appointing authority is of the opinion that the selected candidate is not fit for permanent employment or if at any time during such period of probation or extension thereof he is satisfied that the candidate will not be fit for permanent appointment on the expiration of such period of probation he may discharge him from the service or pass such orders as he thinks fit.

(c) On the successful completion of the period of probation and after passing of the departmental examination the officers will be considered for confirmation in the grade.

(d) Appraisers will be eligible for promotion to the next higher grade of Assistant Collector in the Indian Customs and Central Excise Service, Class I (Rs. 400/1,250) in accordance with the rules in force.

(e) Regarding leave and pension the officers will be treated like other Class II officers in Central Government department. As regards other terms and conditions of their service, they will be governed by the provisions in the Recruitment Rules for the Customs Appraisers' Service, Class II. These rules particularly provide that the members of the service will be liable to posting in any equivalent or higher posts under the Central Board of Excise and Customs anywhere in India.

17. Delhi and Andaman & Nicobar Islands, Civil Service, Class II—

(a) Appointments will be made on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority. Candidates appointed on probation will be required to undergo such training and pass such departmental tests as the Central Government may prescribe.

(b) If in the opinion of Government the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) The officer who has been declared to have satisfactorily completed his period of probation may be confirmed in the Service. If his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) An officer belonging to the Service will be required to serve in Delhi, or Andaman & Nicobar Islands under the Administration of any of these territories.

(e) Scales of pay :—

Grade I (Selection Grade)—Rs. 900—50—1,250.

Grade II—Time scale—Rs. 400—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900.

A person recruited on the results of competitive examination shall, on appointment to the Service, draw pay at the minimum of the time-scale, provided that if he held a permanent post, other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment to the Service, his pay during the period of his probation in the Service shall be regulated under the provisions of Fundamental Rule 22B(1). The pay and increments in the case of other persons appointed to the Service shall be regulated in accordance with the Fundamental Rules.

(f) Officers of the Service are entitled to get dearness allowance at the Central Government rates applicable to employees drawing pay in revised Central scales of pay.

(g) In addition to dearness allowance officers of the Service are entitled to draw compensatory (city) allowance, house rent allowance and allowances to compensate for higher cost of living in hill stations, expensiveness incidental in remote localities etc. If they are posted at place either for training or on duty where such allowances are admissible.

(h) Officers of the service are governed by the Delhi and Andaman & Nicobar Islands Civil Services Rules, 1971, and such other regulations as may be made or instructions issued by the Central Government for the purpose of giving effect to those rules. In regard to matters not specifically covered by the aforesaid Rules or by regulations or orders issued thereunder or by special orders, they are governed by the rules, regulations and orders applicable to corresponding officers serving in connection with the affairs of the Union.

18. The Indian Foreign Service, Branch 'B' Integrated Grades II and III of the General Cadre, Class II (Section Officers' Grade).

(a) 33-1/3% of the maintenance vacancies in the Integrated Grade II & III of the Indian Foreign Service, Branch 'B' (Class II) are filled by direct recruitment through the U.P.S.C. The scale of pay attached to this grade is Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900.

(b) Direct recruits to the Section Officers' Grade will be on probation for two years during which period they will be required to undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the prescribed tests may result in the discharge of probationers from service.

(c) On the conclusion of the period of probation, Government may confirm an officer in his appointment subject to availability of permanent posts or if his work and conduct have, in the opinion of Government, been unsatisfactory may either discharge him from the service, or may extend the period of his probation for such further period as Government may deem fit. The total period of probation will not exceed 3 years.

(d) If the power to make appointments in the service is delegated by Government to any officer, that officer may exercise any of the powers of Government prescribed in the above clauses.

(e) Officers appointed to this service will normally be Heads of Sections. While employed at the Headquarters of the Ministry of External Affairs/Ministry of Foreign Trade they will be designated as Section Officers and sometimes Administrative Officers. While serving in Indian Missions abroad, their designation will be Registrars, although for local purposes they may be called Attaches with diplomatic status.

(f) Section Officers will be eligible for promotion to Grade I of the General Cadre of the IFS(B) in the scale of Rs. 900—50—1,250 in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(g) Officers of the Grade I of the General Cadre of the IFS(B) will in turn be eligible for appointment to posts in the senior scale of IFS(A) in the scale of pay of Rs. 900 (6 years or under)—50—1000—60—1600—50—1800, in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(h) The Indian Foreign Service, Branch (B) is confined to the Ministry of External Affairs and Indian Mission abroad and the officers appointed to this service are not normally liable to transfer to other Ministries except the Ministry of Foreign Trade. They are, however, liable to serve anywhere inside or outside India.

(i) During service abroad, IFS(B) officers are granted foreign allowance in addition to their basic pay at rates which may be sanctioned from time to time, depending upon the cost of living etc. of the countries concerned. In addition, the following concessions are also admissible during service abroad, in accordance with the IFS (PLCA) Rules, 1961, as made applicable to I.F.S.(B) officers :—

- (i) Free furnished accommodation according to the scale prescribed by the Government.
- (ii) Medical Attendance Facilities under the Assisted Medical Attendance Scheme.
- (iii) Return air passages to India and back to the place of duty abroad up to a maximum of two throughout an officer's service for special emergencies such as the death or serious illness of an immediate relation in India as may be defined by the Government.
- (iv) Annual return air passage for children between the ages of 8 and 21 studying in India to visit their parents during vacation subject to certain conditions.
- (v) An allowance for the education of children up to a maximum of two children between the ages of 5 and 18 at rates prescribed by Government from time to time.
- (vi) Outfit allowance in connection with service abroad, in accordance with the prescribed rules and at rates fixed by Government from time to time. In addition to ordinary outfit allowance, special outfit allowance is admissible to officers posted in countries, where abnormally cold climatic conditions exist.
- (vii) Home leave passage for officers and their families in accordance with the prescribed rules.
- (j) The Revised Leave Rules, 1933, as amended from time to time, will apply to members of the service, subject to certain modifications. For service abroad, except in some neighbouring countries, officers are entitled to an additional credit of leave to the extent of 50 per cent of leave admissible under the Revised Leave Rules.

(k) While in India, officers are entitled to such concessions as are admissible to other Central Government servants of equal and similar status.

(l) Officers of the IFS(B) are governed by the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, as amended from time to time and by orders issued thereunder.

(m) Officers appointed to this service are governed by the Liberalised Pension Rules, 1950, as amended from time to time and by orders issued thereunder.

19. The Railway Board's Secretariat Service, Class II—

(a) The Railway Board Secretariat Service consists of the following :—

Service	Scale of pay
(i) Selection Grade Joint Director/Dy. Secretary.	Rs. 1100—50—1300— 60—1,600—100—1,800
(ii) Dy. Directors Grade . . .	Rs. 900—50—1,250 200 S.P. per month
(iii) Asstt. Director/Under Secretary	Rs. 900—50—1,250.
(iv) Section Officer . . .	Rs. 350—25—500— 30—590—EB—30— 800—EB—30—830— 35—900.
(v) Assistant . . .	Rs. 210—10—270— 15—300—EB—15— 450—EB—20—530.

Direct recruitment is made to the posts of Section Officers and Assistants.

(b) Officers recruited direct as Section Officers will be on probation for two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests will result in the discharge of the Probationer from Service.

(c) On the conclusion of his period of probation, the Government may confirm the officer in his appointment or if his work or conduct has, in the opinion of Government, been unsatisfactory, Government may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) If the power to make appointments in the service is delegated by Government to any officer that officer may exercise any of the powers of Government described in the above clauses.

(e) Section Officers will normally be heads of Sections while Assistant Director/Under Secretary will normally be in charge of branches consisted of one or more sections.

(f) Section officers will be eligible for promotion, as Assistant Director/Under Secretary in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(g) Assistant Director/Under Secretary will be eligible for appointment to higher posts of Deputy Director and Selection Grade in the Railway Board's Secretariat.

(h) The Railway Board's Secretariat Service is confined to the Ministry of Railways and the Staff are not liable to transfer to other Ministries as in the Central Secretariat Service.

(i) The staff employed in the Ministry of Railways are entitled to the privilege of passes and Privilege Ticket Orders on the same scale as admissible to Railway Officers.

(j) Officers including probationers of the Railway Board Secretariat Service recruited under these rules :—

(a) will be governed by the Railway Pension Rules; and

(b) Shall subscribe to the State Railway Provident Fund (non-contributory) under the Rules of that fund as amended from time to time.

(k) As regards leave and other conditions of service, officers of the Railway Board Secretariat Service will be treated similar to other Class I and II Officers on Railways but in the matter of Medical facilities they will be governed by the Rules applicable to other Central Government employees headquartered at New Delhi.

20. The Armed Forces Headquarters Civil Service Assistant Civilian Staff Officers Grade, Class II

(a) The Armed Forces Headquarters Civil Service, has at present, the following grades :—

Grade	Scale
(1) Joint Director (Class I) . . .	Rs. 1300—60—1600.
(2) Senior Civilian Staff Officer (Class I) . . .	Rs. 1100—50—1400.
(3) Civilian Staff Officer (Class I) . . .	Rs. 740—30—800—50— 1150.
(4) Assistant Civilian Staff Officer (Class II—Gazetted) . . .	Rs. 350—25—500—30— 590—EB—30—800.
(5) Assistant (Class II—Non-Gazetted) . . .	Rs. 210—10—270—15— 300—EB—15—450—EP— 20—530.

The above Service caters for the Armed Forces Headquarters and Inter Services Organisations of the Ministry of Defence.

Direct recruitment is made to the Assistant Civilian Staff Officers' Grade and to the Assistant Grade only.

(b) Direct recruits to the Assistant Civilian Staff Officers' Grade will be on probation for 2 years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests will result in the discharge of the probationers from service.

(c) On the conclusion of his period of probation, Government may confirm the officer in his appointment, or if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) If the power to make appointments in the Service is delegated by Government to any officer that officer may exercise any of the powers of Government described in the above clauses.

(e) In the Armed Forces Headquarters and Inter Services Organisations of the Ministry of Defence, Assistant Civilian Staff Officers will normally be heads of 'Sections' while Civilian Staff Officers will normally be incharge of one or more Sections.

(f) Assistant Civilian Staff Officers will be eligible for promotion to the Grade of Civilian Staff Officers in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(g) Civilian Staff Officers of the Armed Forces Headquarters Civil Service will be eligible for appointment to the Grade of Senior Civilian Staff Officers of the Service and to other administrative post in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(h) As regards leave, pension and other conditions of service, officers of the Armed Forces Headquarters Civil Service will be governed by the rules, regulations and orders in force from time to time in respect of civilians paid from the Defence Services Estimates.

21. Goa, Daman and Diu Civil Service, Class II

(a) Appointments will be made on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority. Candidates appointed on probation will be required to undergo such training and pass such departmental tests as the administrator of the Territory of Goa, Daman and Diu may prescribe.

(b) If in the opinion of the administrator the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, the administrator may discharge him forthwith.

(c) The officer who has been declared to have satisfactorily completed his period of probation may be confirmed in the service. If his work or conduct has in the opinion of the administrator been unsatisfactory, he may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as the administrator may think fit.

(d) An officer belonging to the Service will be required to serve at any place in the Union Territory of Goa, Daman and Diu.

(e) Scales of Pay—

Grade I (Selection Grade) Rs. 700—40—1100—50/2—1250.

Grade II—Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900.

A person recruited on the results of competitive examination shall, on appointment to the Service, draw pay at the minimum of the time-scale.

Provided that if he held a permanent post, other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment to the Service, his pay during the period of his probation in service shall be regulated under the provisions of sub-rule (1) of rule 22-B of the Fundamental Rules. The pay and increments in the case of other persons appointed to the Service shall be regulated in accordance with the Fundamental Rules.

Officers of the Service will be eligible for promotion to posts in the senior scale of the Indian Administrative Service in accordance with the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955.

(f) Officers of the Service are governed by Goa, Daman and Diu Civil Service Rules 1967, and such other regulations as may be made or instructions issued by the administrator for the purpose of giving effect to those rules.

22. Pondicherry Civil Service, Class II

(a) Appointments will be made on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority. Candidates appointed on probation will be required to undergo such training and pass such departmental tests as the administrator of the Union Territory of Pondicherry may prescribe.

(b) If in the opinion of the administrator the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, the administrator may discharge him forthwith.

(c) The officer who has been declared to have satisfactorily completed his period of probation may be confirmed in the service. If his work or conduct has in the opinion of the administrator been unsatisfactory, he may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as the administrator may think fit.

(d) An officer belonging to the Service will be required to serve at any place in the Union Territory of Pondicherry.

(e) Scale of pay—Rs. 375—25—800.

A person recruited on the results of competitive examination shall on appointment to the Service, draw pay at the minimum of the time-scale.

Provided that if he held a permanent post, other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment to the Service his pay during the period of his probation in Service shall be regulated under the provisions of sub-rule (1) of rule 22-B of the Fundamental Rules. The pay and increments in the case of other persons appointed to the Service shall be regulated in accordance with the Fundamental Rules.

Officers of the Service will be eligible for promotion to posts in the senior scale of the Indian Administrative Service in accordance with the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955.

(f) Officers of the Service are governed by Pondicherry Civil Service Rules, 1967, and such other regulations as may be made or instructions issued by the administrator for the purpose of giving effect to those rules.

APPENDIX IV

REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL EXAMINATION OF CANDIDATES

[These regulations are published for the convenience of candidates and in order to enable them to ascertain the probability of their coming up to the required physical standard. The regulations are also intended to provide guide lines to the medical examiners and a candidate who does not satisfy the minimum requirements prescribed in the regulations, cannot be declared fit by the medical examiners. However, while holding that a candidate is not fit according to the norms laid down in these regulations, it would be permissible for a Medical Board to recommend to the Government of India for reasons specifically recorded in writing that he may be admitted to service without disadvantage to Government.

2. It should, however, be clearly understood that the Government of India, reserve to themselves absolute discretion to reject or accept any candidate after considering the report of the Medical Board].

The classification of various Services under the two categories, namely "Technical" and "Non-technical" will be as under:—

A. Technical

(1) Indian Railway Traffic Service

(2) Indian Police Service and other Central Police Services Class II.

B. Non-Technical

I.A.S., IFS IA & AS Indian Customs Service, Indian Railway Accounts Service, Railway Board Secretariat Service Class II Indian Defence Accounts Service, Income Tax Officers (Class I), Indian Postal Service, Military Land and Cantonments Service Class I & II and other Central Civil Services Class I & II.

1. To be passed as fit for appointment a candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties of his appointment.

2. (a) In the matter of the correlation of age, height and chest girth of candidates of Indian (including Anglo-Indian) race it is left to the Medical Board to use whatever correlation figures are considered most suitable as a guide in the examination of the candidates. If there be any disproportion with regard to height weight and chest girth, the candidate should be hospitalised for the investigation and X-ray of the chest taken before the candidate is declared fit or not fit by the Board.

(b) however, for certain services the minimum standard for height and chest girth without which candidates cannot be accepted, are as follows:

	Height	Chest girth fully expanded	Expansion
1. Indian Railway Traffic Service	152cm 150cm	84 cm 79cm	5cm (For men) 5cm (For women)
2. Indian Police Service Delhi and Andaman & Nicobar Islands Police Service, Class II.	165cm 150cm	84cm 79cm	5cm (For men) 5cm (For women)

The minimum height prescribed is relaxable in case of candidates belonging to races such as Gorkhas, Garwalis, Assamese, Nagaland Tribals etc. whose average height is distinctly lower.

3. The candidate's height will be measured as follows:—

He will remove his shoes and be placed against the standard with his feet together and the weight thrown on the heels and not on the toes or other sides of the feet. He will stand erect without rigidity and with the heels, calves, buttocks and shoulders touching the standard, the chin will be depressed to bring the vertex of the head level under the horizontal bar and the height will be recorded in centimetres and parts of a centimetre to halves.

4. The candidate's chest will be measured as follows:—

He will be made to stand erect with his feet together, and to raise his arms over his head. The tape will be so adjusted round the chest that its upper edge touches the inferior angles of the shoulder blades behind and lies in the same horizontal plane when the tape is taken round the chest. The arms will then be lowered to hang loosely by the side and care will be taken that the shoulders are not thrown upwards or backwards so as to displace the tape. The candidate will then be directed to take a deep inspiration several times and the maximum expansion of the chest will be carefully noted and the minimum and maximum will then be recorded in centimetres 84—89 86—93.5 etc. In recording the measurements fractions of less than half centimetre should not be noted.

N.B.—The height and chest of the candidates should be measured twice before coming to a final decision.

5. The candidate will also be weighed and his weight recorded in kilograms fractions of half a kilogram should not be noted.

6. (a) The candidate's eye-sight will be tested in accordance with the following rules. The result of each test will be recorded.

(b) There shall be no limit for minimum naked eye vision but the naked eye vision of the candidates shall, however,

be recorded by the Medical Board or other medical authority in every case, as it will furnish the basic information in regard to the condition of the eye.

(c) The following standards are prescribed for distant and near vision with or without glasses for different types of Services.

Class of Service	Distant vision		Near vision	
	Better eye (Corrected vision)	Worse eye (Corrected vision)	Better eye (Corrected vision)	Worse eye (Corrected vision)
I.A.S., I.P.S., and Central Services Class I & II				
(i) Technical	6/6 or 6/9	6/12 6/9	J.I	J.II
(ii) Non-technical—				
(a) Services other than I.O.F.S., Class I	6/9	6/12	J.I	J.II
(b) I.O.F.S., Class I	6/6 or 6/9	6/18 6/9	J.I	J.II

(d) (i) In respect of the Technical Services mentioned above and any, other Services concerned with the safety of public the total amount of Myopia (including the cylinder) shall not exceed—4.00 D. Total amount of Hypermetropia (including the cylinder) shall not exceed + 4.00 D.

(ii) In every case of myopia, fundus examination should be carried out and the results recorded. In the event of pathological condition being present which is likely to be progressive and affect the efficiency of the candidate, he should be declared unfit.

(c) *Field of Vision*.—The field of vision shall be tested in respect of all services by the confrontation method. When such test gives unsatisfactory or doubtful results, the field of vision should be determined on the perimeter.

(f) *Night Blindness*.—Broadly there are two types of night blindness; (1) as a result of Vit. A deficiency and (2) as a result of Organic disease of Retina—a common cause being retinitis pigmentosa. In (1) the fundus is normal, generally seen in younger age group and ill nourished persons and improve by large doses of Vit. A in (2) the fundus is often involved and mere fundus examination will reveal the condition in majority of cases. The patient in this category is an adult and may not suffer from malnutrition. Persons seeking employment for higher posts in the Government will fall in this category. For both (1) and (2), dark adaptation test will reveal the condition. For (2) specially when fundus is not involved electro-retino-graphy is required to be done. Both these tests (dark adaptation and retinography) are time-consuming and require specialized set up and equipment; and thus are not possible as a routine test in a medical check up. Because of these technical considerations, it is for the Ministry/Department to indicate if these tests for night blindness are required to be done. This will depend upon the job requirement and nature of duties to be performed by the prospective Government employees.

(g) *Colour Vision*.—The testing of colour vision shall be essential in respect of the Technical Services mentioned above. As regards the non-Technical Services/posts, the Ministry/Department concerned will have to inform the Medical Board that the candidate is for a service requiring colour vision examination or not.

Colour perception should be graded into a higher and

lower grade depending upon the size of aperture in the lantern as described in the table below :—

Grade	Higher grade of colour perception	Lower grade of colour perception
1. Distant between the lamp and candidate	16'	16'
2. Size of aperture	1.3 mm	13 mm.
3. Time of exposure	5 seconds	5 seconds

For the Indian Railway Traffic Service and for other Services concerned with the safety of the public higher grade of colour vision is essential but for others lower grade of colour vision should be considered sufficient.

Satisfactory colour vision constitutes recognition with ease and without hesitation of signal red, signal green and white colours. The use of Ishihara's plates shown in good light and a suitable lantern like Edridge Green's shall be considered quite dependable for testing colour vision. While either of the two tests may ordinarily be considered sufficient in respect of the Services concerned with road, rail and air traffic, it is essential to carry out the lantern test. In doubtful cases where a candidate fails to qualify when tested by only one of the two tests, both the tests should be employed. However, both the Ishihara's plates and Edridge's Green lantern shall be used for testing colour vision of candidates for appointment to the Indian Railway Traffic Service.

(h) *Ocular condition other than visual acuity :—*

- (i) Any organic disease or a progressive refractive error, which is likely to result in lowering the visual acuity should be considered a disqualification.
- (ii) *Squint* : For technical services where the presence of binocular vision is essential, squint, even if the visual acuity in each eye is of the prescribed standard, should be considered a disqualification. For other services the presence of squint should not be considered as a disqualification if the visual acuity is of the prescribed standard.
- (iii) *One eye*.—If a person has one eye or if he has one eye which has normal vision and the other eye is amblyopic or has subnormal vision, the usual effect is that the person lacks stereoscopic vision for perception of depth. Such vision is not necessary for many civil posts. The medical board may recommend as fit, such persons provided the normal eye has—
 - (a) 6/6 distant vision and II near vision with or without glasses, provided the error in any meridian is not more than 4 diopters for distant vision.
 - (b) has full field of vision.
 - (c) normal colour vision wherever required.

Provided the board is satisfied that the candidate can perform all the functions for the particular job in question.

The above relaxed standards of visual acuity will NOT apply to candidates for posts/services classified as "TECHNICAL". The Ministry/Department concerned will have to inform the medical Board that the candidate is for a "TECHNICAL" post or not.

(i) *Contact Lenses*.—During the medical examination of a candidate the use of contact lenses is not to be allowed. It is necessary that when conducting eye test the illumination of the type letters for distant vision should have an illumination of 15 foot-candles.

7. *Blood Pressure*

The Board will use its discretion regarding Blood Pressure. A rough method of calculating normal maximum systolic pressure is as follows :—

- (i) With young subjects 15—25 years of age the average is about 100 plus age.
- (ii) With subjects over 25 year of age the general rule of 110 plus half the age seems quite satisfactory.

N.B.—As a general rule any systolic pressure over 140 mm and diastolic over 90 mm should be regarded as suspicious

and the candidate should be hospitalised by the Board before giving their final opinion regarding the candidate's fitness or otherwise. The hospitalization report should indicate whether the rise in blood pressure is of a transient nature due to excitement etc., or whether it is due to any organic disease. In all such cases X-ray and electrocardiographic examinations of heart and blood urea clearance test should also be done as a routine. The final decision as to the fitness or otherwise of a candidate will, however, rest with the medical board only.

Method of taking Blood Pressure

The mercury manometer type of instrument should be used as a rule. The measurement should not be taken within fifteen minutes of any exercise or excitement. Provided the Patient, and particularly his arm is relaxed, he may be either lying or sitting. The arm is supported comfortably at the patient's side in a more or less horizontal position. The arm should be freed from the clothes to the shoulder. The cuff completely deflated should be applied with the middle of the rubber over the inner side of the arm, and its lower edge an inch or two above the bend of the elbow. The following turns of cloth bandage should spread evenly over the bag to avoid bulging during inflation.

The brachial artery is located by palpitation at the bend of the elbow and the stethoscope is then applied lightly and centrally over it below, but not in contact with the cuff. The cuff is inflated to about 200 mm. Hg. and then slowly deflated. The level at which the column stands when soft successive sounds are heard represents the Systolic Pressure. When more air is allowed to escape the sounds will be heard to increase in intensity. The level at which the well-heard clear sounds change to soft muffled fading sounds represents the diastolic pressure. The measurements should be taken in a fairly brief period of time as prolonged pressure of the cuff is irritating to the patient and will vitiate the readings. Rechecking, if necessary, should be done only a few minutes after complete deflation of the cuff. (Sometimes, as the cuff is deflated sounds are heard at a certain level; they may disappear as the pressure falls and reappear at a still lower level. This 'Silent Gap' may cause error in reading.)

8. The urine (passed in the presence of the examiner) should be examined and the results recorded. Where a Medical Board finds sugar present in a candidate's urine by the usual chemical test the Board will proceed with the examination with all its other aspects and will also specially note any signs or symptoms suggestive of diabetes. If except for the glycosuria the Board finds the candidate conforms to the standard of medical fitness required they may pass the candidate "fit subject to the glycosuria being non-diabetic" and the Board will refer the case to a specified specialist in Medicine who has hospital and laboratory facilities at his disposal. The Medical Specialists will carry out whatever examinations clinical and laboratory he considers necessary including a standard blood sugar tolerance test, and will submit his opinion to the Medical Board, upon which the Medical Board will base its final opinion "fit or unfit". The candidate will not be required to appear in person before the Board on the second occasion. To exclude the effects of medication it may be necessary to retain a candidate for several days in hospital under strict supervision.

9. A woman candidate who as a result of tests is found to be pregnant of 12 weeks standing or over, should be declared temporarily unfit until the confinement is over. She should be re-examined for a fitness certificate six weeks after the date of confinement, subject to the production of a medical certificate of fitness from a registered medical practitioner.

10. The following additional points should be observed :—

(a) that the candidate's hearing in each ear is good and that there is no sign of disease of the ear. In case it is defective the candidate should be got examined by the ear specialist, provided that if the defect in hearing is remediable by operation or by use of a hearing aid, a candidate cannot be declared unfit on that account provided he/she has no progressive disease in the ear. This provision is not applicable in the case of Railway Services. The following

ing are the guidelines for the medical examining authority in this regard :—

- (1) Marked, or total deafness in one ear, other ear being normal. Fit for non-technical jobs if the deafness is upto 30 decibel in higher frequency.
- (2) Perceptive deafness in both ears in which some improvement is possible by a hearing aid. Fit in respect of both technical and non-technical jobs if the deafness is upto 30 Decibel in speech frequencies of 1000 to 4000.
- (3) Perforation of tympanic membrane of Central or marginal type.
 - (i) One ear normal other ear perforation of tympanic membrane present—Temporarily unfit.
Under improved conditions of Ear Surgery a candidate with marginal or other perforation in both ears should be given a chance by declaring him temporarily unfit and then he may be considered under 4(ii) below.
 - (ii) Marginal or attic perforation on both ears—Unfit.
 - (iii) Central perforation both ears—Temporarily unfit.
- (4) Ears with mastoid cavity subnormal hearing on one side/on both sides.
 - (i) Either ear normal hearing other ear Mastoid cavity—Fit for both technical and non-technical jobs.
 - (ii) Mastoid cavity of both sides. Unfit for technical job. Fit for nontechnical jobs, if hearing improve to 30 decibels in either ear with or without hearing aid.
- (5) Persistently discharging ear-operated/unoperated. Temporarily Unfit for both technical and non-technical jobs.
- (6) Chronic inflammatory/allergic conditions of nose with or without bony deformities of nasal septum.
 - (i) A decision will be taken as per circumstances of individual cases.
 - (ii) If deviated nasal Septum is present with symptoms—Temporarily unfit.
- (7) Chronic inflammatory conditions of tonsils and/or larynx.
 - (i) Chronic inflammatory conditions of tonsils and/or Larynx—Fit.
 - (ii) Hoarseness of voice of sever degree if present then—Temporarily unfit.
- (8) Benign or locally malignant tumours of the E.N.T.
 - (i) Benign tumours—Temporarily unfit.
 - (ii) Malignant Tumours—Unfit.

- (9) Otosclerosis If the hearing is within 30 Decibels after operation or with the help of hearing aid—Fit.
- (10) Congenital defects of ear, nose or throat;
 - (i) if not interfering with functions—Fit.
 - (ii) Stuttering of severe degree—Unfit.
- (11) Nasal Poly Temporarily Unfit.
 - (b) that his speech is without impediment;
 - (c) that his teeth, are in good order and that he is provided with dentures where necessary for effective mastication (well filled teeth will be considered as sound);
 - (d) that the chest is well formed and his chest expansion sufficient; and that his heart and lungs are sound;
 - (e) that there is no evidence of any abdominal disease;
 - (f) that he is not ruptured;
 - (g) that he does not suffer from hydrocele, a severe degree of varicocoele, varicose veins or piles;
 - (h) that his limbs, hands and feet are well formed and developed and that there is free and perfect motion of all his joints;
 - (i) that he does not suffer from any inveterate skin disease;
 - (j) that there is no congenital malformation or defect;
 - (k) that he does not bear traces of acute or chronic disease pointing to an impaired constitution;
 - (l) that he bears marks of efficient vaccination; and
 - (m) that he is free from communicable disease.

11. Radiographic examination of the chest should be done as a routine in all cases for detecting any abnormality of the heart and lungs, which may not be apparent by ordinary physical examination.

When any defect is found it must be noted in the certificate and the medical examiner should state his opinion whether or not it is likely to interfere with the efficient performance of the duties which will be required of the candidate.

12. The candidates filing an appeal against the decision of the Medical Board have to deposit an appeal fee of Rs. 50/- in such manner as may be prescribed by the Government of India in this behalf. This fee would be refunded if the candidate is declared fit by the Appellate Medical Board. The candidates may, if they like, enclose medical certificate in support of their claim of being fit. Appeals should be submitted within 21 days of the date of the communication in which the decision of the Medical Board is communicated to the candidates; otherwise, request for second medical examination by an Appellate Medical Board will not be entertained. The Medical examination by the Appellate Medical Boards would be arranged at New Delhi only and no travelling allowance or daily allowance will be admissible for the journeys performed in connection with the medical examination. Necessary action to arrange medical examination by Appellate Medical Boards would be taken by the Cabinet Secretariat (Department of Personnel) on receipt of appeals accompanied by the prescribed fee.

Medical Board's Report

The following intimation is made for the guidance of the Medical Examiner :—

1. The standard of physical fitness to be adopted should make due allowance for the age and length of service, if any, of the candidate concerned.

No person will be deemed qualified for admission to the Public Service who shall not satisfy Government, or the appointing authority, as the case may be, that he has no disease, constitutional affection, or bodily infirmity unfitting him, or likely to unfit him for that service.

It should be understood that the question of fitness involves the future as well as the present and that one of the main objects of medical examination is to secure continuous effective service, and in the case of candidates for permanent appointment to prevent early pension or payments in case of premature death. It is at the same time to be noted that the question is one of the likelihood of continuous effective service, and that rejection of a candidate need not be advised on account of the presence of a defect which in only a small proportion of cases is found to interfere with continuous effective service.

A lady doctor will be co-opted as a member of the Medical Board whenever a woman candidate is to be examined.

Candidates appointed to the Indian Defence Accounts Service are liable for field service in or out of India. In the case of such a candidate, the Medical Board should specially record their opinion as to his fitness or otherwise for field service.

The report of the Medical Board should be treated as confidential.

In case where a candidate is declared unfit for appointment in the Government Service the grounds for rejection may be communicated to the candidate in broad terms without giving minute details regarding the defects pointed out by the Medical Board.

In cases where a Medical Board considers that a minor disability disqualifying a candidate for Government service can be cured by treatment (medical or surgical) a statement to that effect should be recorded by the Medical Board. There is no objection to a candidate being informed of the Board's opinion to this effect by the appointing authority and when a cure has been effected it will be open to the authority concerned to ask for another Medical Board.

In the case of candidates who are to be declared "Temporarily Unfit" the period specified for re-examination should not ordinarily exceed six months at the maximum. On re-examination after the specified period these candidates should not be declared temporarily unfit for a further period but a final decision in regard to their fitness for appointment or otherwise should be given.

(a) Candidate's statement and declaration.

The candidate must make the statement required below prior to his Medical Examination and must sign the Declaration appended thereto. His attention is specially directed to the warning contained in the Note below:—

1. State your name in full (in block letters)
2. State your age and birth place
2. (a) Do you belong to races such as Gorkhas, Garwalis, Assamese, Nagaland Tribals etc. whose average height is distinctly lower? Answer 'Yes' or 'No' and if the answer is 'Yes', state the name of the race.
3. (a) Have you ever had small-pox, intermittent or any other fever, enlargement or sup-puration of glands, spitting of blood, asthma, heart disease, lung disease, fainting attack, rheumatism, appendicitis?

Or

- (b) any other disease or accident requiring confinement to bed and medical or surgical treatment?
4. When were you last vaccinated?
5. Have you suffered from any form of nervousness due to over work

or any other cause?

6. Furnish the following particulars concerning your family:—

Father's age if living and state of health	Father's age at death and cause of death	No. of brothers living, their ages and state of health	No. of brothers, dead, their ages at and cause of death
--	--	--	---

Mother's age if living and state of health	Mother's age at death and cause of death	No. of sisters living, their ages and state of health	No. of sisters, dead, their ages, at and cause of death
--	--	---	---

7. Have you been examined by a Medical Board before?
 8. If answer to the above is Yes, please state what Service/Services you were examined for?
 9. Who was the examining authority?
 10. When and where was the Medical Board held?
 11. Result of the Medical Board's examination, if communicated to you or if known
- I declare all the above answers to be, to the best of my belief, true and correct.

Candidate's signature

Signed in my presence.

Signature of the Chairman of the Board.

NOTE.—The candidate will be held responsible for the accuracy of the above statement. By wilfully suppressing any information he will incur the risk of losing the appointment and, if appointed, of forfeiting all claims to Superannuation allowance or Gratuity.

(b) Report of Medical Board on (name of candidate) physical examination :

1. General development : Good.....Fair.....
Poor.....
Nutrition Thin.....Average.....Obese.....
Height (Without shoes).....Weight.....
Best Weight.....when.....any recent change in weight?.....Temperature.....

Girth of Chest.

(1) (After full inspiration)

(2) (After full expiration)

2. Skin : Any obvious disease.....

3. Eyes :

(1) Any disease.....

(2) Night blindness.....

(3) Defect in colour vision.....

(4) Field of vision.....

(5) Visual acuity.....

(6) Fundus examination.....

Acuity of vision Naked With Strength of glass
eye glasses sph. Cyl. Axis.

Distant vision	R.E.
	L.E.
Near vision	R.E.
	L.E.
Hypermetropia	R.E.
Manifest	L.E.

4. Ears : Inspection.....Hearing : Right Ear....
Left Ear
5. GlandsThyroid
6. Condition of teeth
7. Respiratory System : Does physical examination reveal anything abnormal in the respiratory organs?.....
If yes, explain fully
8. Circulatory System :
(a) Heart : Any organic lesions ?Rate
Standing
After hopping 25 times
2 minutes after hopping.....
(b) Blood Pressure : SystolicDiastolic
9. Abdomen : GirthTenderness.....
Hernia
- (a) Palpable : LiverSpleen
KidneysTumours
- (b) HemorrhoidsFistula
10. Nervous System : Indication of nervous or mental disabilities.....
11. Loco-Motor System : Any abnormality
12. Genito Urinary System : Any evidence of Hydrocele, Varicocele etc.
Urine Analysis :
(a) Physical appearance
(b) Sp. Gr.
(c) Albumen
(d) Sugar
(e) Casts
(f) Cells
13. Report of X-Ray Examination of Chest.
14. Is there anything in the health of the candidate likely to render him unfit for the efficient discharge of his duties in the service for which he is a candidate?

NOTE.—In the case of a female candidate, if it is found that she is pregnant of 12 weeks standing or over, she should be declared temporarily unfit, vide regulation 9 of the Regulations.

15. (i) State the Services for which the candidate has been examined :—
(a) IAS & IFS
(b) IPS, Delhi and Andaman & Nicobar Islands Police, Service
(c) Central Services, Class I & II
(ii) Has he been found qualified in all respect for the efficient and continuous discharge of his duties in :—
(a) IAS & IFS
(b) IPS, Delhi and Andaman & Nicobar Islands Police Service (see especially height, chest girth eye sight, colour blindness and locomotive system)
(c) Indian Railway Traffic Service, (see especially height, chest, eye sight, colour blindness).
(d) Other Central Services Class I/II.
(iii) Is the candidate fit for FIELD SERVICE

NOTE :—The Board should record their findings under one of the following three categories.

- (i) Fit
(ii) Unfit on account of
(iii) Temporarily unfit on account of

Place

Date

Chairman
Member
Member

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 3rd May 1973

No. 51/1/73-ANL(i).—The President is pleased to nominate the following non-official members to the Advisory Committee for the Union territory of Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands, associated with the Minister of Home Affairs, for the period from the 1st April, 1973, to the 31st March, 1974 :—

1. Shri K. Nallakoya of Androth.
2. Shri Baduveganduvar Ali Manikfan of Minicoy.
3. Shri Pattakkal Pookoya of Amini.
4. Shri Kathiyathoda Ahammed of Kavaratti.
5. Shri N. Koya of Kilian.

No. 51/1/73-ANL(ii).—The President is pleased to nominate the following non-official members to the Advisory Council associated with Administrator, Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands, for the period from the 1st April, 1973, to the 31st March, 1974 :—

1. Shri P. Hamza Koya of Kalpeni.
2. Shri M. Sayed Ali of Kadmat.
3. Shri C. Muthukoya of Chetlat.
4. Shri Cheriyaibiyathiyoda Syed Buhari of Bitra.
5. Shri Athenchetta Achapada Kasmi of Agatti.
6. Smt. Puthiya Edayakkal Kadeejabi of Amini.
7. Kumari T. P. Pathumabi of Kalpeni.

G. K. BHANOT, Jt. Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(Bureau of Public Enterprises)

RESOLUTION

New Delhi, the 30th April 1973

No. F.6(23)-Coord./73.—The Government of India have decided that the term of the Action Committee appointed under the Ministry of Finance (Bureau of Public Enterprises) Resolution No. F.6(90)-Coord./71, dated the 31st December, 1971, should be extended upto 31st December, 1973.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India, Part I, Section 1.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of Government of India, Public Sector Undertakings, State Governments/Administrations of Union Territories and all other concerned.

P. C. BHATTACHARYYA, Addl. Secy.

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 11th May 1973

No. 4(1)/73-EPZ.—The Central Government hereby appoints Shri H. N. Ray, Secretary (Expenditure), Ministry of Finance, as a member of the Santa Cruz Export Processing Zone Authority vice Shri M. R. Yardi and makes the following further amendment in the Government of India, Ministry of Commerce Notification No. 4(1)/73-EPZ, dated the 15th February, 1973, namely :—

In the said notification for the entry against serial number (iv), the following entry shall be substituted, namely :—

“(iv) Shri H. N. Ray,

Secretary (Expenditure),
Ministry of Finance.”

N. S. VAIDYANATHAN, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY

RESOLUTION

New Delhi, the 14th May 1973.

No. DST/8(1)/72-JRC.—In continuation of this Department's Resolution No. DST/8/1/72-JRC, dated the 11th December, 1972, it has been further decided by the Government of India to extend the tenure of the Joint Reviewing Committee, set up to review the organisational and procedural set up of the Botanical Survey of India and Zoological Survey of India, upto 31st August, 1973 for the submission of its final report.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be forwarded to the Chairman and all the Members of the Joint Reviewing Committee, the Prime Minister's Secretariat and all Ministries.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for General Information.

A. RAMACHANDRAN, Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

RESOLUTION

New Delhi the 5th May 1973

No. E(RB)/73/21/40.—In supersession of Resolution No. ERBI-70/21/86/ Pt., dated 1-2-73, the Government of India have decided to revive and reconstitute the Non-official Standing Voluntary Help Committee, with immediate effect.

Shri M. Govinda Reddy will be the Chairman of the reconstituted committee and Shri Kameshwar Prasad Singh will be its Member Secretary. The names of members of the committee will be notified later.

2. The committee will concentrate on checking ticketless travel and thefts and pilferages on railways.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

H. F. PINTO, Secy., Rly. Board
& ex-officio It. Secy.